असंशोधित

बिहार विधान-सभा वादवृत्त

सरकारी प्रतिवेदन

09 मार्च, 2021

सप्तदश विधान सभा — मंगलवार, तिथि 09 मार्च, 2021 (ई०)

द्वितीय सत्र — 18 फाल्गुन, 1942(शक)

(कार्यवाही प्रारम्भ होने का समय - 11.00 बजे पूर्वाह्न)

(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

अध्यक्ष: सभा की कार्यवाही प्रारंभ की जाती है । अब प्रश्नोत्तर काल होगा । अल्पसूचित प्रश्न लिये जाएंगे ।

श्री अरूण सिंह: महोदय, दो आदमियों को गोली लगी है । कल सकरा बाजार में अपराधियों ने दो आदमियों को गोली मार दी जिससे एक आदमी की मृत्यु हो गयी और एक आदमी जीवन और मृत्यु से जूझ रहा है । महोदय, मैं मांग करता हूं कि सरकार इसको संज्ञान में ले और अपराधियों पर कार्रवाई करे और वहां उपस्थित जो थाना प्रभारी हैं उनपर कार्रवाई की जाय ।

श्री अजय कुमार: महोदय, एक सूचना है, खगड़िया जिला के देवधा मंदिर में नल-जल योजना में काम करते हुए पांच मजदूरों की मौत हो गयी हमलोगों का दिमाग हिल गया है, इसलिए मैं मांग करता हूं...

अध्यक्ष: वह संज्ञान में आ गया है ।

श्री अजीत शर्मा: महोदय, मृत डॉक्टर की सिविल सर्जन के पद पर पोस्टिंग की गई है इस पर संज्ञान लेकर स्वास्थ्य विभाग पर आपको कार्रवाई करनी चाहिए ।

अध्यक्ष: श्री पवन कुमार जायसवाल ।

प्रश्नोत्तर काल

अल्पसूचित प्रश्न संख्या-'क'-16(श्री पवन कुमार जायसवाल, क्षेत्र संख्या-21 ढाका)

श्री नीरज कुमार सिंह, मंत्री: महोदय, समय चाहिए ।

श्री पवन कुमार जायसवाल: अध्यक्ष महोदय, ये प्रश्न 26 तारीख को विभाग में हस्तांतरित हुआ था । आपदा विभाग से मंत्री जी का कहना है कि कल शाम को उनको मिला है । मेरा यह प्रश्न है कि इतने बड़े सदन का यह विषय है अगर हस्तांतरण 14 दिन में आपदा विभाग ने वन विभाग को नहीं किया, तो इस मामले में जो दोषी अधिकारी हैं माननीय अध्यक्ष जी, क्या उनके ऊपर कार्रवाई होगी ?

श्री नीरज कुमार सिंह, मंत्री: महोदय, कल शाम को ही आया है और हम भी चाहते हैं कि जो महोदय का सवाल है यह पूरा हो । हम लोग इस पर कोशिश करेंगे ।

श्री पवन कुमार जायसवाल: इसमें 14 दिन लग गये ।

अध्यक्ष: अगली तिथि को इसका.....

श्री संजय सरावगी: अध्यक्ष महोदय, मेरा यह कहना है कि यह बहुत महत्वपूर्ण मामला है और आगे एक ही दिन बचा हुआ है, तो माननीय मंत्री इसको कल पर रख कर जवाब दें, इसमें दिक्कत क्या है ? कल पर इसको रख दिया जाय अध्यक्ष महोदय, हां पंद्रह-पंद्रह दिन हो गये, अध्यक्ष महोदय, उत्तर तैयार नहीं है, विभाग ने हस्तांतरण नहीं किया, इसको कल पर रख दिया जाय ।

अध्यक्ष: जिस दिन इस विभाग का प्रश्न रहेगा उसी दिन आयेगा, अगली तिथि में ।

श्री ललित कुमार यादव: अध्यक्ष महोदय, यह पहले भी उपमुख्यमंत्री जब सुशील कुमार मोदी थे उनका स्पष्ट बयान था, सर्पदंश से मृत्यु के बाद उनको मुआवजा मिलेगा महोदय, तो फिर सरकार का दोबारा उत्तर और समय पर समय, महोदय यह स्पष्ट करने की जरूरत थी । सर्पदंश से वन क्षेत्र से बाहर व्यक्ति की मृत्यु पर मुआवजा मिलेगा कि नहीं मिलेगा महोदय, यह एक लाइन का जवाब है महोदय, सरकार क्यों इसको बार-बार टालना चाहती है । महोदय, यह अल्पसूचित प्रश्न है...

अध्यक्ष: स्पष्ट जवाब देने के लिए ही वह समय ले रहे हैं, 16 तारीख को इनकी अगली तिथि पड़ती है । आप उस दिन पूरी तैयारी करके गंभीरता के साथ आएंगे ।

श्री ललित कुमार यादव: महोदय, यह गरीब से संबंधित है । गरीब लोगों में अधिकांश लोगों की सर्पदंश से मृत्यु होती है । महोदय, और यह स्थगित प्रश्न है...

अध्यक्ष: अगली तिथि को कह दिये । बैठ जाइये, बैठ जाइये ।

श्री संजय सरावगी: 14 तारीख को सकारात्मक उत्तर होगा ।

अध्यक्ष: सकारात्मक उत्तर की संभावना है । श्री विजय कुमार सिंह उर्फ डब्लू सिंह ।

<u>अल्पसूचित प्रश्न संख्या-40 (श्री विजय कुमार सिंह उर्फ डब्लू सिंह, क्षेत्र संख्या-221, नवीनगर)</u>

(लिखित उत्तर)

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री: महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि राज्य में +2 स्तर की शिक्षा 3926 उच्च माध्यमिक विद्यालयों में दी जा रही है । इसमें नामांकित छात्र/छात्राओं की कुल संख्या 10,59,115 (दस लाख उनसठ हजार एक सौ पन्द्रह) है ।

+2 स्तर के कार्यरत शिक्षकों की कुल संख्या 11467 (ग्यारह हजार चार सौ सढ़सठ) है, जिनमें पंचायतीराज संस्था एवं नगर निकाय संस्था अन्तर्गत कार्यरत शिक्षकों की संख्या 11221 (ग्यारह हजार दो सौ इक्कीस) है । इसके साथ-साथ 4050 (चार हजार पचास) अतिथि शिक्षकों की सेवा भी संबंधित विद्यालयों में +2 स्तर की कक्षाओं के लिए ली जा रही हैं ।

पंचायतीराज संस्था एवं नगर निकाय संस्था अन्तर्गत छठे चरण के नियोजन की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है, जिसमें +2 स्तर के कुल 18101 (अठारह हजार एक सौ एक) रिक्त पद विज्ञापित हैं ।

अध्यक्षः उत्तर संलग्न है, पूरक पूछिये ।

श्री विजय कुमार सिंह उर्फ डब्लू सिंहः माननीय अध्यक्ष महोदय, जवाब में यह कहा गया है कि 18,101 शिक्षकों की अभी नियुक्ति का विज्ञापन निकाला हुआ है लेकिन अभी तक इसमें क्या हुआ है, क्योंकि हाईस्कूल में शिक्षकों का घोर अभाव है...

अध्यक्षः पूरक पूछिये ।

श्री विजय कुमार सिंह उर्फ डब्लू सिंहः यह कब तक कर देंगे ?

अध्यक्षः माननीय मंत्री, शिक्षा विभाग ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्रीः आपने क्या कहा डब्लू जी ?

अध्यक्षः कब तक कर देंगे ?

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्रीः महोदय, हम समझते हैं कि पूरा सदन अवगत है और कई प्रश्नों के क्रम में बताया जा चुका है कि हमने तो इसमें नियुक्ति का विज्ञापन 2019 में ही कर दिया है और माननीय उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश के कारण यह रुका हुआ था और उसमें हमलोग आई0ए0 फाइल करके उसको शीघ्र कराने जा रहे हैं, महोदय ।

अध्यक्षः श्री ललित कुमार यादव ।

अल्पसूचित प्रश्न संख्या-41(श्री ललित कुमार यादव, क्षेत्र संख्या-82 दरभंगा ग्रामीण)

(लिखित उत्तर)

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्रीः महोदय, 1. महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि राज्य में कुल 270 अंगीभूत/राजकीय महाविद्यालय हैं, जिनमें से 90 अंगीभूत/राजकीय महाविद्यालय नैक से मान्यता प्राप्त हैं । इस प्रकार 33 प्रतिशत अंगीभूत/राजकीय महाविद्यालय नैक से मान्यता प्राप्त हैं ।

राज्य के 16 विश्वविद्यालयों में से संप्रति 13 विश्वविद्यालय ही नैक से मान्यता हेतु पात्र हैं, जिसमें से 04 नैक से मान्यता प्राप्त हैं । इस प्रकार 30 प्रतिशत विश्वविद्यालय नैक से मान्यता प्राप्त हैं ।

राज्य में कुल 235 संबद्धता प्राप्त महाविद्यालयों में से 08 (3.4 प्रतिशत) नैक से मान्यता प्राप्त हैं ।

वर्तमान में केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान के तहत विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों की आधारभूत सुविधाओं के उन्नयन हेतु राशि स्वीकृत की जाती है । वर्तमान में नैक से 2.5 अंक प्राप्त करने वाले संस्थान ही राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान के तहत अनुदान प्राप्त करने के पात्र हैं । राशि स्वीकृति हेतु केंद्र सरकार द्वारा समय-समय पर मानक परिवर्तित किये जाते हैं ।

2. उत्तर अस्वीकारात्मक है । नैक से मान्यता प्राप्त नहीं होने के कारण छात्रों के पलायन किये जाने की सूचना नहीं है ।

अध्यक्ष: आपका उत्तर मुद्रित है । आप पूरक पूछिये ।

श्री ललित कुमार यादव: महोदय, उत्तर मुद्रित है । मैं माननीय मंत्री, सरकार से यह जानना चाहता हूं कि सरकार के पास कोई ब्लू प्रिंट है, जिससे तय समय-सीमा के अंदर सभी विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालयों में नैक के मानक के अनुरूप हो जायेगा ?

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री: महोदय, उत्तर में यह बात बताई गई है कि नैक से मान्यता प्राप्त करने की कार्रवाई अलग-अलग महाविद्यालयों के द्वारा की जाती है । आवश्यक आधारभूत संरचनाओं से लेकर उसके जो भी पैरामीटर्स हैं, जो भी उनके मापदंड हैं या मानक हैं उसके आधार पर महाविद्यालय अपनी परिसंपत्तियों की या अपने यहां उपलब्ध सुविधाओं के आधार पर वह नैक के लिए विश्वविद्यालयों के माध्यम से कार्रवाई करते हैं और फिर उसमें समय-समय पर सरकार भी आवश्यक सहयोग देती है और हम समझते हैं कि जहां तक इन्होंने बताया है और हमने कहा है कि लगभग 30 से 31 प्रतिशत विश्वविद्यालय भी हमारे नैक से मान्यता प्राप्त हैं । इसी तरीके से जितने कांस्टीटुएंट कॉलेज हैं, अंगीभूत राजकीय महाविद्यालय हैं उनमें से भी लगभग 33 प्रतिशत महाविद्यालय नैक से मान्यता प्राप्त हैं । माननीय सदस्य का प्रश्न या चिंता वाजिब है कि यह 33 या 30 परसेंट से हम संतुष्ट नहीं हैं, यह बिल्कुल ही असंतोषजनक है । हम इसमें सुधार करने की लगातार चेष्टा, लगातार प्रयास कर रहे हैं और जैसा कि हमने बताया कि अलग-अलग महाविद्यालयों के द्वारा ही इस संबंध में पहल की आवश्यकता होती है । हमने निदेश दिया है विश्वविद्यालयों को भी और महाविद्यालयों को भी कि वह आवश्यक सुविधाओं का प्रबंध अपने संस्थानों में करके नैक प्राप्ति के लिए आगे बढ़ें, सरकार भी आवश्यक सहयोग देती है ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष: अभी जिनका सवाल है उनको तो पूछने दीजिये, बैठिये ।

श्री ललित कुमार यादव: अध्यक्ष महोदय, मैंने स्पष्ट कहा है कि नैक के मानक अनुरूप सरकार का कोई ब्लू प्रिंट है ? सरकार 30 प्रतिशत अपना लक्ष्य अभीतक का जो बताया है तो 16 साल से यह सरकार चल रही है, महोदय और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा यदि राज्य में नहीं होगी और छात्र पलायन कर रहे हैं, दूसरे राज्य में जा रहे हैं, तो यू0जी0सी0 से भी ग्रांट नहीं मिल रहा है, महोदय तो सरकार को 15-16 साल हो गये और 30 साल में 100 प्रतिशत ये मानक नैक के अनुसार उपलब्ध करा लेंगे, यही बता दें कि इसमें कितना समय लगेगा ?

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्रीः फिर महोदय प्रश्न पूरक वहीं के वहीं रह जाता है । इसलिए हमने कहा है...

श्री ललित कुमार यादवः आपका जवाब वहीं रह गया पूरक का ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्रीः सवाल जहां रहेगा जवाब वहीं रहेगा न । जवाब तो सवाल का होता है, जवाब सवाल से इधर-उधर तो नहीं भटकेगा, इसलिए सवाल जहां है जवाब वहीं रहेगा...

श्री ललित कुमार यादवः आप यही बता दीजिये कि आपने 70 प्रतिशत अपने जवाब में स्वीकार किया है कि नैक के मानक अनुरूप नहीं है तो कब तक आपका लक्ष्य है हम तो वही कह रहे हैं ब्लूप्रिंट क्या है ? 16 साल आपको हो गये 30 साल और होंगे 30 और 70 आप 100 प्रतिशत पर आ जायेंगे ।

अध्यक्षः बैठ जाइये, माननीय मंत्रीजी को बोलने दीजिये ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्रीः महोदय, हमने बताया है कि इस दिशा में पहल संबंधित महाविद्यालयों के द्वारा विश्वविद्यालय के माध्यम से की जाती है सरकार उसमें सहयोग देती है और इसी क्रम में यह अब 30-33 प्रतिशत तक पहुंचा है जो खुद सरकार की तरफ से हमने स्वीकारा है कि यह स्थिति संतोषजनक नहीं है हम इसमें आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं । इसके अलावे अगर नैक एक्रेडिटेशन पाने के लिये माननीय सदस्य भी कुछ सुझाव देंगे तो हम उसको सम्मिलित करेंगे ।

श्री ललित कुमार यादवः महोदय, ये सरकार से बाहर हो जायं हमलोगों को सरकार में आने दें, हम 100 प्रतिशत इनको करके दिखा देंगे, यही सुझाव है ।

(व्यवधान)

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्रीः अब महोदय, अब देखिये कि इन्होंने पूरक को कहां शिक्षा विभाग और सरकारी बात से अलग करके राजनीतिक बात पर पहुंचा दिया । अब ऐसा पूरक पूछियेगा तो जवाब भी तो उसी तरह का हो जायेगा कि ये 30 प्रतिशत भी जो है इसी 15 साल में हुआ है उसके पहले 15 साल में कुछ नहीं है ।

अध्यक्षः माननीय सदस्य ।

श्री अवध विहारी चौधरीः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि नैक में क्वालिफाई कर जाने के बाद इस राज्य के कितने ऐसे कॉलेज हैं, जिसमें से यू0जी0सी0 के द्वारा उन्हें सहायता प्रदान की जा रही है ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्रीः महोदय, लगता है कि हमारे वरीय सदस्य श्री अवध विहारी चौधरी जी ने प्रश्न का मूल उत्तर नहीं देखा है । उसमें हमने इन सारी चीजों का जिक्र किया है । अगर आसन इजाजत देगा तो हम फिर से पढ़ देंगे ।

अध्यक्षः पढ़ दीजिये ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्रीः महोदय इस संबंध में वस्तुस्थिति यह है कि राज्य में कुल 270 अंगीभूत या राजकीय महाविद्यालय हैं, जिनमें से 90 अंगीभूत या राजकीय महाविद्यालय नैक से मान्यता प्राप्त हैं ।

...क्रमशः...

टर्न-2/सत्येन्द्र/09-03-21

...क्रमशः...

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्रीः महोदय, 270 में 90 इसीलिए हमने कहा था 30 प्रतिशत, इसी प्रकार 33 प्रतिशत अंगीभूत राजकीय महाविद्यालय, ये नैक से मान्यता प्राप्त हैं । राज्य के 16 विश्वविद्यालयों में से सम्प्रति 13 विश्वविद्यालय ही नैक से मान्यता हेतु पात्र हैं जिनमें से 4 को नैक की मान्यता प्राप्त है । इस प्रकार 30 प्रतिशत विश्वविद्यालय नैक से मान्यता प्राप्त हैं । वर्तमान में केन्द्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान के तहत महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों के आधारभूत सुविधाओं के उन्नयन हेतु राशि स्वीकृत की जाती है । वर्तमान में नैक से 2.5 अंक प्राप्त करने वाले संस्थान ही राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान के तहत अनुदान प्राप्त करने के पात्र हैं ।

श्री ललित कुमार यादवः यह तो मंत्री जी ने विस्तार से बतला ही दिया है, फिर उसी जवाब को पढ़ रहे हैं ।

अध्यक्षः माननीय सदस्य, विपक्ष भी सरकार के अंग होते हैं । आपका कोई सुझाव है तो वह बता दीजिये । आप कह रहे थे, कोई सुझाव है तो बता दीजिये । उन्होंने तो साफ-साफ शब्दों में बता दिया है ।

श्री अवध बिहारी चौधरीः महोदय, विपक्ष भी सरकार के अंग होते हैं, लेकिन विपक्ष द्वारा अगर कोई अच्छे प्रश्न किया जायं, तो सरकार को भी स्पष्ट तरीके से इधर-उधर नहीं भटका कर उन प्रश्नों का स्पष्ट जवाब देना चाहिए ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, हमारे चौधरी साहब ने ठीक ही कहा और इसीलिए हमने शुरू में ही माननीय सदस्य श्री ललित यादव जी को कहा था कि आपका प्रश्न बहुत ही मौजू है, आपने सही प्रश्न को उठाया है । ये सरकार की भी चिन्ता है और आपने सुना होगा कि हमने ये भी कहा कि हमारी संस्थाओं के जो हायर स्टडीज के इंस्टीच्यूशंस हैं उनको नैक की मान्यता मिले । इसलिए सरकार तो प्रयत्न कर रही है और जैसा कि अवध विहारी बाबू ने कहा कि हमने तो कहा कि आपके भी जो सुझाव हैं, वह दे दीजिये, हमलोग उस पर भी अमल करने को तैयार हैं ।

श्री संदीप सौरभः अध्यक्ष महोदय..

अध्यक्षः अब आपका क्या है ? अब तो इतना क्लीयर जवाब हो गया । क्या है बोलिये जल्दी ।

श्री संदीप सौरभः अध्यक्ष महोदय, मेरा कहना है कि नैक का तो ग्रेडिंग होता है, 2.5 चाहिए और उसमें बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर ग्रेडिंग हो रहा है लेकिन तीन यूनिवर्सिटीज अभी है आपकी, आरा की यूनिवर्सिटी वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी, 40 एकड़ में से 25 एकड़ उसकी जमीन जो है वह मेडिकल कॉलेज को दे दी गयी है । 6 होस्टल, 32 स्टाफ क्वार्टर और एक स्टेडियम मगध यूनिवर्सिटी का वह आई0आई0एम0 को दे दिया गया है । मिथिला यूनिवर्सिटी का जो दूर शिक्षा विभाग था, निदेशालय था उसका, उसको भी बंद कर दिया गया है तो जब आपको बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर नैक की मान्यता प्राप्त करने के लिए चाहिए, ऐसे में सब जगह पर यूनिवर्सिटीज को काटकर उसका हिस्सा अलग किया जा रहा है तो यह तो 90 प्रतिशत हमें लगता है कि धीरे-धीरे वह और खराब स्थिति में चली जायेगी । इस पर माननीय मंत्री जी को क्या कहना है, इन तीन यूनिवर्सिटीज के बारे में ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्रीः महोदय, माननीय सदस्य ने जो बात कही है, उनकी चिंता भी वाजिब है लेकिन इसको दो तरीके से देखा जाना चाहिए कि एक तो सरकार ने जो जमीन निकाल कर मेडिकल कॉलेज को दी, जैसा कि आपने बताया, आखिर वह भी हायर स्टडीज उच्चतर शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए ही किया गया है चूंकि मेडिकल कॉलेज की भी राज्य में उतनी ही आवश्यकता है और दूसरी बात सुनिये जो आपने चिन्ता जाहिर की है कि जितनी जमीन जिस भी विश्वविद्यालय की या महाविद्यालय की निकाल कर दूसरे संस्थानों को दी गयी है, उतने से उस महाविद्यालय या उस विश्वविद्यालय की नैक के द्वारा मान्यता पाने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है ।

श्री अजीत कुमार सिंहः महोदय, एक सवाल है कि जो विश्वविद्यालय की जमीन एक्वायर की गयी है बहुत मुश्किल से और अगर उसकी 25 एकड़ जमीन मेडिकल कॉलेज को दे दी जायेगी तो हमारी जो यूनिवर्सिटी है, जहां से हमने पी0एच0डी0 किया है, कई लोगों ने वहां से पास किया है तो ऐसी स्थिति में उसकी मान्यता ही खत्म हो जायेगी, यूनिवर्सिटी होने का क्राईटेरिया उसका खत्म हो जायेगी । दूसरी बात है कि मेडिकल कॉलेज के हम विरोधी नहीं है, मेडिकल कॉलेज के लिए दूसरी जमीन आवंटित की जाय, क्यों विश्वविद्यालय के लिए अर्जित की हुई जमीन पर मेडिकल कॉलेज खोला जा रहा है, इसके पहले भी उसी यूनिवर्सिटी के अन्दर सेन्ट्रल स्कूल के लिए उसकी जमीन को दे दिया गया । बहुत मुश्किल से यह एक यूनिवर्सिटी है पूरी का पूरी यूनिवर्सिटी खत्म हो जायेंगी महोदय, चार जिलों का एक मात्र विश्वविद्यालय है, लोग कहां जायेंगे विश्वविद्यालय में, यह बहुत बड़ा सवाल है,

वहां अनशन चल रहा है, लड़के आन्दोलन कर रहे हैं और महोदय, आज यह सवाल आया है तो हम आपके माध्यम से चाहेंगे कि कम से कम वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय, मगध विश्वविद्यालय जैसे ये जो ऐतिहासिक धरोहर है इसको बचाने की आपसे हम गुजारिश करते हैं, इसको बचाने की कोशिश की जाय और मेडिकल कॉलेज को वहां से स्थानांतरित करके विश्वविद्यालय के वजूद को बचाया जाय, उसके लिए हमलोग सवाल उठा रहे हैं ।

श्री संदीप सौरभः महोदय, मगध विश्वविद्यालय में सिर्फ 6 ही होस्टल थे, कैम्पस के अंदर 6 होस्टल हैं और 6 के 6 आप आई0आई0एम0 को दे देंगे तो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर कहां बच रहा है वहां पर, 32 स्टाफ क्वार्टर चले जायेंगे, एक खेल का स्टेडियम है वह चला जायेगा तो क्या बच रहा है इस यूनिवर्सिटीज के पास?

अध्यक्षः अब बैठ जाइए ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्रीः महोदय, यूनिवर्सिटी की जमीन मेडिकल कॉलेज या किसी दूसरे संस्थानों को दी जानी चाहिए कि नहीं दी जानी चाहिए, ये इस प्रश्न के क्षेत्राधिकार में नहीं है पहली बात, दूसरी बात इस प्रश्न से संबंधित जो बात या जो मुद्दा है, इसके लिए हमने सदन को बताया है कि जो जमीन दी गयी है, उससे संबंधित विश्वविद्यालय के नैक की मान्यता प्रभावित नहीं होती है ।

अध्यक्षः चलिये, अब बैठ जाइए, हो गया। अब तारांकित प्रश्न लिये जायेंगे।

श्री संदीप सौरभः महोदय...

(व्यवधान)

अध्यक्षः जिससे संबंधित विषय हो, उन सारे विषयों को आप अलग से लाइए । जो आपकी चिंता है, वह अलग से विषय लाइए ।

तारांकित प्रश्न संख्या-1347(मो0 आफाक आलम, क्षेत्र सं0- 58, कसबा)

(व्यवधान)

अध्यक्षः माननीय मंत्री, शिक्षा विभाग ।

श्री संदीप सौरभः बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है महोदय...

(व्यवधान)

अध्यक्षः बैठ जाइए, आप बैठ जाइए । आप देखें कि पूरे 8 मिनट इस क्वेश्चन पर चला है।

(व्यवधान)

श्री भाई वीरेन्द्रःअध्यक्ष महोदय,सरकार इस पर गंभीर हो...

(व्यवधान)

अध्यक्षः माननीय मंत्री अब जवाब देंगे, बैठ जाईए वीरेन्द्र जी।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री:1-वस्तुस्थिति यह है कि मध्य विद्यालय प्राणपति का उत्क्रमण उच्च माध्यमिक विद्यालय में वित्तीय वर्ष 2014-15 में हुआ था।

2 एवं 3- वस्तुस्थिति यह है कि उक्त विद्यालय के भवन निर्माण हेतु संवेदक से एकरारनामा 14-05-2015 को किया गया था। भवन का निर्माण कार्य दिनांक 15-10-15 को प्रारम्भ हुआ जो 19-4-17 से अवरूद्ध हो गया । प्रश्नगत विद्यालय के भवन निर्माण का कार्य प्रथम तल के छत स्थल तक किया गया है। भवन का निर्माण प्राक्कलन के अनुरूप नहीं होने की शिकायत प्राप्त होने पर उसकी जांच कराकर एकरारनामा को दिनांक 25-02-2021 को विखंडित कर दिया गया है। संबंधित संवेदक के परफौरमेंस सेक्यूरिटी की राशि को जप्त करते हुए संवेदक को काली सूची में दर्ज करने हेतु कार्रवाई हो रही है, साथ ही भवन निर्माण को पूर्ण करने के लिए निविदा आमंत्रित कर नये संवेदक के माध्यम से कार्य पूर्ण करा दिया जायेगा।

श्री मो0 आफाक आलम: अध्यक्ष महोदय...

अध्यक्ष: अब तो इतना स्पष्ट उत्तर दे दिये हैं जो प्रश्न आपका था,काली सूची में जा ही रहा है।

श्री मो0 आफाक आलम: अध्यक्ष महोदय, वह काली सूची में जा ही रहा है लेकिन इस स्कूल के जो बच्चे हैं उसको दूसरे जगह पर सिफ्ट कर दिया गया है और वहां पर प्राईमरी स्कूल, मध्य विद्यालय और हाई स्कूल तीनों का बच्चा एक ही जगह पढ़ रहा है, स्कूल में जगह नहीं है, दूसरी बात यह है कि जो संवेदक इसको काम किये हैं उस पर तो कार्रवाई हो रही है लेकिन विभाग के जो अफसर जे0ई0 हैं, एक्सक्यूटिव हैं या अन्य लोग हैं और भवन का कार्य इतना ऊपर चला गया तब तक वे लोग इस काम को नहीं देखें और दूसरी बात यह है कि यह भवन कबतक में बनेगा, दूसरे जगह पर बच्चे की पढ़ाई वहां कैसे होगी, इस पर बतावें कि भवन कब तक बनेगा ?

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री: महोदय, हमने दानों बात बतलायी है कि भवन निर्माण में देरी हुई है और संवेदक द्वारा जो उसमें स्पेसिफिकेशन था उसके हिसाब से नहीं कार्य किये जाने के शिकायत प्राप्त हुए थे और जांच में भी शिकायत सही पाया गया इसलिए काम रोक कर उसका एकरारनामा विखंडित किया गया और उसको ब्लैकलिस्ट भी किया जा रहा है। संबंधित जो जे0ई0 हैं उनसे भी सो-काऊज किया जायेगा और जो शेष कार्य है उसका अलग से प्राक्कलन बनाकर, निविदा कर के अगले वित्तीय वर्ष में पूरा कर दिया जायेगा।

टर्न-3/मधुप/09.03.2021

श्री महबूब आलम : कार्यपालक अभियंता पर कार्रवाई करने का इरादा है कि नहीं ?

अध्यक्ष : क्या ?

श्री महबूब आलम : कार्यपालक अभियंता जो है संबंधित विद्यालय के निर्माण का...

अध्यक्ष : अब तो बता दिये कि जो दोषी है...

श्री महबूब आलम : दोषी है तो कार्यपालक अभियंता दोषी है, जे0ई0 पर क्यों छोड़ दिया गया?

अध्यक्ष : पदाधिकारी जो हैं, जे0ई0 के बारे में बताये हैं कि उससे भी स्पष्टीकरण लिया गया है ।

तारांकित प्रश्न सं0-1348 (श्रीमती रश्मि वर्मा, क्षेत्र सं0-3 : नरकटियागंज)

(लिखित उत्तर)

श्रीमती शीला कुमारी, मंत्री : बिहार राज्य पथ परिवहन निगम के बस बेड़ा में बसों की कमी है। फलस्वरूप सभी जिलों के प्रमुख मार्गों पर बसों का परिचालन कराया जा रहा है ।

वर्तमान में प्रस्तावित मार्ग पर बस परिचालन करने का प्रस्ताव निगम के विचाराधीन नहीं है ।

प्राइवेट बस मालिकों द्वारा मनमाफिक किराया वसूलने संबंधी तथ्य की जॉच कर नियमानुसार कार्रवाई करने हेतु जिला परिवहन पदाधिकारी, बेतिया(पश्चिमी चम्पारण) को विभागीय पत्रांक-1708, दिनांक-02.03.2021 द्वारा निदेशित किया गया है ।

अध्यक्ष : उत्तर संलग्न है । पूरक पूछिये ।

श्रीमती रश्मि वर्मा : महोदय, मेरा क्षेत्र गांधी जी की कर्मभूमि है, भितिहरवा आश्रम यहीं पर अवस्थित है । सरकारी बस का परिचालन होने से इलाज, पढ़ाई एवं कार्यालय संबंधित चीजों में सहुलियत होगी । महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी विशेष ध्यान इस क्षेत्र पर रहा है....

अध्यक्ष : आप पूरक पूछिये, भूमिका बनाने में समय बरबाद न करें माननीय सदस्या ।

श्रीमती रश्मि वर्मा : महोदय, माननीय मंत्री महोदया द्वारा यह कहा गया है कि वर्तमान में प्रस्तावित मार्ग पर बस परिचालन होने हेतु निकट भविष्य में भी कोई योजना नहीं है। तो क्या यहॉ की जनता प्राइवेट बसों का मनमाना किराया देती रहे ? महोदय....

अध्यक्ष : पूरक क्या है ? क्या जानना चाहती हैं ? क्या पूछना चाहती हैं ?

श्रीमती रश्मि वर्मा : महोदय, कबतक उक्त मार्ग पर बस का परिचालन कराना चाहती हैं ?

श्रीमती शीला कुमारी, मंत्री : हम इसपर विचार करेंगे, जल्द ही कर देंगे ।

अध्यक्ष : जल्द करेंगे विचार ।

तारांकित प्रश्न सं0-1349 (श्री महानंद सिंह, क्षेत्र सं0-214 : अरवल)

(लिखित उत्तर)

श्री सुमित कुमार सिंह, मंत्री : उत्तर अस्वीकारात्मक है । राज्य सरकार द्वारा सात निश्चय कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्य के प्रत्येक जिले में पॉलिटेक्निक संस्थान स्थापित करने का निर्णय है ।

उक्त के आलोक में विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 821, दिनांक 17 मार्च, 2016 के द्वारा राज्य के अरवल जिले में पॉलिटेक्निक संस्थान की स्थापना की योजना की स्वीकृति प्रदान की गयी है ।

आयुक्त कार्यालय, मगध प्रमंडल, गया के पत्रांक 3516, दिनांक 30 नवम्बर, 2018 के द्वारा अरवल जिला में पॉलिटेक्निक संस्थान की स्थापना हेतु कुर्था अंचल के मौजा-धमौल में 5.00 एकड़ भूमि विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग, बिहार, पटना को अंतर्विभागीय नि:शुल्क हस्तान्तरण की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 21, दिनांक 19 जनवरी, 2019 द्वारा अरवल जिला में पॉलिटेक्निक संस्थान की स्थापना की स्वीकृति तथा संस्थान के भवनों के निर्माण कार्यों के लिये कुल रूपया 36.35 करोड़ (छत्तीस करोड़ पैंतीस लाख रूपये) मात्र के अनुमानित व्यय पर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गयी है ।

भवन निर्माण विभाग से प्राप्त प्रतिवेदनानुसार पॉलिटेक्निक संस्थान के भवनों का निर्माण अभी प्रारंभिक अवस्था में है ।

वर्तमान में राजकीय पॉलिटेक्निक अरवल राजकीय पॉलिटेक्निक अस्थावॉ (नालन्दा) के परिसर में संचालित है तथा शैक्षणिक सत्र 2019-20 से पठन-पाठन की प्रक्रिया प्रारंभ है ।

अध्यक्ष : उत्तर मुद्रित है । पूरक पूछिये ।

श्री महानंद सिंह : महोदय, अरवल में पॉलिटेक्निक कॉलेज के लिए 30 नवम्बर, 2018 को ही जमीन की स्वीकृति मिल गई है । इसके अलावे 2019 में प्रशासनिक स्वीकृति मिल गई है 36 करोड़ 35 लाख रूपये का । फिर भी अरवल के छात्रों को अस्थावॉ जाकर वहॉ पढ़ना पड़ता है, एडमीशन लेना पड़ता है ।

महोदय, आपके माध्यम से हम मंत्री महोदय से जानना चाहते हैं कि कबतक वहॉ बनेगा ? अभी तक भवन का निर्माण शुरू नहीं किया गया है, बनना भी शुरू नहीं हुआ है ।

अध्यक्ष : मंत्री, विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग ।

श्री सुमित कुमार सिंह, मंत्री : महोदय, उत्तर अस्वीकारात्मक है । राज्य सरकार द्वारा...

अध्यक्ष : उत्तर मुद्रित है । जो पूरक पूछे हैं, उसका जवाब दीजिए । माननीय सदस्य, बताइये एक बार कि पूरक क्या है ?

श्री महानंद सिंह : महोदय, पूरक है कि वहाँ जमीन की भी स्वीकृति मिल गई है, पैसे का भी आवंटन हो गया है, फिर भी वहाँ भवन नहीं बना है । अरवल के छात्रों को नालन्दा के अस्थावाँ जाना पड़ता है पढ़ने के लिए, एडमीशन के लिए तो कबतक बनेगा वहाँ ? अभी तक भवन नहीं बना है ।

श्री सुमित कुमार सिंह, मंत्री : महोदय, भवन निर्माण विभाग से जो जानकारी मिली है, कार्य प्रारंभ हो गया है और अगर ऐसा कुछ है तो हम उसकी जानकारी लेकर माननीय सदस्य को अवगत करा देंगे ।

अध्यक्ष : कार्य प्रारंभ हो गया है ।

श्री महानंद सिंह : जानकारी नहीं हुआ है । पहले ही से सवाल दिया गया है, हुजूर ।

अध्यक्ष : कह रहे हैं कि कार्य प्रारंभ हो गया है । जानकारी है आपको ?

श्री महानंद सिंह : अभी प्रारंभ नहीं हुआ है । जाँच करवाया जाय ।

अध्यक्ष : आप जाँच करवा लीजिए ।

श्री सुमित कुमार सिंह, मंत्री : महोदय, हम इसकी जाँच करवा कर हम देखवा लेंगे ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : अब आप यहाँ से उठकर वहाँ कहाँ चले गये ? बैठिए ।

तारांकित प्रश्न सं0-1350 (श्रीमती वीणा सिंह, क्षेत्र सं0-129 : महनार)

अध्यक्ष : उत्तर संलग्न है । पढ़ दिया जाय क्या ?

श्रीमती वीणा सिंह : महोदय, यह बहुत ही जरूरी है जन्दाहा बाजार के लिए तो इसको...

अध्यक्ष : आप उत्तर निकाल कर देखी हैं ?

श्रीमती वीणा सिंह : नहीं देखे हैं, सर ।

अध्यक्ष : तो पढ़ दीजिए माननीय मंत्री, शिक्षा विभाग ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : महोदय, उत्तर आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है ।

वस्तुस्थिति यह है कि वैशाली जिला के नगर परिषद् महनार अन्तर्गत वार्ड नं0-7 में राजकीय मध्य विद्यालय की कुल 1400 फीट चाहरदीवारी निर्मित है, जिसमें से लगभग 100 फीट आंशिक रूप से जर्जर एवं गड़बड़ है ।

आगामी वित्तीय वर्ष में प्राथमिकता के आधार पर उक्त विद्यालय के जर्जर हिस्से की मरम्मती करा दी जाएगी ।

तारांकित प्रश्न सं0-1351 (श्री ललन कुमार, क्षेत्र सं0-154 : पीरपैंती(अ0जा0)

(लिखित उत्तर)

श्री संतोष कुमार सुमन, मंत्री : स्वीकारात्मक ।

2. अनुसूचित जनजाति के सर्वांगीण विकास तथा शैक्षणिक स्थिति में सुधार के लिए आवासीय विद्यालय पूर्व से ही बिहार में संचालित हैं । वर्ष 2010 में शिवनारायणपुर में अनुसूचित जानजाति आवासीय विद्यालय खोले जाने का कोई निर्णय नहीं हुआ है ।

3. वस्तुस्थिति यह है कि विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या-66 दिनांक-10.10.2017 द्वारा भागलपुर जिलान्तर्गत कहलगॉव अनुमंडल के पीरपैंती अंचल के मौजा-खवासपुर दियारा में अनुसूचित जनजाति सह-शिक्षा (Co-ed) आवासीय विद्यालय निर्माण की स्वीकृति दी गई है ।

अध्यक्ष : उत्तर संलग्न है । पूरक पूछिये ।

श्री ललन कुमार : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी का जवाब आया है कि शिवनानाराणपुर के बजाय पीरपैंती अंचल के खवासपुर दियारा में अनुसूचित जनजाति आवासीय विद्यालय खोलने की स्वीकृति वर्ष 2017 में ही सरकार द्वारा दे दी गई है। बहुत अच्छी बात है, अध्यक्ष महोदय । खवासपुर को बिहार सरकार के द्वारा आदर्श ग्राम का भी दर्जा प्राप्त है । मेरा प्रश्न है कि क्या माननीय मंत्री खवासपुर में आवासीय विद्यालय खोलना चाहते हैं ? यदि हॉ, तो कबतक, अगर नहीं तो क्यों?

श्री संतोष कुमार सुमन, मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि उत्तर में मुद्रित है कि खवासपुर में प्रशासनिक स्वीकृति हो गई है 2017 में और पिछले कैबिनेट से भी इसकी स्वीकृति जो रेट रिवीजन का था, उसका भी हो गया है ।

महोदय, मैं माननीय सदस्य को आपके माध्यम से आश्वस्त कर देना चाहता हूँ कि अगले वित्तीय वर्ष में कार्य प्रारंभ हो जायेगा और बहुत जल्द ही ।

श्री ललन कुमार : अध्यक्ष महोदय, एक बात....

अध्यक्ष : स्पष्ट जवाब दे दिये, अब बैठ जाइये ।

श्री ललन कुमार : अध्यक्ष महोदय, एक मिनट ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं । माननीय मंत्री, ध्यान में रखियेगा कि कटोरिया और बरारी के बाद हमारे पीरपैंती विधान सभा क्षेत्र में सबसे ज्यादा अनुसूचित जाति जनजाति की संख्या है....

अध्यक्ष : आप डिटेल में मिलकर बता दीजियेगा ।

श्री ललन कुमार : इसलिए इसको प्राथमिकता सूची में रखा जाय ।

तारांकित प्रश्न सं0-1352 (श्री विजय कुमार सिंह उर्फ डब्लू सिंह(क्षेत्र सं0-221 : नवीनगर)

(लिखित उत्तर)

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : वस्तुस्थिति यह है कि प्रयोगशाला की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु वित्तीय वर्ष 2017-18 में राज्य के 2000 उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कक्षा-11 एवं 12 के लिए प्रति विद्यालय 5 लाख रूपये की दर से राशि उपलब्ध कराई गई । इसी प्रकार 4000 उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कक्षा- 9 एवं 10 के लिए प्रति विद्यालय 3 लाख रूपये की दर से राशि उपलब्ध कराई गई ।

विद्यालय के शिक्षक के द्वारा प्रयोगशाला का संचालन किया जाता है । इस हेतु प्रायोगिक शिक्षा के लिए अलग से शिक्षकों की बहाली का प्रावधान नहीं है।

अध्यक्ष : उत्तर संलग्न है । पूरक पूछिये ।

श्री विजय कुमार सिंह उर्फ डब्लू सिंह : महोदय, माननीय मंत्री जी से हम यह जानना चाहते हैं कि इसमें कबतक शिक्षकों की बहाली होगी क्योंकि हमलोगों के यहाँ +2 में प्रयोगशाला में एक भी शिक्षक नहीं है ?

अध्यक्ष : आप पूरक पूछे हैं कबतक ? बताइये ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : महोदय, उत्तर में तो बताया गया है कि शिक्षकों की बहाली की प्रक्रिया चल रही है । माननीय उच्च न्यायालय के आदेश से यह रूक गई थी लेकिन अब जो सूचना है कि हमलोगों ने विभाग की तरफ से अनुरोध किया तो न्यायालय द्वारा उसकी इजाजत दी जा रही है जैसी सूचना है, तो उसके आधार पर हमलोग तुरत शिक्षकों की बहाली करने वाले हैं और जहाँ तक माननीय सदस्य कह रहे हैं कि प्रयोगशालाओं के लिए अलग से शिक्षक, तो महोदय, विद्यालयों में प्रयोगशालाओं के लिए अलग से शिक्षकों की व्यवस्था नहीं होती है । जो विभिन्न विषयों से संबंधित शिक्षक होते हैं, प्रयोगशालाओं में वही शिक्षक छात्रों को प्रयोगशाला से संबंधित चीजों का भी ज्ञान देते हैं ।

तारांकित प्रश्न सं0-1353 (श्री शाहनवाज, क्षेत्र सं0-50 : जोकीहाट)

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, शिक्षा विभाग । इसका जवाब नहीं आया है ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : जवाब तो ऑनलाईन कर दिया गया है ।

अध्यक्ष : ना । पढ़ दिया जाय ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि राज्य के अराजकीय प्रस्वीकृत अनुदानित मदरसों/संस्कृत विद्यालयों में कार्यरत नियमित शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मियों जिनकी नियुक्ति 15.02.2011 के पूर्व हुई है तथा उन्हें नियमित वेतनमान दिया जा रहा है, वे इस योजना से आच्छादित नहीं हैं ।

ज्ञातव्य हो कि विभागीय संकल्प संख्या-985 एवं 986 दिनांक-18.11.2020 द्वारा राज्य के अराजकीय प्रस्वीकृत अनुदानित मदरसा एवं संस्कृत विद्यालय में दिनांक- 15.02.2011 से अथवा उसके बाद स्वीकृत पदों के विरूद्ध नियुक्त एवं कार्यरत कर्मियों को दिनांक-01 अक्टूबर, 2020 के प्रभाव से ई0पी0एफ0 स्कीम से आच्छादित करने की स्वीकृति दी गयी है तथा विभागीय पत्रांक-1012 दिनांक-02.12.2020 द्वारा ई0पी0एफ0 स्कीम के आच्छादन हेतु जिलों को दिशा निर्देश जारी भी कर दिया गया है ।

महोदय, जो सूचना है, प्रायः सभी जिलों के अराजकीय प्रस्वीकृत अनुदानित मदरसों एवं संस्कृत विद्यालयों में दिनांक-15.02.2011 से अथवा उसके बाद विधिवत रूप से नियुक्त एवं कार्यरत कर्मियों को ई0पी0एफ0 स्कीम में अंशदान की कटौती की जा रही है ।

टर्न-4/आजाद/09.03.2021

<u>तारांकित प्रश्न सं0-1354(श्री राघवेन्द्र प्रताप सिंह,क्षेत्र सं0-193 बड़हरा)</u>

(लिखित उत्तर)

श्री आलोक रंजन, मंत्री : 1. उत्तर आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है ।

2. उत्तर आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है ।

3. वस्तुस्थिति यह है कि भोजपुर जिला अन्तर्गत बड़हरा प्रखंड में स्टेडियम निर्माण की स्वीकृति हेतु जिला पदाधिकारी, भोजपुर से प्रस्ताव की मांग विभागीय पत्रांक-434, दिनांक 02.03.2021 द्वारा की गयी है ।

प्रस्ताव प्राप्त होते ही विभागीय मानक के अनुरूप निर्विवाद सरकारी भूमि उपलब्ध होने पर स्टेडियम निर्माण की स्वीकृति पर विचार किया जायेगा ।

श्री नीतीश मिश्रा : महोदय, मुझे अधिकृत किया गया है, उत्तर आया हुआ है ।

अध्यक्ष : ठीक है बोलिए ।

श्री नीतीश मिश्रा : महोदय, माननीय मंत्री जी से कुछ पूरक है, जिसके संबंध में जानना चाहूंगा कि पहला जो जिलाधिकारी से प्रस्ताव मांगा गया है, एक तो प्रस्ताव का समय सीमा ये बता दें कि कितने दिनों के अन्दर .....

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, बैठ जाइए ।

श्री नीतीश मिश्रा : कितने दिनों के अन्दर यह प्रस्ताव आयेगा क्योंकि प्रायः जिलों से प्रस्ताव मांगा जाता है लेकिन समय पर नहीं आता है । मैं एक ही साथ दूसरा पूरक भी पूछ लेता हूँ कि हरेक प्रखंड में स्टेडियम का निर्माण होगा, यह सरकार की योजना है, यह स्कीम कब बनाई गयी थी और बिहार के 534 प्रखंड में जब हमें स्टेडियम बनाना है तो एक वित्तीय वर्ष में कितने प्रखंड में बना लेते हैं और एक ही साथ सबों का ये प्रस्ताव मंगा लें, मैं यही सुझाव देना चाहूँगा कि बिहार में जिस प्रखंड में स्टेडियम नहीं बने हैं, एक ही साथ सभी प्रखंडों का प्रस्ताव मंगा लें, इससे विभाग को सहूलियत होगी ।

श्री आलोक रंजन, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, पत्रांक-434 दिनांक 02.03.2021 द्वारा यह प्रस्ताव मांगी गयी है । अब जितना जल्दी वहां से आ जाय, हम तो माननीय सदस्य से भी आग्रह करेंगे कि वहां लगकर के जितना जल्दी प्रस्ताव भेजवा देंगे हमलोग काम को शुरू करवा देंगे ।

श्री अनिल कुमार साहनी : अध्यक्ष महोदय, ...

अध्यक्ष : मंत्री जी खड़े हैं, माननीय सदस्य, आप सांसद रहे हैं न, मंत्री जी जब खड़े हैं तो आप बैठ जाइए, वे बैठेंगे तो आप उठियेगा ।

श्री नीतीश मिश्रा : अध्यक्ष महोदय, मैंने पूरक में स्पष्ट कहा है कि इनका उत्तर आया है । जिला से लगकर के विधायकों को प्रस्ताव अगर भेजवाना पड़ेगा तो मेरे समझ से विभाग यह समन्वय कर ले जिला प्रशासन से और विभाग एक समय निर्धारित करे कि एक माह के अन्दर, तीन माह के अन्दर प्रस्ताव आपको अवश्य भेज देना है ।

श्री भाई वीरेन्द्र : अध्यक्ष महोदय, सरकार बेबस है .....

अध्यक्ष : आपको पूरक पूछना है, अब इनका प्रश्न ध्यान से सुनिए, अब बैठिए ।

तारांकित प्रश्न सं0-1355(श्री मो0 नेहालउद्दीन,क्षेत्र सं0-224 रफीगंज)

अध्यक्ष : उत्तर संलग्न है ।

श्री मो0 नेहालउद्दीन : अध्यक्ष महोदय, मेरे पास नहीं है, कृपया पढ़वा दिया जाय ।

अध्यक्ष : थोड़ा पी0ए0 सबको लगाइए, उत्तर निकाल कर देखने के लिए । पढ़ दिया जाय माननीय मंत्री, शिक्षा विभाग ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि रफीगंज प्रखंड में उत्क्रमित मध्य विद्यालय कोटवारा अवस्थित है, जिसमें विद्यालय का तीन कमरा निर्मित है और शेष भूमि खाली है जिसको विवादित एवं अतिक्रमित होने के कारण उक्त विद्यालय में शौचालय निर्माण का कार्य नहीं हो सका है । अतिक्रमण मुक्त करने हेतु अतिक्रमणवाद दायर किया गया है, जिसका वाद सं0-02/2020-21 है ।

उत्क्रमित मध्य विद्यालय कोटवारा में चूँकि जो खाली जगह है, जहां शौचालय बनना था, उसपर विवाद चल रहा है, अतिक्रमण भी है तो हमने विद्यालय

की तरफ से अतिक्रमणवाद दायर भी करा दिया है और इस बीच हमने कहा है कि कम से कम छात्र एवं छात्राओं को असुविधा नहीं हो, इसलिए कोई टेम्पोरेरी शौचालय भी वहां पर बनवा दिया जाय ।

अध्यक्ष : बहुत सकारात्मक उत्तर है ।

श्री मो0 नेहालउद्दीन : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा सवाल था कि अक्रिमण हुआ है तो क्या उसको मुक्त कराकर के उसपर पिछले कई सालों से वहां पर जो पैसा मौजूद है, उसका इस्तेमाल किया जायेगा या नहीं तो हम आपसे जानना चाहते हैं कि अतिक्रमण हटाने का यह 10 सालों से नहीं 1953 में यह जमीन महामहिम राज्यपाल महोदय के नाम से दान किया गया था और यह अतिक्रमणवाद कब चल रहा है 2021 में, जब यहां सवाल दायर किया गया तब वाद दायर किया गया है । इसके पहले उनको कोई सूचना नहीं थी ? हम यही सिर्फ यही कहना चाहते हैं कि जो 50-60 साल से स्कूल है, जमीन है, मकान है, पैसा वहां पर उपलब्ध है तो आज तक सरकार ने वहां शौचालय नहीं बनवाया, खासकर के लड़कियों का, महिलाओं का मामला है, उनको बहुत दिक्कत होती है शौच करने के लिए इसलिए कृपया इसको बनवाया जाय और जो दबंग लोग हैं उनसे जमीन खाली करवाया जाय । महामहिम राज्यपाल महोदय के नाम से यह जमीन दान किया हुआ है । इसलिए सरकार कब तक उस अतिक्रमण को खतम करवा करके वहां पर शौचालय निर्माण कराने का इरादा रखती है ?

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : महोदय, माननीय सदस्य सही कह रहे हैं और हमने भी स्वीकार किया है कि विद्यालय की भूमि, जमीन अतिक्रमित है और इसीलिए हमने विभाग की तरफ से, उस स्कूल की तरफ से अतिक्रमणवाद दायर करवाया है और यह कानूनी प्रक्रिया की शुरूआत हो चुकी है और जो अतिक्रमण है महोदय, उसको खाली करवाया जायेगा । जहां तक माननीय सदस्य छात्र-छात्राओं की असुविधा की बात शौच के लिए कर रहे हैं तो उसके संबंध में संज्ञान लेते हुए हमने निदेश दिया है कि कम से कम टेम्पोरेरी शौचालय वहां पर जहां भी जमीन उपलब्ध है, जितना भी जमीन उपलब्ध है, उसमें शौचालय बनवा दिया जाय और हमारी कोशिश होगी कि एक महीने के अन्दर वहां पर टेम्पोरेरी शौचालय बनवा दिया जायेगा ।

श्री मो0 नेहालउद्दीन : माननीय मंत्री महोदय जो वाद आप कह रहे हैं, वह अंचल अधिकारी के यहां हुआ है । हम तो वही कहेंगे कि उसी का सह और वही मुद्दई और वही मुंशी, सब वही लोग हैं, इसलिए उनसे इंसाफ की हमें उम्मीद नहीं है । आप किसी एडिशिनल कलक्टर को या कलक्टर को निदेशित कीजिए । 3 साल पहले महोदय हमने एजुकेशन के सचिव महोदय से बात किया था लेकिन अभी तक कुछ

नहीं हुआ । इसीलिए आप इसपर संज्ञान लीजिए और इसपर कलक्टर को निदेश दिया जाय कि जिला कलक्टर या एडिशनल कलक्टर से इसकी जॉच कराया जाय।

अध्यक्ष : ठीक है, अब क्वेश्चन को आगे बढ़ने दीजिए । माननीय सदस्य श्री बीरेन्द्र सिंह ।

तारांकित प्रश्न सं0-1356 (श्री बीरेन्द्र सिंह,क्षेत्र सं0-234 वजीरगंज)

(लिखित उत्तर)

श्री जनक राम,मंत्री : 1. अस्वीकारात्मक है ।

2. गया जिलान्तर्गत वजीरगंज प्रखंड में राधा ईट भट्ठा प्रो0 श्री दिलीप कुमार पिता-श्री देवकीनन्दन प्रसाद, ग्राम-अमन विगहा, पोस्ट-कुर्किहार, थाना-वजीरगंज, गया के द्वारा मौजा-मदारडीह, खेसरा सं0-74, खाता सं0-119 में संचालित किया जा रहा है ।

3. प्रश्नगत चिमनी ईट भट्ठा के लिए बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद, पटना के द्वारा स्थापना की सहमति एवं उत्सर्जन सहमति आदेश प्राप्त है, जिसकी अवधि 31.12.2025 तक वैध है, जिसका अनुश्रवण समय-समय पर बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद, पटना द्वारा किया जाता है ।

4. समाहर्ता के माध्यम से प्राप्त जॉच प्रतिवेदन के आलोक में 1.50 से 2.0 फीट तक मिट्टी कटाई की अधिकतम गहराई 3 मीटर निर्धारित है ।

अध्यक्ष : उत्तर संलग्न है ।

श्री बीरेन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, उत्तर से संतुष्ट नहीं है ।

अध्यक्ष : आप पूरक पूछिए, आपकी संतुष्टि सरकार करेगी ।

श्री बीरेन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि ईट भट्ठा के बगल में ही महादलितों का गांव है और उसके बगल में ही स्कूल संचालित है सरकारी स्कूल । बच्चों को स्कूल जाने में प्रदूषण से ग्रसित होते हैं और महादलित लोग भी प्रदूषण से ग्रसित होते हैं । क्या सरकार फिर से इसकी जॉच कराना चाहती है और नहीं तो क्यों ?

श्री जनक राम,मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य जी को धन्यवाद देना चाहते हैं कि दलित समाज को आपने चिन्ता जाहिर किया है और खुद मैं दलित समाज से ही आता हूँ ।

उत्तर अस्वीकारात्मक है । गया जिला अन्तर्गत वजीरगंज प्रखंड में राधा ईट भट्ठा प्रो0 श्री दिलीप कुमार, पिता-श्री देवकीनन्दन प्रसाद .....

अध्यक्ष : उत्तर तो मिल गया है और माननीय सदस्य पढ़ लिये हैं तो आप पूरक का जवाब दे दीजिए ।

श्री जनक राम, मंत्री : अगर माननीय सदस्य उत्तर से संतुष्ट नहीं होते हैं तो जिला पदाधिकारी का रिपोर्ट लगा हुआ है और फिर दोबारा हम इसकी जॉच करा लेते हैं.....

अध्यक्ष : ठीक है जॉच करा लीजिए, जो रिपोर्ट लगी हुई है ।

तारांकित प्रश्न सं0-1357(श्री मनोज कुमार यादव,क्षेत्र सं0-16 कल्याणपुर)

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, प्रश्नगत विद्यालय में चहारदिवारी निर्माण का कार्य मनरेगा से कराने हेतु जिला शिक्षा पदाधिकारी एवं उप विकास आयुक्त, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी को संसूचित किया गया है ।

श्री मनोज कुमार यादव : महोदय, अनुसूचित जाति से जुड़ा हुआ मामला है और स्कूल बनकर तैयार है और जो उत्तर आया है, उसमें कोई पत्रांक, दिनांक कुछ भी नहीं है । इसलिए माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहेंगे कि इसी वित्तीय वर्ष में करा दीजियेगा ? जवाब गोलमटोल है ।

अध्यक्ष : चलिए, बैठ जाइए । माननीय सदस्य श्री मुकेश कुमार यादव ।

तारांकित प्रश्न सं0-1358(श्री मुकेश कुमार यादव,क्षेत्र सं0-27 बाजपट्टी)

(लिखित उत्तर)

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : वस्तुस्थिति यह है कि मदरसा में विज्ञान शिक्षकों की नियुक्ति भारत सरकार की SPQEM योजनान्तर्गत की गई है । भारत सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2015-16 में उपलब्ध कराई गई राशि से वित्तीय वर्ष 1997-98 से लेकर वर्ष 2013-14 तक बकाया मानदेय भुगतान किया जा चुका है ।

प्रश्नगत शिक्षकों की नियुक्ति वर्ष 2017 में हुई है । वित्तीय वर्ष 2014-15 से वित्तीय वर्ष 2018-19 तक बकाया मानदेय भुगतान हेतु भारत सरकार के स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता मंत्रालय के साथ दिनांक 22.02.2021 को आहुत बैठक में दिए गए निदेश के आलोक में मदरसा बोर्ड द्वारा विज्ञापन प्रकाशित कर उक्त अवधि के भुगतान हेतु जिला को निदेशित किया जा चुका है ।

अध्यक्ष : उत्तर संलग्न है, पूरक पूछ लीजिए ।

श्री मुकेश कुमार यादव : महोदय, 22.02.2021 को आहुत बैठक के द्वारा शिक्षा बोर्ड को निदेशित किया गया है कि विज्ञापन निकाल कर शिक्षकों का भुगतान किया जाय लेकिन डेट निर्धारित नहीं है । महोदय, मैं शिक्षा मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि मदरसा विज्ञान शिक्षकों को कब तक भुगतान किया जायेगा ?

टर्न-5/शंभु/09.03.21

श्री विजय कुमार चौधरी,मंत्री : महोदय, हमने तो उत्तर में बताया है कि इन विज्ञान शिक्षकों की नियुक्ति एवं इनका भुगतान केन्द्र सरकार की एक विशेष योजना जिसे एस0पी0क्यू0एम0 स्कीम फोर प्रोवाइडिंग क्वालिटी एजुकेशन इन मदरसाज इस

विशेष योजना के तहत इनकी नियुक्ति हुई थी और इनका भुगतान किया जाता है । बीच में यह रूक गया था और हमने अपने उत्तर में बताया है कि अभी 22 फरवरी को इसके संबंध में हम ही लोगों के अनुरोध पर एक विशेष बैठक हुई थी जिसमें इस योजना का फिर क्लीयरेंस दिया गया है, राशि भेजे जाने की सूचना दी गयी है और अब इनका भुगतान शुरू हो जायेगा ।

तारांकित प्रश्न सं0-1359(श्री हरिनारायण सिंह)क्षेत्र सं0-177 हरनौत

(अनुपस्थित)

तारांकित प्रश्न सं0-1360(डा0 रामानन्द यादव)क्षेत्र सं0-185 फतुहा

(लिखित उत्तर)

श्री विजय कुमार चौधरी,मंत्री : महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि विभागीय संकल्प सं0-1021, दिनांक 05.07.2013 के द्वारा राज्य सरकार का यह निर्णय संसूचित है कि सभी पंचायतों का एक-एक उच्च माध्यमिक विद्यालय से आच्छादित किया जाय । प्रश्नगत तीनों पंचायत माध्यमिक विद्यालय विहीन थे । उक्त संकल्प के आलोक में प्रश्नगत तीनों विद्यालयों को उच्च माध्यमिक विद्यालय में उत्क्रमित करने का निर्णय विभागीय आदेश सं0-1650, दिनांक 27.08.2015 के द्वारा लिया गया । उक्त उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालयों में प्रति विद्यालय 6 माध्यमिक शिक्षक के पद का सृजन किया जा चुका है । इन पदों पर नियुक्ति होने तक वैकल्पिक व्यवस्था के तहत प्रश्नगत विद्यालयों में स्नातक योग्यताधारित शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति की गयी है ।

अध्यक्ष : पूरक पूछिए, उत्तर संलग्न है ।

डा0 रामानन्द यादव : अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि फतुहा प्रखंड में सात विद्यालय उत्क्रमित हुए हैं- मौजीपुर, बुद्धुचक, कोलहर, डुमरी, दौलतपुर और ढीवर, लेकिन प्रश्न है तीन हाईस्कूल का मौजीपुर, बुद्धुचक और कोलहर तो मौजीपुर में छात्रों की संख्या मध्य विद्यालय में 400 है और उसमें एक हरिजन विद्यालय प्राथमिक भी टैग कर दिया गया है । वहां लड़कों के बैठने के लिए हॉल नहीं है सिर्फ 5 रूम है जिसमें एक में प्राचार्य बैठते हैं, 4 में छात्र पढ़ते हैं और पढ़ाई नहीं होती है और किसी स्कूल में प्रैक्टिकल की व्यवस्था में प्रतिनियुक्ति नहीं है, लेकिन मंत्री जी द्वारा यह बताया गया कि योग्यतानुसार सभी विद्यालय में शिक्षक प्रतिनियुक्त है । मैं चुनौती देता हूँ कि किसी स्कूल में प्रतिनियुक्त नहीं हैं । नहीं तो विषयवार बताया जाय कि किस स्कूल में कौन-कौन शिक्षक किस विषय के हैं । मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ ।

श्री विजय कुमार चौधरी,मंत्री : महोदय, मैंने सिर्फ उत्तर में इतना बताया है कि हमलोगों ने प्रति विद्यालय 6 अलग-अलग विषयों के पद के सृजन की स्वीकृति दी है और हमलोगों की नियुक्ति प्रक्रियाधीन है । अभी सभी माननीय सदस्य समाचार पत्रों के माध्यम से जाना होगा कि एस0टी0इ0टी0 जो 2019 का था इसके रिजल्ट प्रकाशन पर माननीय उच्च न्यायालय से स्थगन का आदेश था उसको सरकार के विशेष अनुरोध पर इजाजत मिल गयी है और हमलोग लगभग 30 हजार से अधिक शिक्षकों की नियुक्ति तत्काल करने जा रहे हैं और वह जो हमने कहा है कि उसमें अलग-अलग विद्यालय के लिए अलग-अलग कोई व्यवस्था नहीं की गयी है या तो जिन विद्यालयों का उत्क्रमण किया गया है, अगर उसमें से कोई पहले से योग्यताधारी शिक्षक थे तो उनसे पढ़ाई का काम लिया जाता है । वर्ना, सरकार की तो मौलिक नीति है कि हम उन विद्यालयों, उत्क्रमित विद्यालयों में अलग से पद सृजन जो हम लोगों ने किया है उसपर अभी ये रिजल्ट प्रकाशन पर रोक हटने की सूचना मिल गयी है । हमलोग अविलंब नियुक्ति कर रहे हैं उसके बाद आपके इन तीनों विद्यालयों में शिक्षकों का पदस्थापन कर दिया जायेगा ।

डा0 रामानन्द यादव : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूँ कि मंत्री जी के उत्तर में है कि जिन उत्क्रमित हाईस्कूल में हम प्रतिनियुक्ति पर विषयवार और योग्यतानुसार कर दिये हैं । उसके बारे में मैं जानना चाहता हूँ और जिस विद्यालय की जमीन उपलब्ध है और बनाया नहीं गया उसपर मंत्री जी जवाब दें ।

अध्यक्ष : उत्तर तो स्पष्ट उन्होंने कर ही दिया है ।

डा0 रामानन्द यादव : अध्यक्ष महोदय, इसमें उत्तर स्पष्ट कहां है ? इसमें उत्तर में लिखा हुआ है कि वैकल्पिक व्यवस्था मैं कर दिया हूँ, उत्क्रमित जितना भी हाईस्कूल है उसमें शिक्षक पढ़ा रहे हैं, कहीं शिक्षक नहीं पढ़ा रहे हैं न प्रैक्टिकल होता है, सब ट्यूशन पढ़कर परीक्षा देते हैं । इनके जवाब में है, जवाब देख लीजिए नीचे । वो सृजन वाला वैकल्पिक व्यवस्था के लिए मंत्री जी कहे हैं । उसपर जवाब दे दें ।

श्री अजय कुमार : महोदय, कब तक बहाली कर दी जायेगी ?

अध्यक्ष : बता ही दिये ।

श्री विजय कुमार चौधरी,मंत्री : महोदय, न्यायालय का स्थगन आदेश था । हमने बताया है कि सरकार के विशेष प्रयास से स्थगन आदेश हटा दिया गया है । अब रिजल्ट प्रकाशित करके शीघ्र से शीघ्र नियुक्ति कर दी जायेगी ।

डा0 रामानन्द यादव : महोदय, नीचे जो प्रश्न का जवाब है.....

(व्यवधान)

अध्यक्ष : अब शीघ्र से शीघ्र हो गया है । अब आगे बढ़ें । माननीय सदस्य, आपका पूरक पूरा हो गया था ।

डा0 रामानन्द यादव : इन्होंने कहा कि डिग्रीधारी की प्रतिनियुक्ति कर देंगे तो कब तक कर देंगे?

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, आप जवाब देखिये अजय जी पूरक पूछ लिये तो आप पूरक पूछ पाइयेगा, जब वे आगे बढ़ गये तो अब आप बैठ जाइये ।

(व्यवधान)

इतना समय नहीं मिलता था हम भी दशक तक रहे हैं इस सदन के सदस्य, इतना समय नहीं मिलता था, बैठ जाइये । उन्होंने जल्द से जल्द कहा है ।

तारांकित प्रश्न सं0-1361(श्री विनय कुमार)क्षेत्र सं0-225 गुरूआ)

श्री विजय कुमार चौधरी,मंत्री : महोदय, उत्तर अस्वीकारात्मक है । वस्तुस्थिति यह है कि गया जिला के गुरूआ प्रखंड के पलुहारा पंचायत के ग्राम झिकटिया में वर्ष 2010 से मध्य विद्यालय झिकटिया अवस्थित है । जहां उक्त ग्राम के वर्ग 1 से 8 तक के बच्चे शिक्षण प्राप्त करते हैं, पठन पाठन में किसी प्रकार की कठिनाई नहीं होती है।

श्री विनय कुमार : उत्तर से संतुष्ट हैं सर ।

तारांकित प्रश्न सं0-1362(श्री सुरेन्द्र मेहता)क्षेत्र सं0-142 बछवाड़ा

(लिखित उत्तर)

श्री विजय कुमार चौधरी,मंत्री : महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि बेगुसराय जिला का बछवाड़ा प्रखंड तेघड़ा अनुमंडल के अन्तर्गत है । तेघड़ा अनुमंडल में डिग्री महाविद्यालय स्थापित करने हेतु सरकार द्वारा निर्णय लिया जा चुका है । इसके लिए जिला पदाधिकारी, बेगुसराय द्वारा भूमि चयन की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है । भूमि चयन के उपरांत तेघड़ा अनुमंडल में डिग्री महाविद्यालय की स्थापना हेतु भवन निर्माण की कार्रवाई शुरू की जायेगी । बछवाड़ा प्रखंड में डिग्री महाविद्यालय खोलने की कोई योजना नहीं है ।

अध्यक्ष : उत्तर संलग्न है, पूरक पूछिए ।

श्री सुरेन्द्र मेहता : महोदय, आपके माध्यम से जानना चाहते हैं कि ये डिग्री कॉलेज कब तक खुलेगा ?

श्री विजय कुमार चौधरी,मंत्री : महोदय, हमने तो उत्तर में कहा है कि तेघड़ा अनुमंडल में भूमि चयन के लिए जिला पदाधिकारी को कार्रवाई करने के लिए कहा गया है । अभी उपयुक्त भूमि का चयन नहीं हो पाया है जैसे ही होगा हमलोग उसके निर्माण की कार्रवाई करेंगे ।

तारांकित प्रश्न सं0-1363(श्री रामवृक्ष सदा)क्षेत्र सं0-148 अलौली

श्री विजय कुमार चौधरी,मंत्री : महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि राज्य सरकार की वर्तमान नीति के अनुसार सिर्फ उन्हीं अनुमंडलों में सरकारी डिग्री महाविद्यालय स्थापित करने की योजना है जहां पूर्व से अंगीभूत डिग्री महाविद्यालय संचालित नहीं है । अलौली

विधान सभा क्षेत्र में खगड़िया अनुमंडल के क्षेत्र भी समाहित हैं । खगड़िया अनुमंडल में पूर्व से कोशी कॉलेज, खगड़िया एवं महिला कॉलेज खगड़िया अंगीभूत महाविद्यालय के रूप में संचालित है । अतः खगड़िया जिला के अलौली विधान सभा क्षेत्र में फिलहाल डिग्री महाविद्यालय खोलने की कोई योजना नहीं है ।

श्री रामवृक्ष सदा : महोदय, अलौली विधान सभा नक्सल प्रभावित क्षेत्र है और अलौली विधान सभा से खगड़िया की दूरी.....

(व्यवधान)

हमको प्रश्न पूछने का अधिकार है कि नहीं है ?

अध्यक्ष : सबको अधिकार है ।

श्री रामवृक्ष सदा : अलौली से खगड़िया की दूरी 8 कि0मी0 पड़ता है और अलौली नक्सल प्रभावित क्षेत्र है । एक तरफ आपकी सरकार कहती है कि हम दलित महादलित को शिक्षा से जोड़ते हैं और सबसे ज्यादा महादलित अलौली प्रखंड के अन्तर्गत आता है फिर भी वहां कॉलेज क्यों नहीं ? सरकार जवाब दे इस मुद्दे पर ।

अध्यक्ष : आप फिर सुझाव ही दे रहे हैं और सरकार ने सुझाव को ग्रहण किया ।

<u>तारांकित प्रश्न सं0-1364(श्री विजय कुमार खेमका)क्षेत्र सं0-62 पूर्णियां</u>

अध्यक्ष : उत्तर संलग्न है, पूरक पूछिए ।

श्री विजय कुमार खेमका : उत्तर संलग्न नहीं है सर । ऑनलाइन नहीं आया है।

अध्यक्ष : उत्तर संलग्न है, उत्तर तो सामने है ।

श्री विजय कुमार खेमका : पढ़ दिया जाय ।

श्री विजय कुमार चौधरी,मंत्री : महोदय, 1- उत्तर स्वीकारात्मक है ।

2 एवं 3- वस्तुस्थिति यह है कि प्रश्नगत विद्यालय में चहारदीवारी है जिसका कुछ भाग क्षतिग्रस्त है । इसे बांस बल्ला से तत्काल घेर दिया गया है । इस विद्यालय के समिति से उनके कोष में उपलब्ध राशि से उक्त चहारदीवारी के क्षतिग्रस्त भाग की मरम्मति कराने का निदेश दिया गया है ।

टर्न-6/ज्योति/09-03-21

श्री विजय कुमार खेमका : अध्यक्ष महोदय, स्वयं शिक्षा मंत्री जी ने स्वीकार किया है कि विद्यालय बड़ा महत्वपूर्ण है और एस.सी./एस.टी...

अध्यक्ष : आप पूरक पूछिये ।

श्री विजय कुमार खेमका : पूरक पूछ रहे हैं अध्यक्ष महोदय, उसमें एस.सी./एस.टी. छात्रावास भी है और पिछले 2016 में ही भवन निर्माण विभाग द्वारा निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, शिक्षा विभाग बिहार पटना को 1 करोड़ 58 लाख 4 सौ रुपये का

प्राक्कलन बनाकर भेजा गया है, उसके निर्माण के लिए । मैं पूरक प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि क्या भेजे गए प्राक्कलन पर विचार करते हुए वहाँ चहारदिवारी निर्माण कराने की स्वीकृति मंत्री महोदय देंगे ?

अध्यक्षः जवाब तो दिया तो जवाब आप सुने नहीं क्या ? कहे कि प्रबंध समिति और आपके जो स्कूल में फंड है उससे करवा लीजिये उससे हटकर पूरक पूछिये न ?

श्री विजय कुमार खेमका : अध्यक्ष महोदय, जो फंड है उससे निर्माण नहीं हो सकता है इसीलिए प्राक्कलन 1 करोड़ 58 लाख का भेजा गया है ।

अध्यक्ष : फंड से निर्माण नहीं हो सकता है चूँकि उतना फंड नहीं है ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : महोदय, उस विद्यालय के विकास कोष में 27 लाख 07 हजार 62 रुपये उपलब्ध है और सिर्फ चहारदिवारी की मरम्मती करानी है ।

अध्यक्ष : अब चलिए उससे करवाईये । अब हो गया ।

तारांकित प्रश्न संख्या 1365–श्री अमरजीत कुशवाहा(क्षेत्र सं0–106 जीरादेई)

अध्यक्ष : उत्तर संलग्न है । माननीय सदस्य पूरक पूछिये ।

श्री अमरजीत कुशवाहा : नहीं मिला है हमको पढ़ दिया जाय ।

अध्यक्ष : अच्छा ठीक है, पढ़ दिया जाय माननीय मंत्री, लेकिन निकालने का प्रयास कीजिये, इसको देखवा लीजिये, यहाँ आया हुआ है हमारे पास ।

श्री अमरजीत कुशवाहा : हम जेल से आए है, हम जेल से आते हैं थोड़ी सी दिक्कत रहती है।

अध्यक्ष : अच्छा ठीक है । माननीय मंत्री, शिक्षा विभाग । पी.ए. रहता है न ?

श्री अमरजीत कुशवाहा : रहता है वह भी लेट से उसकी बहाली हुई है ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, शिक्षा विभाग ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि प्रश्नगत महाविद्यालय के प्रबंधन एवं प्राचार्य के बीच विवाद (न्यायवाद सहित) रहने के कारण शासी निकाय/प्रबंधन समिति का निबंधन बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से नहीं होने के कारण वर्ष 2008 से 2013 की अवधि के लिए अनुदान नहीं दिया जा सका ।

उक्त विवाद के समाधान के उपरान्त बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के पत्रांक 1595 दिनाँक 14–09–2019 के द्वारा प्रश्नगत महाविद्यालय के शासी निकाय/प्रबंधन समिति का निबंधन किया जा चुका है । साथ ही प्रश्नगत महाविद्यालय को सत्र 2012–2014 तथा 2013–2015 का भुगतान किया जा चुका है ।

विभाग द्वारा बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को इसी वित्तीय वर्ष में 842 करोड़ रुपये उपलब्ध करा दिया जा रहा है । जिसके तहत इन सब का भुगतान किया जायेगा ।

श्री अमरजीत कुशवाहा : धन्यवाद सर ।

तारांकित प्रश्न संख्या-1366 (श्री अजीत कुमार सिंह,क्षेत्र सं0 201-डुमरांव)

अध्यक्ष : जवाब इनका देखिये तो उत्तर तो संलग्न है ।

श्री अजीत कुमार सिंह : मेरे पास नहीं है ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, पढ़ दिया जाय । हमलोग उत्तर ऑनलाईन निकाले हैं ।

श्री अजीत कुमार सिंह : ऑनलाईन नहीं आया है ।

अध्यक्ष : ठीक है, पढ़ देते हैं ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि राज्य सरकार की वर्तमान नीति के अनुसार सिर्फ उन्हीं अनुमंडलों में सरकारी डिग्री महाविद्यालय स्थापित करने की योजना है जहाँ पूर्व से कोई अंगीभूत डिग्री महाविद्यालय संचालित नहीं है । बक्सर जिले का नावानगर प्रखण्ड डुमराँव अनुमण्डल के क्षेत्रान्तर्गत हैं, जहाँ डी0के0कॉलेज, डुमराँव पूर्व से अंगीभूत महाविद्यालय के रुप में संचालित है ।

अतः बक्सर जिले के नावानगर प्रखण्ड में डिग्री महाविद्यालय खोलने की तत्काल कोई योजना नहीं है ।

अध्यक्ष : अब तो उत्तर स्पष्ट है कि जहाँ है वहाँ नहीं खोलना है ।

श्री अजीत कुमार सिंह : उत्तर स्पष्ट है लेकिन एक लगातार उठता रहा है सिर्फ मेरा नहीं बल्कि पूरे हाउस इसलिए मेरा आपके माध्यम से आग्रह है कि कम से कम हाउस की मांग को ध्यान में रखकर प्रखंड स्तर पर एक मेडिकल कॉलेज खोला जाय ।

तारांकित प्रश्न संख्या 1367-श्री संदीप सौरभ (क्षेत्र सं0-190 पालीगंज)

(लिखित उत्तर)

श्री संतोष कुमार सुमन, मंत्री : महोदय, 1- आंशिक स्वीकारात्मक है । वस्तुस्थिति यह है कि पटना जिलान्तर्गत पालीगंज अनुमंडल में अनुसूचित जाति बालक छात्रावास वर्त्तमान में संचालित नहीं है ।

पालीगंज अनुमंडल में अनुसूचित जाति के छात्रों की आवासन क्षमता की समीक्षा करने के उपरान्त भवन निर्माण विभाग से तकनीकी अनुमोदित प्राक्कलन प्राप्त होने पर अग्रेतर कार्रवाई की जाएगी ।

श्री संदीप सौरभ : अध्यक्ष महोदय, उत्तर यहाँ पर है, पूरक सवाल पूछता हूँ । सवाल हमने किया था कि पालीगंज में जो दलित छात्रावास है उसकी स्थिति खराब है यहाँ पर जवाब है कि पालीगंज अनुमंडल में अनुसूचित बालक छात्रावास वर्तमान में संचालित नहीं है । 15 साल से ज्यादा समय हो गए होंगे उस हाई स्कूल के अंदर जो एक छात्रावास था उसकी हालत बहुत बदत्तर है लेकिन संचालित

जाहिर सी बात है नहीं है तो उस भवन का निर्माण कब तक होगा और उसका संचालन कब से होगा यह मैं जानना चाहता हूँ ?

श्री संतोष कुमार सुमन, मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को धन्यवाद देना चाहता हूं कि हमारे संज्ञान में लाए हैं और माननीय सदस्य के क्वेश्चन के उपरांत मैंने सारी जानकारी ली है और जिलाधिकारी, पटना को सूचित कर दिया है और उसके उन्नयन के लिए और भवन निर्माण के माध्यम से प्रस्ताव लाने के लिए जितना जल्द प्रस्ताव आयेगा, विभाग उस पर काम करने की चेष्टा करेगा ।

अध्यक्ष : ठीक है ।

श्री संदीप सौरभ : हाई स्कूल से कई बार प्रस्ताव गया हुआ है उसका एक लेटर मेरे पास आया था, उसी से हमने प्रश्न बनाया है तो सरकार के पास प्रस्ताव स्कूल की तरफ से पहले से ही गया हुआ है, अब नया प्रस्ताव किससे चाहिए ?

अध्यक्ष : देखवा लीजिये ।

श्री संतोष कुमार सुमन, मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रस्ताव एक आया था प्रखण्ड विकास पदाधिकारी के माध्यम से कि जीर्ण शीर्ण अवस्था में है उसका प्रस्ताव आया था और प्रस्ताव आते ही हमने उसको आगे कर दिया है । मैं आपको सूचना में देना चाहता हूँ कि पटना में 8 छात्रावास संचालित हैं और मुझे खुशी होगी कि आपने इस तरह के अनुसूचित जाति के अनुसूचित जनजाति के छात्र छात्राओं के लिए आपने सवाल किया है बहुत जल्द इसका कार्य शुरु किया जायेगा ।

अध्यक्ष : ठीक है ।

तारांकित प्रश्न संख्या 1368- श्री मनोहर प्रसाद सिंह(क्षेत्र सं0-67 मनिहारी)

(अनुपस्थित)

तारांकित प्रश्न संख्या -1369 श्रीमती मीना कुमारी(क्षेत्र सं0-34 बाबूबरही)

श्री आलोक रंजन , मंत्री : महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि मधुबनी जिलान्तर्गत लदनियां प्रखण्ड के जे.सी.के.एल. उच्च विद्यालय खाजेडीह में स्टेडियम निर्माण की स्वीकृति विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 80 दिनांक 17-02-2009 द्वारा दी गयी थी जिसे पुनरीक्षित विभीय स्वीकृत्योदेश संख्या 601 दिनांक 18-02-2017 द्वारा दिया गया है उक्त निर्माण कार्य को शीघ्र पूर्ण कराने हेतु विभागीय पत्रांक 428 दिनॉक 2-03-2021 द्वारा जिला पदाधिकारी, मधुबनी को निर्देश दिया गया है ।

अध्यक्ष : ठीक है ।

श्रीमती मीना कुमारी : कबतक पूर्ण होगा ?

श्री आलोक रंजन, मंत्री : हमने बताया है जिलाधिकारी को हमने 02-03-2021 को पत्र दिया है इसको जल्द से जल्द पूर्ण कराया जायेगा ।

तारांकित प्रश्न संख्या 1370 –श्री पवन कुमार यादव (क्षेत्र सं0155 कहलगांव)

अध्यक्ष : पूरक पूछ लीजिये उत्तर संलग्न है ।

श्री पवन कुमार यादवः नहीं आया है सर, निकला नहीं है ।

अध्यक्ष : आप निकालने का प्रयास नहीं किए हैं उत्तर यहॉ आया हुआ है । माननीय मंत्री ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : महोदय, यह भी कुछ उसी तरह का मामला है अनुमण्डल वाला । राज्य सरकार की वर्तमान नीति है कि सिर्फ उसी अनुमण्डल में खोला जाय जहॉ पर कोई दूसरा महाविद्यालय नहीं है और भागलपुर जिलान्तर्गत कहलगांव अनुमण्डल में पूर्व से एस.एस.वी. कॉलेज कहलगांव अंगीभूत महाविद्यालय के रुप मे संचालित है जहॉ सह शिक्षा की व्यवस्था है । अतः भागलपुर जिलान्तर्गत कहलगांव में महिला कॉलेज खोलने की कोई योजना तत्काल विचाराधीन नहीं है ।

अध्यक्ष : उत्तर पहले भी आ चुका है ।

श्री पवन कुमार यादव : महोदय, बहुत ज्यादा संख्या में बच्चा वहॉ है 6600 बच्चा हर साल वहां पास करके निकलता है इसलिए महिला कॉलेज बहुत जरुरी है इसलिए विचार किया जाय ।

तारांकित प्रश्न संख्या –1371–श्री संजय कुमार तिवारी उर्फ मुन्ना तिवारी(क्षेत्र सं0–200 बक्सर)

(लिखित उत्तर)

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : उत्तर आंशिक रुप से स्वीकारात्मक है ।

सर्व शिक्षा अभियान योजना (समग्र शिक्षा अभियान योजना) अन्तर्गत जिले में स्थानीय व्यक्तियों से उत्प्रेरक के रुप में विद्यालय शिक्षा समिति के सदस्यों, पंचायत प्रतिनिधियों तथा समुदाय के अन्य सदस्यों को सर्व शिक्षा अभियान योजना (समग्र शिक्षा अभियान योजना) से संबंधित कार्यों के प्रति प्रेरित करने हेतु उन्मुखीकरण एवं प्रशिक्षण के लिए अस्थायी तौर पर आवश्यकतानुसार ली जाती है ।

वैश्विक महामारी कोविड–19 के प्रभाव को देखते हुए वित्तीय वर्ष 2020–21 में e-content के माध्यम से फिल्म दिखाकर प्रशिक्षण कराने का निर्णय लिया गया है । उक्त प्रशिक्षण के आरम्भ के समय विद्यालय बंद अथवा आंशिक रुप से बंद थे । उस समय शिक्षकों के पास कोई शैक्षणिक कार्य नहीं था। अतः उनकी सेवाओं का उपयोग इस प्रशिक्षण में लिया गया है ।

भविष्य में कोविड-19 की स्थिति सामान्य होने पर उत्प्रेरकों के माध्यम से आवश्यकता आधारित प्रशिक्षण कार्य लिया जा सकेगा ।

श्री संजय कुमाार तिवारी उर्फ मुन्ना तिवारी : उत्तर मुद्रित है महोदय, लेकिन कोविड का हवाला दिया गया है अब तो वैक्सिन आ गया तो सरकार कबतक उन लोगों को रखेगी जो भुखमरी की कगार पर है महोदय ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : महोदय, कोविड का हवाला इसलिए नहीं दिया गया कि कोविड के कारण बंद हुआ उसमें कहा ये गया है कि उस समय कोविड में विद्यालय बंद थे, शिक्षक विद्यालय नहीं जा रहे थे इसलिए उस बीच में शिक्षकों से ही यह काम लिया जा रहा था उत्प्रेरक का अब विद्यालय फिर से खुल गए हैं और शिक्षक विद्यालय जायेंगे ।

क्रमशः

टर्न-7/पुलकित-अभिनीत/09.03.2021

..क्रमशः..

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्रीः तो स्वाभाविक रूप से पहले जो उत्प्रेरक काम करते थे उनका काम शुरू हो जायेगा ।

अध्यक्षः अब प्रश्नोत्तर काल समाप्त हुआ...

(व्यवधान)

श्री संजय कुमार तिवारी उर्फ मुन्ना तिवारीः महोदय, दिया गया है कि भविष्य में कोविड- 19 की स्थिति सामान्य होने पर उत्प्रेरकों के माध्यम से प्रशिक्षण का कार्य लिया जा सकेगा । महोदय, कब लिया जा सकेगा ?

अध्यक्षः सामान्य होने पर । अब प्रश्नोत्तर काल समाप्त हुआ ।

(व्यवधान)

हां तो सामान्य की स्थिति बढ़ गयी है ।

(व्यवधान)

श्री संजय कुमार तिवारी उर्फ मुन्ना तिवारीः महोदय, सरकार बता दे कब तक ?

अध्यक्षः जिन प्रश्नों के उत्तर तैयार हों, उन्हें सदन पटल पर रख दिये जायं ।

माननीय सदस्यगण, आज कला संस्कृति एवं युवा विभाग 100 परसेंट, समाज कल्याण विभाग 100 परसेंट, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग 75 परसेंट, खान एवं भूतत्व विभाग 100 परसेंट, विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग 100 परसेंट, परिवहन विभाग 100 परसेंट, शिक्षा विभाग 72 परसेंट तथा मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग 100 परसेंट, काफी अच्छा है ।

अब शून्यकाल लिये जायेंगे ।

(व्यवधान)

श्री मुकेश कुमार रौशनः महोदय, शेखपुरा में सिविल सर्जन की बहाली की गयी है, पदस्थापित किया गया है, जो कि मृत डॉक्टर हैं और उनकी पोस्टिंग की गयी है । महोदय, इसकी जांच करायी जाय । स्वास्थ्य व्यवस्था का यह हाल है कि डॉक्टर लाचार है, अस्पताल बीमार है और मरीज बदहाल है ।

अध्यक्षः श्री रामचन्द्र पासवान ।

(व्यवधान)

श्री संजय सरावगीः अध्यक्ष महोदय, मेरा एक नम्बर में है...

(व्यवधान)

श्री अजीत शर्माः महोदय, पहले भी हमने बोला था ।

अध्यक्षः अगर दस लोग बोलेंगे तो हम कैसे सुनेंगे । पहले सब बैठ जाइये, एक व्यक्ति ही बोलिये, व्यक्तिगत शून्यकाल नहीं पढ़े जायेंगे ।

(व्यवधान)

आपके दलीय नेता खड़े हैं, उनका सम्मान तो करिये ।

श्री अजीत शर्माः अध्यक्ष महोदय, मैंने पहले भी यह बात, आपसे आग्रह की थी इसको संज्ञान में लेकर आदेश करें कि वो कैसे.....

अध्यक्षः ठीक है, सरकार के संज्ञान में आप दे दिए हैं ?

श्री अजीत शर्माः महोदय, उस पर कार्रवाई, मृत डॉक्टर की पोस्टिंग हुई है, जो अधिकारी, दोषी है उस पर कार्रवाई हो ।

अध्यक्षः ठीक है, अब बैठ जाइये ।

शून्यकाल

श्री राम चंद्र प्रसादः अध्यक्ष महोदय, दरभंगा जिला के अंतर्गत हायाघाट प्रखंड में आनन्दपुर उच्च विद्यालय के खेल मैदान में अशोक पेपर मिल थाना खुलने से विद्यार्थियों को खेलने में अत्यधिक परेशानी होती है । सरकार से अविलम्ब थाना को हस्तांतरित कराने की मांग करता हूं ।

श्री संजय सरावगीः अध्यक्ष महोदय ।

अध्यक्षः संजय सरावगी जी आपका क्या विषय है ? पढ़िये इस तरह से आगे रहेगा तो शून्यकाल मत डालियेगा ।

श्री संजय सरावगीः अध्यक्ष महोदय, दरभंगा, 8 मार्च बीती रात को दरभंगा नगर थाना अंतर्गत शिवाजी नगर में रात्रि 9 बजे व्यवसायी से लूट की घटना में अपराधियों की गोली से रवि साह नामक एक युवक की मौत हो गई, अविलंब कांड का उद्‌भेदन एवं मृतक के परिजनों को मुआवजा की मांग करता हूं ।

श्री महानंद सिंहः अध्यक्ष महोदय, अरवल वासिलपुर मुहल्ला के सैकड़ों एकड़ जमीन में खेती करने के लिए पटना मुख्य नहर पर पुल नहीं होने से घूम कर 3 किलोमीटर दूरी तय कर जाना पड़ता है, पुल निर्माण की मांग करता हूं ।

श्री जय प्रकाश यादवः अध्यक्ष महोदय, अररिया जिला के नरपतगंज प्रखंड अंतर्गत भगही पंचायत के श्यामनगर गांव स्थित कजरा नदी पर बना रींग बांध विगत कई वर्षों से बाढ़ में क्षतिग्रस्त हो जाने के कारण बरसात के समय गांव में पानी भरा रहता है । उक्त रींग बांध की मरम्मति की मांग सदन के माध्यम से करता हूँ ।

अध्यक्षः माननीय सदस्यगण, बैठ जायं । शून्यकाल में लोग बाहर जाने की प्रवृत्ति को रोकें। आज 57 शून्यकाल हैं, इसलिए माननीय सदस्यगण जल्दी-जल्दी पढ़ें ।

श्री राकेश कुमार रौशनः अध्यक्ष महोदय, नालंदा जिला के एकंगर सराय प्रखंड के कोरथू गांव एवं छोटे-छोटे दो टोला फल्गू नदी के उस पार बसा हुआ है, जिसकी आबादी एक से डेढ़ हजार है, पुल के अभाव में प्रखंड एवं जिला मुख्यालय आने जाने में कठिनाई हो रही है ।

अतः मैं कोरथू गांव के समीप फल्गू नदी में पुल बनाने हेतु मांग करता हूँ ।

श्री मनोज मंजिलः अध्यक्ष महोदय, बिहार सरकार द्वारा वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय, आरा की 25 एकड़ जमीन स्वास्थ्य विभाग को देने से विश्वविद्यालय की यू0जी0सी0 की मान्यता पर संकट बढ़ गया है । मैं सदन के माध्यम से उक्त जमीन को वापस करने की मांग करता हूँ ।

(व्यवधान)

अध्यक्षः यह उचित नहीं है । शून्यकाल में आप बैठ जाइये ।

श्रीमती मीना कुमारीः अध्यक्ष महोदय, मधुबनी जिलान्तर्गत बाबूबरही विधान सभा क्षेत्र के लदनियां प्रखण्ड के पिपराही लदनियां, तेनुआही, जयनगर होते हुए पटना तक परिवहन विभाग द्वारा बस परिचालन की सुविधा नहीं है ।

अतः सरकार से उक्त स्थान से पटना तक जनहित में बस की परिचालन की मांग करती हूँ ।

श्री समीर कुमार महासेठः अध्यक्ष महोदय, मधुबनी जिला का सूता मिल, पंडौल बंद पड़ा हुआ है । रोजगार के लिये लोगों का पलायन हो रहा है । बेरोजगारों में हाहाकार है । बंद पड़े सूता मिल, पंडौल को चालू किया जाय ।

श्रीमती शालिनी मिश्राः अध्यक्ष महोदय, हाजीपुर-सुगौली रेल लाईन हेतु केसरिया विधान सभा क्षेत्र के केसरिया नगर पंचायत, बथना, लोहरगामा ग्राम पंचायत सहित दर्जनों ग्रामों के किसानों की अर्जित जमीन का मुआवजा भुगतान अभी तक नहीं किया गया है ।

अतः अविलम्ब मुआवजा का भुगतान कराया जाय ।

श्री संजय कुमार तिवारी उर्फ मुन्ना तिवारीः अध्यक्ष महोदय, बिहार राज्य के उच्च माध्यमिक विद्यालय में कार्यरत प्लस टू अतिथि शिक्षकों को 2018 में विज्ञापन के माध्यम से शिक्षा विभाग बिहार सरकार के द्वारा नियुक्ति की गई । इसमें 4203 कार्यरत अतिथि शिक्षकों की शैक्षणिक योग्यता स्नातकोत्तर एवं बी0एड0 उत्तीर्ण है, उन अतिथि शिक्षकों को स्थायी किया जा सकता है ।

अतः सभी अहर्त्ता को पूरा करते हुए अतिथि शिक्षकों की मांग को पूरा किया जाय ।

श्री मिथिलेश कुमारः माननीय अध्यक्ष महोदय, विगत 08.03.2021 को सीतामढ़ी के शिक्षक सुनील कुमार को छुरा से घायल कर दिया गया तथा रीगा के व्यवसायी दीपक कुमार की दूकान में डकैती की घटना की गई । सीतामढ़ी जिलावासी कैसे जीवन जी सके ? सरकार अपराध पर गंभीर हो ।

श्री विजेन्द्र चौधरीः अध्यक्ष महोदय, मुजफ्फरपुर जिलान्तर्गत मुजफ्फरपुर के वार्ड न0-1, महापौर निवास के सामने से दिनांक 16.02.2021 को 08:57 बजे पूर्वा0 से सुश्री खुशी कुमारी, पिता श्री राजन साह, जिसकी उम्र मात्र पांच वर्ष है, अभी तक लापता है ।

अतः सरकार से उक्त बच्ची को खोज कर सकुशल लाने हेतु मांग करता हूँ ।

श्री आनन्द शंकर सिंहः अध्यक्ष महोदय, जिला मुख्यालय शिक्षा विभाग का अपना कार्यालय भवन नहीं है । जबकि औरंगाबाद मुख्यालय में भवन के लिए जमीन आवंटित की जा चुकी है ।

अतः सरकार से आग्रह है कि शिक्षा विभाग के कार्यालय के लिए भवन का निर्माण जल्द करावें ।

(व्यवधान)

अध्यक्षः आप जानते हैं कि शून्यकाल समिति भी है और सारे विषय आ रहे हैं । आप लोग पुराने सदस्य हैं । श्री मुहम्मद इजहार असफी ।

श्री मुहम्मद इजहार असफीः अध्यक्ष महोदय, कोचाधामन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को सामुदायिक केन्द्र का दर्जा मिला है परंतु चिकित्सा सुविधा के नाम पर कोई सुधार नहीं है । तकनीशियन नहीं होने के कारण एक्स-रे मशीन भी संचालित नहीं है । मैं सरकार से चिकित्सा सुविधा में सुधार के साथ तकनीशियन की नियुक्ति की मांग करता हूँ।

श्री राजवंशी महतोः अध्यक्ष महोदय, बेगूसराय जिला में मुख्यमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट नल जल योजना के कार्यान्वयन हेतु अनुरक्षकों की बहाली में भाई-भतीजावाद, रिश्वतखोरी एवं अन्य धांधलियों पर आम नागरिकों के हितार्थ प्रतिबंध लगाया जाय ।

श्री मुकेश कुमार यादवः अध्यक्ष महोदय, सीतामढ़ी जिला अन्तर्गत 609 कोटि के 64 मदरसा शिक्षकों का वेतन 17 माह से बंद है । वेतन नहीं मिलने से शिक्षकों में भुखमरी की समस्या उत्पन्न हो गयी है । मदरसा तालिमें निसवां बेलाखाप के शिक्षक मो0 खालिद अशरफ की मृत्यु हो चुकी है, जांच कराकर वेतन भुगतान कराई जाय ।

श्री ललित नारायण मंडलः अध्यक्ष महोदय, भागलपुर जिले के सुलतानगंज प्रखंड के सुलतानगंज बाजार के बीच में बंद पड़े महिला अस्पताल को यथा शीघ्र पुनः चालू करवाया जाय । यह अति आवश्यक है ।

टर्न-8/हेमन्त-धिरेन्द्र/09.03.2021

श्री पवन कुमार जायसवाल : अध्यक्ष महोदय, राज्य में आंगनबाड़ी केंद्रों पर टेक होम(टी.एच.आर.) अभिभावकों से ओ.टी.पी. पूछकर करना, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के मानक के विरुद्ध है ।

मैं सरकार से टेक होम (टी.एच.आर.) का संपादन पुरानी व्यवस्था या डी.बी.टी. से करने, सेविका के खराब सरकारी मोबाईल की जगह नया देने, सेविका को 15 हजार एवं सहायिका को 7 हजार मानदेय बढ़ाकर देने की मांग करता हूं ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : आप बैठ जाइये, दूसरे की चिंता करिये । आप बैठ जाइये, पवन जी ।

(व्यवधान)

जो समय बर्बाद करेंगे, उन पर हम गंभीरता से विचार करेंगे । बैठ जाइये ।

श्री आलोक कुमार मेहता : अध्यक्ष महोदय, पंचायती राज अधिनियम 2004 के अनुसार जिला पुलिस अधीक्षक के आदेशानुसार ओ.पी., थानाध्यक्षों के निर्देशानुसार ग्रामरक्षादल/पुलिसमित्र संध्याप्रहरी रात्रिप्रहरी के रूप में, राष्ट्रीय त्योहारों एवं आपदा के समय शांति सहयोगी बनकर बिना भत्ता/मानदेय के कार्य करते रहे हैं । मैं सरकार से मांग करता हूं कि इन्हें पारिश्रमिक दिया जाय ।

श्री पवन कुमार यादव : माननीय अध्यक्ष महोदय, भागलपुर जिलान्तर्गत सन्हौला प्रखंड के सनहौला-जगदीशपुर पथ (18.75 किलोमीटर) का चौड़ीकरण कार्य स्वीकृति के अभाव में कार्य लंबित है ।

अतः सरकार से उक्त सड़क के निर्माण की स्वीकृति हेतु मांग करता हूं।

श्री ललन कुमार : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं भागलपुर जिलान्तर्गत विक्रमशिला में प्रस्तावित विक्रमशिला केंद्रीय विश्वविद्यालय का निर्माण कार्य सरकार से यथाशीघ्र प्रारंभ करने की मांग करता हूं ।

अध्यक्ष : धन्यवाद । आपका 18 शब्दों में ही है ।

श्री विद्यासागर केशरी : अध्यक्ष महोदय, अररिया जिलान्तर्गत नगर परिषद् फारबिसगंज के ज्योति मोड़ रेलवे क्रॉसिंग एवं नगर पंचायत जोगवनी के उच्च विद्यालय-साहू धर्मशाला के सामने रेलवे क्रॉसिंग के रेल पैदल पार पुल नहीं होने से छात्र-छात्राओं सहित आमजन को भारी परेशानी झेलनी पड़ती है । उक्त दोनों स्थानों पर फुट ओवरब्रिज निर्माण की मांग सदन से करता हूं ।

श्री विजय कुमार खेमका : अध्यक्ष महोदय, बिहार-झारखंड राज्य में टू-व्हीलर और फोर व्हीलर के रजिस्ट्रेशन शुल्क में असमानता रहने के कारण यहां के खरीददार पड़ोसी राज्य से गाड़ी खरीदतते हैं जिससे राज्य को राजस्व की क्षति होती है ।

अतः मैं सरकार से गाड़ी का रजिस्ट्रेशन शुल्क पड़ोसी राज्य के बराबर करने की मांग करता हूं ।

अध्यक्ष : आपको भी धन्यवाद, आपका भी पन्द्रह शब्दों में है । बोलिए ।

श्री संजय कुमार गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, सीतामढ़ी जिलान्तर्गत बेलसण्ड अनुमंडल में लगभग तीन वर्षों से डी.सी.एल.आर. का पद रिक्त है । जनहित में तत्काल पदस्थापन करावें ।

श्री मिश्री लाल यादव : अध्यक्ष महोदय, दरभंगा जिला के केवटी प्रखंड के ग्राम केवटी निवासी स्व0 श्री नारायण लाल दास दरभंगा के प्रथम लोकसभा सदस्य निर्वाचित हुए थे । उनकी प्रतिमा प्रखंड मुख्यालय केवटी के परिसर में लगाने की जनभावना है ।

अतः स्व0 श्री नारायण लाल दास की आदमकद प्रतिमा लगाने की सरकार से मांग करता हूं ।

श्री अजय कुमार : महोदय, समस्तीपुर जिलान्तर्गत दलसिंहसराय में चल रही थोक सब्जी मंडी लगभग पांच प्रखंडों के लिए वरदान है । सरकारी आदेशानुसार खानगी जमीन से बाजार समिति प्रांगण में आया, जिसे पुनः हटाने की बात की जा रही है ।

मैं सरकार से उक्त सब्जीमंडी को वर्तमान जगह ही स्थायीकरण एवं मानवोचित सुविधा उपलब्ध कराने की मांग करता हूं ।

श्री मोहम्मद अनजार नईमी : मेरे विधान सभा क्षेत्र 52 बहादुरगंज अन्तर्गत कुम्हारटोली से चुनीमारी जाने वाली सड़क में नदी में पुल नहीं होने के कारण वर्षा ऋतु में यातायात ठप हो जाता है ।

मैं पुल निर्माण विभाग से मांग करता हूं कि नदी में पुल निर्माण कर यातायात साधन बहाल किया जाय ।

श्री विनय कुमार : अध्यक्ष महोदय, गरूआ विधान सभा अंतर्गत परैया प्रखंड के गया-परैया पथ से प्रभुआ, विशुनपुर, रामपुर, टड़वा, कजरी होते हुए मेडिकल-कपस्या जाने वाली रोड दस वर्षों से जर्जर हालत में है । इसे जल्द बनवाने की मांग करता हूं ।

श्री मुरारी मोहन झा : अध्यक्ष महोदय, दरभंगा जिलान्तर्गत सिंधवाड़ा प्रखंड में महादलित मुहल्ला माधोपुर बस्तवाड़ा वार्ड-07 में दिलिप पासवान के घर से मुख्य सड़क तक समाज की मदद से रास्ता बनाया गया है, सरकार आमजनों के हित में इस सड़क को खरंजा कर पक्की सड़क बनाने की कृपा करे ।

श्री गोपाल रविदास : अध्यक्ष महोदय, ग्राम-रसुलपुर, प्रखण्ड-पुनपुन मोरहर नदी पर पुल पुरानी और जर्जर स्थिति में है । नये पुल का निर्माण कराया जाय ।

अध्यक्ष : धन्यवाद । आपका 18 शब्दों में है ।

श्री श्यामबाबू प्रसाद यादव : अध्यक्ष महोदय, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के सभी धाराओं का अक्षरसः अनुपालन करते हुए दिव्यांगों को सभी बुनियादी सुविधायें, अधिकार, प्रतिनिधित्व के साथ-साथ उन्हें सरकारी एवं निजी सेक्टर में रोजगार सुनिश्चित कराने हेतु सरकार से मांग करता हूँ ।

श्री भाई वीरेन्द्र : अध्यक्ष महोदय, पटना जिलान्तर्गत बिहटा प्रखण्ड स्थित पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय के तहत संचालित जी0जे0 महाविद्यालय, रामबाग, बिहटा में पी0जी0 की पढ़ाई प्रारंभ करावें ।

अध्यक्ष : धन्यवाद । आपका भी 21 ही शब्दों में है ।

श्री रामबली सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, जहानाबाद जिला में एक भी ट्रॉमा सेंटर नहीं है । जिलान्तर्गत एकमात्र सदर अस्पताल में आई0सी0यू0 की खिड़कियां टूटी हुई है । बढ़ती सड़क दुर्घटना को देखते हुए साहोबिगहा, बंधुगंज, हाटी और झुनाठी में ट्रॉमा सेंटर खोलने तथा आई0सी0यू0 को ठीक कराने का मांग करता हूँ ।

अध्यक्ष : व्यक्तिगत नाम की सूचना को नहीं पढ़ेंगे ।

श्री अरूण सिंह : अध्यक्ष महोदय, काराकाट विधानसभा अंतर्गत सकला बाजार पर शिवजी साह की दूकान है । मिठाई खरीदने में मोलभाव का बहाना बनाकर अपराधियों ने दिन-दहाड़े गोलियां चलाई, जिसमें रौशन साह की मौत व अरूण साह घायल हो गये ।

मैं अपराधियों की गिरफ्तारी तथा पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई सहित मुआवजे की मांग करता हूँ ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : आपको उनकी चिंता नहीं है । बैठ जाइये । सारे सदस्य अपने-अपने मामलों को गंभीरता से बोल रहे हैं।

श्री संदीप सौरभ : अध्यक्ष महोदय, पटना पी0एम0सी0एच0 के इमरजेंसी वार्ड में मरीजों का तत्काल भर्ती कर ईलाज शुरू करने का समुचित इंतजाम नहीं है । बेड और डॉक्टर की कमी है । सवाल उठाने पर गार्डस द्वारा परिजनों के साथ मारपीट के मामले सामने आये हैं । तत्काल कार्रवाई की मांग करता हूँ ।

श्री अरूण शंकर प्रसाद : अध्यक्ष महोदय, राज्य के सभी ग्राम पंचायतों में वार्ड सदस्यों के योजनाओं का क्रियान्वयन वार्ड सचिव द्वारा किया जाता है । परन्तु वार्ड सचिव आर्थिक रूप से परेशान है । वार्ड सचिवों को सरकार द्वारा न्यूनतम मजदूरी की दर से मानदेय का भुगतान कराने की मांग सरकार से करता हूँ ।

श्री महबूब आलम : अध्यक्ष महोदय, कटिहार जिलान्तर्गत बारसोई प्रखण्ड के मोटबाड़ी घाट में पुल निर्माण की मांग करता हूँ ।

अध्यक्ष : धन्यवाद । आपने तो 11 शब्द में ही गागर में सागर भर दिया ।

श्री विनय बिहारी : अध्यक्ष महोदय, योगापट्टी अंचल स्थित नेशनल हाइवे पर अवस्थित थाना शनीचरी के सिपाही खपड़ैल खंडहर जैसे मकान में रहते हैं । सरकार आवासन की व्यवस्था करे ।

अध्यक्ष : आपका 19 शब्दों में है ।

श्रीमती भागीरथी देवी : अध्यक्ष महोदय, बेतिया जिलान्तर्गत प्रखण्ड रामनगर के ग्राम बलूवा बखराहा के सिंगाही बेल बाग तक पक्की पथ बन जाने के बाद जगह-जगह पुलिया नहीं होने से आमजन को काफी कठिनाइयां हो रही हैं । मैं मांग करती हूँ कि पथ में पुलिया बनाई जाय ।

अध्यक्ष : पथ पर पुलिया बनायी जाय, यही है न ।

श्री ऋषि कुमार : अध्यक्ष महोदय, औरंगाबाद जिलान्तर्गत जिला सूचना पदाधिकारी के पद पर छः वर्ष से कार्यरत है ।

अतः मैं प्रभारी मंत्री जी से आग्रह करता हूँ कि स्थानांतरण अतिशीघ्र करायें ।

अध्यक्ष : यह व्यक्तिगत सूचना है । आगे से ध्यान रखें । व्यक्तिगत सूचनाओं को आगे से नहीं पढ़वायेंगे ।

श्री राम विशुन सिंह : अध्यक्ष महोदय, भोजपुर जिलान्तर्गत जगदीशपुर अनुमंडल में एक भी डिग्री कॉलेज नहीं है । जगदीशपुर प्रखंड के मौजा रंगरूआ थाना नं0-237 में सरकारी जमीन लगभग 10 एकड़ खाली है, उसी पर बालिका डिग्री कॉलेज खोलवाने की मांग सदन से करता हूँ ।

श्री अवध विहारी चौधरी : अध्यक्ष महोदय, सीवान शहर में सब्जी मंडी कोरोना काल में बंद है। सब्जी मंडी को दारोगा राय कॉलेज एवं पथ निर्माण रोड पर लगाया जा रहा है, जिससे जाम लगता है । कॉलेज का पठन-पाठन बाधित होता है । सब्जी मंडी हेतु अन्यत्र स्थान मुहैया कराने हेतु सरकार का ध्यान आकृष्ट करता हूँ ।

टर्न-9/सुरज-संगीता/09.03.2021

श्री विजय कुमार : अध्यक्ष महोदय, शेखपुरा जिलान्तर्गत पटेल चौक रेलवे क्रासिंग स्थल पर भीड़-भाड़ एवं बड़ी दुर्घटना की समस्या को रोकने हेतु रेल पथ पर ऊपरी पथ (फ्लाई ओवर ब्रिज) पुल का निर्माण जनहित में शीघ्र करने की माँग करता हूं ।

श्रीमती वीणा सिंह : अध्यक्ष महोदय, वैशाली जिला के जन्दाहा बाजार में सड़क चौड़ीकरण करने में नालों को तोड़ दिए जाने की वजह से बरसात के दिनों में 1 फीट तक पानी का जमाव रहता है, जिससे सड़क पर चलना मुश्किल होता है, जिस वजह से लोगों में असंतोष व्यक्त है, इसलिए पानी की निकासी के लिए नये नालों का निर्माण कर बाया नदी में मिलाया जाये, बाजार के पास से ही बाया नदी गुजरती है।

श्री विनय कुमार चौधरी : अध्यक्ष महोदय, दरभंगा जिला से गुजरने वाली S.H.-17, S.H.-56 और S.H.-80 को N.H.-57 से जोड़ने वाली धरोड़ा सकरीपथ पर गाड़ियों का दबाव बढ़ गया है । इसका चौड़ीकरण किया जाय ।

श्री अजीत कुमार सिंह : अध्यक्ष महोदय, बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित दरोगा भर्ती परीक्षा में व्यापक धांधली की बात सामने आ रही है ।

अतः सदन से ये मांग करता हूं कि बिहार लोक सेवा आयोग की तर्ज पर दरोगा अभ्यर्थियों की उत्तर पुस्तिका को सार्वजनिक किया जाय ।

श्री रणविजय साहू : अध्यक्ष महोदय, समस्तीपुर जिला के मोरवा एवं पटोरी प्रखण्ड के डेढ़ दर्जन पंचायत जैसे-चकपहाड़, लरूआ, दरबा, चकसलेम, सिरदिलपुर, जोड़पुरा, मर्चा आदि चौर में कई माह तक जलजमाव बना रहता है, मैं ऐसे क्षेत्रों में जल-निकासी की व्यवस्था करने की मांग करता हूं, ताकि उन खेतों में खेती हो सके ।

श्री सुधाकर सिंह : अध्यक्ष महोदय, कैमूर जिला में दुर्गावती थाना अन्तर्गत दिनांक-06.03.2021 की रात डिलखिली टोल प्लाजा पर ट्रक लदे बालू माफियाओं ने टोल प्लाजा कर्मी के साथ मारपीट कर वगैर टोल टैक्स दिए गाड़ी पार किए, घटना की उच्च स्तरीय जांच कर बालू माफियाओं पर कार्रवाई करें ।

श्री कुमार कृष्ण मोहन उर्फ सुदय यादव : अध्यक्ष महोदय, जहानाबाद जिलान्तर्गत अंचल रतनी फरीदपुर के मौजा सेसम्वा थाना नं0-78, खाता नं0-358, प्लॉट नं0-2912 आम रास्ता जिसका दबंगों द्वारा अतिक्रमण कर बन्द कर दिया गया है । अतिक्रमण मुक्त कर आम रास्ता चालू करावें ।

श्री मोहम्मद नेहालउद्दीन : अध्यक्ष महोदय, औरंगाबाद जिला अन्तर्गत रफिगंज प्रखंड के रफिगंज के पंचायत कजपा के ग्राम-सैफगंज और बराही बाजार के सामने बड़की नहर में पुल का निर्माण करावें ।

श्री कुमार शैलेन्द्र : अध्यक्ष महोदय, भागलपुर के बिहपुर प्रखंड में हरिओ और गाविंदपुर मुशहरी के बीच में कोशीधार पर 2011 से ही पुल का निर्माण हो रहा है, लेकिन पुल का निर्माण अभी तक नहीं हो पाया है ।

अतएव सरकार से जल्द से जल्द पुल निर्माण करवाने की मांग करता हूं।

श्री सुदामा प्रसाद : अध्यक्ष महोदय, भोजपुर जिला के सहार, तरारी व पीरो के प्रखण्ड अस्पतालों में कुत्ता-सियार काटने पर लगने वाले इंजेक्शन की आपूर्ति नहीं होने से गरीबों की भारी मुसीबत है । सरकार शीघ्रातिशीघ्र पर्याप्त इंजेक्शन की आपूर्ति सुनिश्चित करावे ।

श्री अमरजीत कुशवाहा : अध्यक्ष महोदय, सीवान जिला के मौरवा प्रखंड की लड़कियां खेल के क्षेत्र में देश-विदेश में नाम रोशन कर रही हैं । बावजूद मैरवा में खेल स्टेडियम नहीं है । मैरवा में स्टेडियम का निर्माण कराने की मांग करता हूं ।

श्री वीरेन्द्र प्रसाद गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, बंद पड़ी रीगा चीनी मिल क्षेत्र के हजारों किसानों की खेतों में खड़ी सूख रही गन्ना की फसल के मुआवजा देने की मांग सरकार से करता हूं ।

अध्यक्ष : धन्यवाद 21 शब्दों में आपका प्रश्न है ।

श्री अचमित ऋषिदेव : अध्यक्ष महोदय, अररिया जिलान्तर्गत रानीगंज प्रखंड हाँसा पंचायत के ग्राम लक्ष्मीपुर वार्ड नं0-2 में भोला ठाकुर के घर से तिरन मुशहरी जानेवाली पथ में एप्रोच रोड के अभाव में पुल से आवागमन बाधित है । तत्काल मनरेगा से मिट्टी भराकर एप्रोच रोड बनाने के लिए सरकार से मांग करता हूं ।

अध्यक्ष : माइक का इंतजार मत कीजिए बोलते रहिये ।

श्री मो0 इसराईल मंसूरी : अध्यक्ष महोदय, मुजफ्फरपुर जिलान्तर्गत मड़वन प्रखंड के बड़का गांव आसपास नून नदी से जलजमाव के कारण सैकड़ों एकड़ जमीन का फसल की बर्बादी से बचाने हेतु जल निकासी की स्थायी प्रबंधन किया जाय ।

श्री मनोज कुमार यादव : अध्यक्ष महोदय, पूर्वी चम्पारण जिला के प्रखंड कोटवा में एन.एच. 28, पराउबाबा मठ से 495 आरडी पुल होकर कल्याणपुर जाने वाली नहर सड़क को नवनिर्माण कार्य कराने की सदन से मैं मांग करता हूं ।

अध्यक्ष : धन्यवाद, 57 शून्यकाल हुए और जो कम शब्दों में लिखेंगे, प्राथमिकता देंगे । व्यक्तिगत लिखेंगे वह आगे नहीं भी आएगा । अब ध्यानाकर्षण सूचनाएं ली जायेंगी।

श्री ललित कुमार यादव : महोदय, एक महत्वपूर्ण सूचना है । स्वास्थ्य विभाग में डॉक्टर रामनारायण राम जी का देहान्त हो गया, आप ही के बगल के जिला में शेखपुरा में सिविल सर्जन पद पर स्वास्थ्य विभाग में कोरोना काल में जिनकी मौत हो गई, सिविल सर्जन, शेखपुरा उनको पदस्थापित कर दिया गया है । महोदय, यह सरकार के लिए दुर्भाग्य की बात है, जो मरे हुए व्यक्ति को सिविल सर्जन को...

(व्यवधान)

अध्यक्ष : माननीय सदस्य युसुफ सलाहउद्दीन अपनी सूचना को पढ़ें ।

श्री भाई वीरेन्द्र : महोदय, बहुत ही गंभीर मामला है..

अध्यक्ष : यह भी आप ही लोगों का दिया हुआ गंभीर है..

श्री ललित कुमार यादव : ठीक है महोदय, लेकिन इसको देख लीजिए ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : अब ठीक है ।

ध्यानाकर्षण सूचनाएं तथा उसपर सरकारी वक्तव्य

सर्वश्री युसुफ सलाहउद्दीन, मोहम्मद इसराईल मंसूरी एवं अन्य बारह सभासदों से प्राप्त ध्यानाकर्षण सूचना तथा उसपर सरकार [शिक्षा विभाग] की ओर से वक्तव्य ।

श्री युसुफ सलाहउद्दीन : अध्यक्ष महोदय, ''बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड..

(व्यवधान)

अध्यक्ष : अब सुन लीजिए ।

श्री युसुफ सलाहउद्दीन : पटना में अध्यक्ष द्वारा किये जा रहे मनमानी पूर्ण (मदरसा संख्या-107. ..

(व्यवधान)

अध्यक्ष : सरकार गंभीरता से सुन रही है ।

श्री युसुफ सलाहउद्दीन : के गठित प्रथम पक्ष प्रबंध समिति को हटा कर द्वितीय पक्ष को अवैध रूप से गठित कर दिया गया जो गलत है) कार्य, माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों का उल्लंघन...

(व्यवधान)

अध्यक्ष : इन सब चक्करों में कहां आप पड़ गये ? चलिये । हम जिनसे सीख रहे हैं, सीखने के क्रम में ही हैं । चलिये ।

श्री युसुफ सलाहउद्दीन : अपने निकट संबंधी की अवैध बहाली एवं वित्तीय अनियमितता की जांच हेतु शिक्षा विभाग के ज्ञापांक-1105, दिनांक-29.12.2020 द्वारा त्रिस्तरीय समिति का गठन किया गया था, जिसके जांच प्रतिवेदन में दोषी पाए जाने पर भी कोई कार्रवाई नहीं की गई । साथ ही निगरानी विभाग के पुलिस अधीक्षक के पत्रांक-45, दिनांक-11.01.2021 द्वारा प्रधान सचिव, शिक्षा विभाग को जांच हेतु प्रेषित पत्र पर भी अध्यक्ष, बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड के विरूद्ध कार्रवाई नहीं की गई है । इससे राज्य के मदरसों में अराजक स्थिति हो गई है । पठन-पाठन भी प्रभावित हो रहा है ।

अतः अध्यक्ष, बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड के विरूद्ध प्राप्त जांच प्रतिवेदन एवं निगरानी विभाग के पुलिस अधीक्षक के उक्त पत्र पर उचित कार्रवाई करने हेतु हम सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हैं ।''

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, शिक्षा विभाग ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : महोदय, माननीय उच्च न्यायालय, पटना में दायर याचिका संख्या- 23609/2019 अहसन रजा बनाम मदरसा बोर्ड एवं अन्य, अन्य विभिन्न माध्यमों से प्राप्त परिवादों तथा निगरानी विभाग के पत्रांक-118 दिनांक-16.03.2020

के पत्रांक-2648, दिनांक-13.10.2020 द्वारा प्राप्त परिवाद के आलोक में विभागीय ज्ञाप संख्या-1105, दिनांक-29.12.2020 द्वारा बिहार राज्य मदरसा बोर्ड द्वारा किए जा रहे मनमानीपूर्ण रवैये वित्तीय अनियमितता, अवैध नियुक्ति आदि से संबंधित आरोपों की जांच हेतु विभाग द्वारा त्रिसदस्यीय समिति का गठन किया गया है । इस समिति ने एक अंतरिम जांच प्रतिवेदन दिया है, जिसमे तथ्यों एवं साक्ष्यों की पूर्ण जांच नहीं की गई है । अतः यह एक अधूरी एवं अपूर्ण प्रतिवेदन है । विभाग द्वारा समिति को सभी तथ्यों को, जितने आरोप लगाये गए हैं उन सबों की जांच करके विस्तृत जांच प्रतिवेदन देने का निदेश दिया गया है । जांच प्रतिवेदन प्राप्त होने पर तदनुसार नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी ।

टर्न-10/मुकुल-राहुल/09.03.2021

(व्यवधान)

अध्यक्षः माननीय सदस्य, आप बैठ जायं । पहली सूचना किनकी है, पहली सूचना जो इन्होंने अभी पढ़ी है ?

श्री ललित कुमार यादवः अध्यक्ष महोदय, यह युसुफ सलाहउद्दीन जी का है ।

अध्यक्षः तो युसुफ सलाहउद्दीन जी आप पूरक नहीं करेंगे ?

श्री युसुफ सलाहउद्दीनः अध्यक्ष महोदय, नहीं । नेहाल साहब पूछेंगे ।

अध्यक्षः मोहम्मद नेहालउद्दीन जी आप पूछिए ।

श्री मोहम्मद नेहालउद्दीनः माननीय अध्यक्ष महोदय, किसी भी बोर्ड में चेयरमैन का अपना कोई पावर नहीं होता है ।

अध्यक्षः आप डायरेक्ट पूरक करें ।

श्री मोहम्मद नेहालउद्दीनः अध्यक्ष महोदय, उसी से जुड़ा हुआ है । मान्यवर, पूरा बिहार देख रहा है करोड़ों नहीं, पचासों करोड़ों से ज्यादा का घपला का मामला है, इसलिए बड़ी गंभीरतापूर्ण आपसे मेरा आग्रह है कि आप भी इसको गौर से सुनिये ।

अध्यक्षः हम समय से बंधे हैं इसलिए शॉर्ट में बताइये ।

श्री मोहम्मद नेहालउद्दीनः अध्यक्ष महोदय, हम शॉर्ट में ही बता रहे हैं । यह जनवरी, 2019 में इनकी नियुक्ति हुई, जुलाई में इनको चेयरमैन का दर्जा दिया गया इस दरमियान में उनको राज्य मंत्री का कोई दर्जा नहीं था और इन्होंने अपने बेटे को, अपने भांजों को और अपने दामादों को बहाल किया, जो नियमतः गलत है । जितना भी आज तक दो सालों में माननीय मंत्री महोदय, सिर्फ एक बार कोर्ट के आदेश से वर्ष 2020 में उन्होंने मीटिंग बुलाई उसके बाद आज तक कोई मीटिंग नहीं बुलाया, इसीलिए उन्होंने जितनी बार गड़बड़ी की है उसकी जांच के बारे में निगरानी विभाग ने भी कहा था कि इनकी पूरी संपत्ति की जांच कराई जाए और पता लगाया जाए

कि इन्होंने अनियमितता बरती है या नहीं । आज तक इन्होंने कुछ नहीं किया और न ही कोर्ट की बात मानते हैं । माननीय आनरेबल हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि इनके सारे कार्यकलापों पर रोक लगायी जाती है, इसके खिलाफ में एल0पी0ए0 में गये, एल0पी0ए0 ने कहा कि आप, जो भी डेट है एल0पी0ए0 में इनको कोई रिलीफ नहीं मिला और कहा गया कि आप बोर्ड की मीटिंग बुलाकर जो इसका निर्णय होगा, आप उस निर्णय को लेकर फिर वही सिंगल बैंच में जाइयेगा उसी में जो आपका फैसला होगा, वही देंगे । मगर इन्होंने बोर्ड की मीटिंग बुलाई और बोर्ड ने इनके सारे जितने भी फैसले थे उनको रद्द कर दिया उसके बाद भी आज तक मनमानी ढंग से ये करोड़ नहीं, 10 करोड़, महोदय, 18 करोड़ फिक्ड-डिपॉजिट था उसको भी खत्म कर दिया और जितना भी अनुदान वगैरह आता है इन सबका कम से कम पचासों करोड़ रुपया से ऊपर का घपला हुआ है इसलिए हम मांग करते हैं कि तत्काल सरकार उस चेयरमैन को बर्खास्त करे और उस पर निगरानी विभाग से या फिर सदन की समिति बनाकर, आप जिसको भी कहिये उसकी तीन आदमी या पांच आदमी की कमिटी बनाकर उसकी जांच करें, इसलिए क्योंकि पूरे बिहार का यह बहुत बड़ा मामला है और पूरा बिहार इसको देख रहा है । इसलिए माननीय इसको हल्का में न लिया जाए, आपसे आग्रह है कि सरकार इसमें चेतावनी दे।

अध्यक्ष: माननीय मंत्री ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री: अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले हम माननीय सदस्य को और सदन को भी आश्वस्त करना चाहते हैं कि सरकार इस मामले को क्या, किसी भी मामले को हल्के में नहीं लेती है । सरकार जिस भी मामले को लेती है गंभीरता से ही लेती है और इसीलिए इसमें तीन लोगों की कमिटी त्रिस्तरीय जांच समिति का गठन करके सरकार जांच करवा रही है और वैसे भी माननीय सदस्य पुराने हैं, इन्होंने कहा कि विजिलेंस ने इनको कहा है जांच कराने के लिए । यह सदन के लिए सोचने की बात है कि सरकार विजिलेंस को कहती है जांच करने के लिए, विजिलेंस डिपार्टमेंट सरकार को जांच करने के लिए नहीं कहती है सबसे पहली बात । यह सब समझदारी में स्पष्टता होनी चाहिए ।

श्री ललित कुमार यादव: आप बताइये न, आप कहां बता रहे हैं ?

अध्यक्ष: आप इनकी बात सुनिये ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री: हम बता रहे हैं न । अब जो बात कहियेगा, आपको बोलने का मौका आये तो जो बात नहीं बोलना चाहिए वह सब बात बोल जाइये । हमको तो सब बात का संज्ञान, आप ही न कहें कि हम लोगों की बात का गंभीरता से संज्ञान लीजिए।

अध्यक्ष: अब सुनिये, माननीय मंत्री जी के विषय को सुनिये, फिर आप पूरक पूछिये । अभी सुन लीजिए ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री: महोदय, माननीय सदस्यों ने या माननीय नेहाल साहब ने जो पूरक में प्रश्न उठाये हैं उन सभी बातों का हम गंभीरता से संज्ञान लेते हैं, चाहे नियुक्तियों के संबंध में आपने जो कहा कि उन्होंने अपने रिश्तेदारों को नियुक्ति किया है, वित्तीय अनियमितता है या उनकी जो कार्यशैली थी उसके संबंध में जो कोर्ट की टिप्पणी थी, कोर्ट के जो आदेश हैं वह भी हमने देखा है कि उसने सीधा कोर्ट के आदेश में महोदय, वह हमने देखा है कि उसमें सिर्फ कोर्ट ने इनको बोर्ड के बिहाल्फ में जो ये कुछ फैसले लेते थे उसको कोर्ट ने रोका है, इनको चेयरमैन के रूप में काम करने से नहीं रोका है और कोर्ट के ऑर्डर का ऑपरेटिव पार्ट जो है, उसमें यही है कि "The Chairman shall not function and exercise the power of the Madarsa Board." पहली बात चेयरमैन के रूप में उनके काम करने पर रोक नहीं लगी थी, लेकिन कोर्ट कहे अच्छी बात है, न भी कहे अगर सरकार की किसी संस्था में कोई अधिकारी या कोई पदाधिकारी जो उच्च पद पर है, अगर कोई भ्रष्टाचार, वित्तीय अनियमितता या गलत कार्य करता है तो सरकार उसकी जांच कराकर दोषी व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई करना सरकार अपना कर्तव्य समझती है और महोदय, इसी के तहत वह पत्र जिसकी विजिलेंस की बात हो रही है, विजिलेंस में दिया गया था, सीधे सरकार में दिया गया, कोर्ट में भी, इससे संबंधित मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष से संबंधित दो-तीन मामले उच्च न्यायालय में भी चल रहे हैं या जिस आदेश का नेहाल साहब हवाला दे रहे हैं वह एक अंतरिम आदेश है, in the mean while कह कर इतने ऑपरेटिव पार्ट का डायरेक्शन दिया गया है वह भी अभी कोर्ट के विचाराधीन ही है और उस पर फाइनल जजमेंट नहीं आया, हमने तो आपको कहा कि आप लोगों ने जितने आरोप लगाए हैं सरकार पूरे पारदर्शी तरीके से और स्पष्टता से उनकी जांच कराना चाहती है और इसीलिए हमने कहा कि जो जांच का प्रतिवेदन अभी अंतरिम आया है उसमें जितने आरोप लगाए थे सभी की जांच करके रिपोर्ट पूर्णता से दाखिल नहीं की गई है इसलिए हम लोगों ने निदेश दिया है कि जितने भी आरोप लगाए गए हैं उन सबकी जांच करके विस्तृत जांच प्रतिवेदन दें और अगर उसमें दोषी पाए जाएंगे तो कार्रवाई होगी ।

श्री मोहम्मद नेहालउद्दीन: महोदय, माननीय मंत्री जी ने कहा कि चेयरमैन के फंक्शन पर रोक नहीं लगाई गई है, साफ ऑर्डर कह रहा है कि उनके फंक्शन पर रोक लगाई जाती है और आज तक इसको बहाल नहीं किया गया है । अगर ठीक है आपने या सरकार ने जो त्रिस्तरीय कमिटी बनाई है, उसकी रिपोर्ट अधूरी है, पूरी रिपोर्ट आने

के बाद आप कार्रवाई करेंगे, इस दरमियान में इस आदेश के आलोक में चेयरमैन के सारे कामकाज पर कोर्ट ने जो रोक लगाई है...

अध्यक्ष: आदेश आप उपलब्ध करवा दीजिए ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री: ठीक है ।

(व्यवधान)

श्री महबूब आलम: महोदय, कोर्ट ने चेयरमैन के खिलाफ...

अध्यक्ष: महबूब जी आपका हस्ताक्षर इसमें नहीं है, आप बैठ जाइए ।

(व्यवधान)

बहुत लोग हैं, 14 लोग हैं साइन किए हुए ।

श्री मोहम्मद इसराईल मंसूरी: महोदय, माननीय मंत्री जी से जानना चाहेंगे कि जो जांच करवाएंगे तो जांच अवधि की कोई समय सीमा भी तय होगी या सालों-साल जांच होती रहेगी, यह बताइए ?

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री: महोदय, सरकार की तत्परता तो आप इससे समझ सकते हैं कि फरवरी में ही आरोप पत्र आया है और हमने अंतरिम जांच रिपोर्ट मंगा ली है और उसको विस्तृत करने का निदेश दे दिया है तो समझिए एक महीने के अंदर सारी चीजें की जाएंगी ।

अध्यक्ष: माननीय सदस्य श्री समीर कुमार महासेठ अपनी सूचना को पढ़ें ।

श्री समीर कुमार महासेठ: महोदय, पहली वाली सूचना पर बोलना है ।

अध्यक्ष: अच्छा पहले वाले पर बोलिए ।

श्री समीर कुमार महासेठ: अध्यक्ष महोदय, पहली वाली में हम आपसे संरक्षण चाहते हैं कि जब इतना स्पष्ट, माननीय मंत्री जी दूध का दूध और पानी का पानी करना चाहते हैं तो अभी से हम लोगों का जो आरोप है, आपका संरक्षण चाहिए इनको अपने कामों से जब तक त्रिस्तरीय कमिटी की रिपोर्ट नहीं आ जाती है तब तक उनके कामों पर हरेक तरह से हाईकोर्ट ने रोक लगाकर रखी है ।

टर्न-11/यानपति-अंजली/09.03.2021

अध्यक्ष: चलिये सुझाव है आपका । अब आप अपनी सूचना पढ़िये ।

श्री ललित कुमार यादव: महोदय और माननीय सदस्य का जो.....

(व्यवधान)

अध्यक्ष: तो इनकी सूचना फिर पढ़ी नहीं जायेगी, आप शार्ट में पूरक पूछिये, जो पूरक आ चुका है उस पर प्रश्न नहीं करिये । दूसरा पूरक है तो पूछिये ।

श्री भाई वीरेन्द्रः महोदय, ये गंभीर मामला है हुजूर और वित्तीय अनियमितता का सवाल है और जो चेयरमैन हैं तथाकथित चेयरमैन हैं वह अपने सगा-संबंधियों की बहाली कर रखे हैं, जब कि कोर्ट में मामला लंबित है और 107 मदरसा उसको संचालित कर रहे हैं और द्वितीय पक्ष को अधिकार दे दिये हैं प्रथम पक्ष का था और प्रथम पक्ष के लोगों को मनमाने ढंग से रोक दिया गया और द्वितीय पक्ष उसको आदेश पारित कर दिया जो कोर्ट का उल्लंघन है, सरकार के आदेश का उल्लंघन है, तो माननीय मंत्री से मैं कहूंगा कि उन्होंने जो जवाब दिया कि हम जांच करायेंगे और काम पर रोक लगाकर के समय-सीमा बतावें ।

अध्यक्षः माननीय मंत्री ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्रीः महोदय, जिस मदरसा संख्या 107 का जिक्र कर रहे हैं । पहली बात तो उसका सिर्फ जिक्र था जो ऑपरेटिव पार्ट है उसमें उससे संबंधित कोई इसमें निवेदन या इसमें कुछ मांग नहीं की गई थी लेकिन माननीय सदस्य की चिंता है तो जो ये जांच कमेटी त्रि-सदस्यीय जांच समिति इसकी जांच कर रही है उसके जांच के मेंडेट में इस मदरसा से संबंधित 107 संख्या से संबंधित जो आदेश है, हम उसकी भी जांच करने के लिए उनको निदेश दे देंगे ।

श्री ललित कुमार यादवः अध्यक्ष महोदय, एक पूरक, माननीय मंत्री जी ने 107 मदरसा की संख्या में जो भाई वीरेन्द्र ने प्रश्न पूछा, 107 में द्वितीय पक्ष को गलत आदेश दे दिया है प्रथम पक्ष को भी आदेश दे दिया काम करने के लिए और इधर द्वितीय पक्ष को भी आदेश दे दिया है और प्रथम पक्ष को कहा सिविल सूट में जाइए और दूसरे पक्ष अपीलीय प्राधिकार में दोनों मामला लंबित था उसी बीच द्वितीय पक्ष को आदेश कर दिया है ये गलत है ये इसमें उद्धृत है । महोदय, दूसरा एक 24 फरवरी को माननीय मंत्री को इस संबंध में पत्र भी मिला है 107 मदरसा के संबंध में स्पेशली तो माननीय मंत्री जी को सिर्फ इतना ही बता दें जो गलत काम कर रहे हैं प्रथम पक्ष को या तब तक दोनों पक्षों पर रोक रहेगी जब तक माननीय मंत्री जी का कोई निर्णय नहीं होगा । बस एक सवाल सरकार से ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्रीः माननीय अध्यक्ष महोदय, वैसे तो विहित प्रक्रिया है कि अगर मदरसा बोर्ड का प्रशासन या मदरसा बोर्ड अध्यक्ष अगर कोई गलत या अनियमित आदेश करते हैं तो उसकी निर्धारित प्रक्रिया है कि आप विशेष सचिव के यहां उसके विरुद्ध अपील में जा सकते हैं एक ये प्रक्रिया है । लेकिन माननीय सदस्य चूंकि इसका जिक्र अलग से कर रहे हैं इसलिए इस मदरसा से संबंधित क्या आदेश है इसको हम अलग से दिखाकर माननीय सदस्य से भी बात कर लेंगे ।

श्री ललित कुमार यादवः महोदय, माननीय मंत्री जी ने अपने जवाब में स्पष्ट कहा है कि इसके लिए विशेष सचिव अपीलीय प्राधिकार है वही तो हम भी कह रहे हैं वह लंबित है

और उसके बावजूद अलग अध्यक्ष आदेश कर दिया, माननीय मंत्री जी भी तो स्वीकार कर रहे हैं अपीलीय प्राधिकार है जब अपीलीय प्राधिकार में वह गये हुये हैं, लंबित था तो किस आधार पर मदरसा बोर्ड के चेयरमैन ने यह दुबारा आदेश कर दिया यही तो सवाल है तो इसी पर तो कहा जा रहा है महोदय, तब तक कहा जा रहा है सर यदि गलत आदेश हुआ है उसके दोनों पक्ष को रोककर के माननीय मंत्री जी जांच कर लें और जो सही होगा माननीय मंत्री जी, सरकार करे, हम यही चाहते हैं...

अध्यक्षः माननीय मंत्री जी ने कहा कि इसको हम गंभीरता से देख लेते हैं आपने ध्यान आकृष्ट कराया । आप जानकारी भी दे रहे हैं ।

श्री ललित कुमार यादवः महोदय, माननीय मंत्री के जवाब को ही मैं कह रहा हूं माननीय मंत्री अपने जवाब में...

अध्यक्षः अब समय बहुत कम बचा है ।

श्री ललित कुमार यादवः महोदय, लेकिन समस्या का निदान, महोदय, माननीय मंत्री...

अध्यक्षः वे देख लेंगे ।

श्री ललित कुमार यादवः महोदय, 107 मदरसा में अपीलीय प्राधिकार में जाना चाहिए हम कह रहे हैं अपीलीय प्राधिकार में लंबित है जब लंबित है तो फिर माननीय महोदय भी मान रहे हैं कि लंबित है ।

अध्यक्षः माननीय मंत्री जी जब कह रहे हैं हम देख लेते हैं, जांच कर लेते हैं तो समय देना होगा, देखिये सदन के अंदर आपने ध्यान आकृष्ट किया ।

श्री ललित कुमार यादवः महोदय, आसन का हमलोग, माननीय मंत्री के जवाब को ही हम पोर्ट कर रहे हैं । माननीय मंत्री कह रहे हैं कि यदि कोई बाधा है या कोई गलत आदेश है तो अपीलीय प्राधिकार में जाय वही तो माननीय मंत्री जी के सवाल में है कि अपीलीय प्राधिकार में लंबित था वह विशेष सचिव के कोर्ट में गये हुये हैं इस बीच में मदरसा बोर्ड के चेरयमैन ने गलत आदेश कर दिया है तो दोनों आदेश को देखकर तत्काल कार्य पर दोनों पक्ष को रोक लगाते हुये माननीय मंत्री जी जांच करा कर के जो भी निर्णय का फलाफल हो वह करेंगे...

अध्यक्षः माननीय मंत्री जी, आप इसको देख लें गंभीरता के साथ ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्रीः ठीक है ।

अध्यक्षः श्री समीर कुमार महासेठ ।

सर्वश्री समीर कुमार महासेठ, विजय कुमार सिंह उर्फ डब्लू सिंह एवं अन्य चार सभासदों से प्राप्त ध्यानाकर्षण सूचना तथा उस पर सरकार (सहकारिता विभाग) की ओर से वक्तव्य ।

श्री समीर कुमार महासेठः अध्यक्ष महोदय, ''अपार्टमेंट में रह रहे फ्लैट मालिकों के द्वारा एक एसोसिएशन का गठन कर अपार्टमेंट की देखरेख की जाती है । सरकार द्वारा जारी निर्देशानुसार इस तरह के एसोसिएशन का सहकारिता एक्ट या कंपनी एक्ट की धारा-8 के अंतर्गत निबंधन किया जा सकता है । सहकारिता एक्ट में एसोसिएशन का निबंधन तभी हो सकता है जब आरक्षण के नियमों का पालन किया गया हो । अपार्टमेंट बिक्री या खरीद में आरक्षण का ध्यान रखा जाना संभव नहीं है, ऐसी स्थिति में कोई एसोसिएशन सहकारिता विभाग के अंतर्गत निबंधन नहीं हो सकता है। नतीजतन सहकारिता कानून के तहत राज्य में अपार्टमेंट ऑनर एसोसिएशन का निबंधन नहीं हो पा रहा है जिसके कारण तरह-तरह की कानूनी अड़चनें सामने आती हैं ।

अतः बिना आरक्षण के नियमों का पालन किये अपार्टमेंट ऑनर एसोसिएशन का निबंधन किये जाने का प्रावधान सहकारिता एक्ट में किये जाने हेतु हम सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हैं ।''

अध्यक्षः माननीय मंत्री, सहकारिता विभाग ।

श्री श्रवण कुमार, मंत्रीः महोदय, समय चाहिए ।

अध्यक्षः समय चाहिए, ठीक है ।

श्री समीर कुमार महासेठः अध्यक्ष महोदय, पूरे देश में सब जगह हो रहा है केवल बिहार में नहीं हो पा रहा है और मेरा...

(व्यवधान)

अध्यक्षः चलते सत्र में ही जवाब मिलेगा । अब माननीय सदस्य,श्री राणा रणधीर अपनी सूचना को पढ़ें ।

सर्वश्री राणा रणधीर, पवन कुमार जायसवाल एवं अन्य दो सभासदों से प्राप्त ध्यानाकर्षण सूचना तथा उस पर सरकार (स्वास्थ्य विभाग) की ओर से वक्तव्य।

श्री राणा रणधीरः अध्यक्ष महोदय, ''पूर्वी चम्पारण जिला के पकड़ी दयाल अनुमंडल स्थित अनुमंडलीय अस्पताल का उद्घाटन वर्ष 2014 में माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों द्वारा किया गया था । अभी तक उक्त अनुमंडलीय अस्पताल को तकनीकी रूप से अनुमंडलीय अस्पताल का दर्जा नहीं दिया गया है, जिसके कारण लाखों ग्रामीण जनता बेहतर स्वास्थ्य सुविधा से वंचित हैं ।

अतः पकड़ी दयाल अनुमंडल अस्पताल को तकनीकी रूप से अनुमंडलीय अस्पताल का दर्जा देने हेतु हम सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हैं ।''

अध्यक्षः माननीय मंत्री, स्वास्थ्य विभाग ।

श्री श्रवण कुमार, मंत्रीः समय चाहिए ।

अध्यक्षः चलते सत्र में ही ।

श्री श्रवण कुमार, मंत्रीः चलते सत्र में ही दोनों ध्यानाकर्षण का जवाब होगा । माननीय सदस्य थोड़ा गंभीर रहें तभी न जवाब होगा, गंभीर रहते ही नहीं हैं, तो जवाब कैसे होगा ।

अध्यक्षः अब सभा की कार्यवाही 2:00 बजे दिन तक के लिए स्थगित की जाती है ।

टर्न-12/सत्येन्द्र/09-03-2021

(अन्तराल के बाद)

(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

अध्यक्ष: सभा की कार्यवाही प्रारम्भ की जाती है। अब वित्तीय कार्य लिये जायेंगे।

वित्तीय कार्य

अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, ऊर्जा विभाग की अनुदान की मांग पर वाद विवाद, सरकार का उत्तर एवं मतदान होगा । इसके लिए तीन घंटे का समय उपलब्ध है । विभिन्न दलों को उनकी सदस्य संख्या के आधार पर समय का आवंटन निम्न प्रकार किया जाता है । इसी समय में से सरकार को उत्तर के लिए भी समय दिया जायेगा।

राष्ट्रीय जनता दल	-	56 मिनट
भारतीय जनता पार्टी	-	55 मिनट
जनता दल युनाइटेड	-	33 मिनट
इंडियन नेशनल कांग्रेस	-	14 मिनट
सी0पी0आई0(एम0एल0)	-	09 मिनट
ऑल इंडिया मजलिस-ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन	-	04 मिनट
हिन्दुस्तानी आवाम मोर्चा	-	03 मिनट
विकासशील इंसान पार्टी	-	03 मिनट
सी0पी0आई0एम0	-	01 मिनट
सी0पी0आई0	-	01 मिनट
लोक जनशक्ति पार्टी	-	01 मिनट

माननीय मंत्री, ऊर्जा विभाग अपनी मांग प्रस्तुत करें ।

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : अध्यक्ष महोदय,मैं प्रस्ताव करता हूँ....

'' ऊर्जा विभाग'' के संबंध में 31 मार्च, 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्त्ति के लिए 85,59,99,72,000/-(पचासी अरब उनसठ करोड़ निन्यानवे लाख बहत्तर हजार) रूपये से अनधिक राशि प्रदान की जाय ।''

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है ।

अध्यक्ष: इस मांग पर माननीय सदस्य श्री विजय शंकर दूबे, श्री राजेश कुमार, श्री अजीत शर्मा, श्री सत्यदेव राम, श्री अख्तरूल ईमान, श्री सुधाकर सिंह एवं श्री महबूब आलम से कटौती प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं । ये सभी व्यापक हैं, जिस पर सभी माननीय सदस्य विचार विमर्श कर सकते हैं । माननीय सदस्य श्री विजय शंकर दूबे

का प्रस्ताव प्रथम है। अतएव माननीय सदस्य, श्री विजय शंकर दूबे अपना कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करें ।

श्री लखेंद्र कुमार रौशन:अध्यक्ष महोदय,एक मिनट का समय चाहिए।

अध्यक्ष: बोलिये।

श्री लखेन्द्र कुमार रौशन: विधायक के क्षेत्राधिकार का मामला है महोदय, अभी वैशाली जिला में जिला कृषि पदाधिकारी और पातेपुर प्रखंड के प्रखंड कृषि पदाधिकारी द्वारा कृषि मेला का उदघाटन स्वयं पदाधिकारियों द्वारा किया जाता है, कल ही हुआ है महोदय, जब हम सभी विधायक यहां है और किसान से जुड़ा हुआ विषय है। कृषि महोदय द्वारा इसे संज्ञान में लिया जाय कि जब विधान-सभा सत्र चले तो कम से कम पदाधिकारी इस प्रकार का मेला का उदघाटन कर के जनप्रतिनिधि के साथ नाइंसाफी नहीं करे महोदय,मैं यही निवेदन करता हूँ आपसे।

अध्यक्ष: ठीक। श्री विजय शंकर दूबे।

श्री विजय शंकर दूबे: अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :-

'' इस शीर्षक की मांग 10/-रूपये से घटायी जाय । ''

अध्यक्ष महोदय, ये प्रस्ताव मैं इसलिए लाया हूँ कि महोदय बिजली के क्षेत्र में सुधार हुआ है महोदय, नि:संदेह माननीय मंत्री के कार्यकाल में बिजली में व्यापक सुधार हुआ लेकिन आज जो महोदय बिजली के बिल को लेकर जो गड़बड़ियां हैं आमलोगों को जो परेशानी हो रही है महोदय बिल को सुधार कराने में जिला में , माननीय मंत्री एक एस0डी0ओ0 को या तीन चार ब्लौक पर एक बिजली एस0डी0ओ0 को अधिकार दे रखें हैं बिल में सुधार करने का, आज सहायक अभियंता ब्लौकों में कैम्प नहीं करते, वे एक जगह कार्यालय बनाकर के बैठे हुए हैं और किसान, आम आदमी, गरीब गुरबे साधारण लोग दौड़ लगा रहे हैं। आज ब्लौक के हालत हो गये हैं बिजली में सुधार कराने का इसीलिए महोदय..

अध्यक्ष: चार ही मिनट का समय है।

श्री विजय शंकर दूबे: इसमें सुधार की जरूरत है और महोदय बिजली में अन्य सुधार की भी आवश्यकता है। हर खेत को पानी देने की सरकार घोषणा की थी। बिहार किसानों का प्रदेश है अभी तक हर खेत में बिजली नहीं पहुंची है, बिजली के रेट तय नहीं है, उनके खेत तक बिजली पहुंचाने में अभी सारे किसानों का आवेदन लंबित है, उस पर ध्यान सरकार का नहीं है इसलिए मैं मांग करता हूँ कि कृषि मंत्री जी किसानों के कृषि के खेत में बिजली पहुंचाने में प्राथमिकता दें । दूसरा महोदय, आज बिजली के साथ अन्य विभाग भी हैं जिसमें योजना विकास विभाग भी शामिल है। एक बात की ओर महोदय मैं आसन का ध्यान आकृष्ट करता हूँ और आसन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ,अभी यहां सरकार

की उपस्थिति कम है दो इम्पौर्टेंट मंत्री बैठे हुए हैं, आपकी नियत अगर सही है और माननीय सदस्य जो सवाल उठा रहे थे ये सवाल आज ज्वलंत होता जा रहा है माननीय सदस्यों का सवाल महोदय, आपने भी आसन से निर्देश जारी किया है सुधार की दिशा में और महोदय, आसन के निर्देश का एक तो असर दिख रहा है कि प्रश्नों के उत्तर शत प्रतिशत प्राप्त हो रहा है। यह असर हुआ है लेकिन एक बात महोदय, दूसरी ओर सदन का ध्यान और माननीय मंत्री विजेन्द्र यादव जी जो राज्य के वरिष्ठ मंत्री हैं उनका ध्यानाकृष्ट करना चाहता हूँ कि अनुमंडलों में जो विधायक की अध्यक्षता में अनुश्रवण समिति बनती थी और अनुमंडल पदाधिकारी उसके सचिव होते थे, उस कमिटी का गठन नहीं हो पाया है। पिछली बार गठन भी हुआ था, माननीय मुख्यमंत्री छपरा गये थे उन्होंने दो तीन मीटिंग की, हर मीटिंग में इस सवाल को मैं उठाता था, माननीय मुख्यमंत्री जी ने तीसरी बार कहा कि जब तक मैं यहां बैठा हुआ हूँ सरकार नोटिफिकेशन की प्रति माननीय सदस्यों को वितरित करे और छपरा जिले की पूरी कमिटी गठित हुई थी फिर उस पर मैंने सवाल उठाया कि जो नौर्मस सरकार ने निर्धारित किया है यह उस नौर्मस के प्रतिकुल है, उसमें सुधार कराया गया । महोदय, ये पहले से स्थापित नियम है, माननीय सदस्य उसके अध्यक्ष हुआ करते हैं अनुमंडल पदाधिकारी उसके सचिव होते हैं, अन्य सदस्य जो सिनियर होगा, चाहे वह किसी दल का हो, इधर का हो या उधर का हो जो वरीय होगा वह अध्यक्ष होगा। उसकी मीटिंग होती थी, अनुश्रवण होती थी। बैठक कराया जाना माननीय विधायक के अध्यक्षता में अनुमंडल में इसके लिए उस कमिटी का होना आवश्यक है

अध्यक्षः अब बैठ जाईए।

श्री विजय शंकर दूबेः इसलिए मैं सरकार से मांग करता हूँ कि सरकार उस अनुश्रवण समिति को पुनर्जीवित करे राज्य में और योजना विकास विभाग उसमें पारदर्शिता बरते । अपने लोगों को मंत्रियों की अध्यक्षता में न बैठाया करे, मंत्री तो मंत्री हैं राज्य सरकार हैं उनको नहीं बैठाया करें । पिछली बार ये गलतियां हुई थीं इसलिए मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ कि केवल और केवल विधायक की अध्यक्षता में अनुमंडल में कमिटी बने।

टर्न–13/मधुप/09.03.2021

अध्यक्ष : अब बैठ जायं । 4 मिनट एक्स्ट्रा हो गया ।

श्री विजय शंकर दूबे : महोदय, हमारे दल के दूसरे सदस्य शेष समय भर बोलेंगे, इन्हीं शब्दों के साथ मैं कटौती प्रस्ताव का पुरजोर समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ ।

अध्यक्ष : श्री रामवृक्ष सदा । 13 मिनट का समय है ।

श्री रामवृक्ष सदा : महोदय, सबसे पहले मैं आपको सहृदय आभार प्रकट करता हूँ कि आपने इस बिहार विधान सभा में पहली बार हमें बोलने का मौका दिया, मैं आभार प्रकट करना चाहता हूँ आदरणीय नेता बाबू श्री लालू प्रसाद यादव जी का, वे मेरे भगवान हैं जिन्होंने आज एक मजदूर मुसहर के बेटा को नेता बनाने का काम किया, मैं आभार प्रकट करता हूँ बिहार के सबल प्रहरी प्रतिपक्ष के नेता आदरणीय बाबू तेजस्वी यादव जी को, जिनके चलते, जिनके सहयोग, आशीर्वाद और प्यार से आज विधान सभा देखने का मौका मिला, मैं आभार प्रकट करना चाहता हूँ उस महान जनता मालिक का, लाखो-लाख बार उस अलौली की धरती को प्रणाम करता हूँ जिस धरती से आज महान जनता मालिक ने एक गरीब, एक मजदूर, एक मुहसर के बेटा को अपना पक्ष इस विधान सभा में रखने के लिए भेजने का काम किया ।

महोदय, आज विपक्ष के द्वारा बिजली के अनुदान मॉग पर लाये गये कटौती प्रस्ताव के पक्ष में मैं अपनी बात को आपके सामने रख रहा हूँ । महोदय, एक तरफ जहॉ बिहार सरकार बिजली के नाम पर अपनी पीठ थपथपा रही है, वहीं दूसरी तरफ बिजली का कनेक्शन वहॉ तक नहीं पहुँचा है जहॉ तक पहुँचना चाहिए। महोदय, आज सरकार बोल रही है कि पूरे बिहार में हम बिजली दे रहे हैं लेकिन महोदय, सरकार को यह भी बोलना चाहिए कि पूरे बिहार में आप बिजली दे रहे हैं तो पूरे देश में सबसे महँगी बिजली आप बिहार में दे रहे हैं । महोदय, मैं आपको अवगत कराना चाहता हूँ कि आज किसान लोग, मजदूर लोग, जो खेतिहर मजदूर हैं, किसान हैं, हमलोगों के घर में बिजली का कनेक्शन है, अगर हम 200 रू0 भी दो महीना नहीं जमा करते हैं तो हमारा बिजली काट दिया जाता है, कनेक्शन काट दिया जाता है और हमको बिजली चोर बोला जाता है। महोदय, सुशासन बाबू के राज में तमाम कार्यालय में अरबो-अरब बिजली बिल बाकी है, क्या उसे सुशासन चोर हम नहीं बोलेंगे ? निश्चित रूपेण बोलेंगे जो बिजली बिल करोड़ो रू0 के बकाया के बाद भी अपने कार्यालय का बिजली कनेक्शन नहीं काटते हैं और 200 रू0 अगर मजदूर और किसान के यहॉ बिजली बिल बाकी होता है, उनका कनेक्शन काट दिया जाता है । महोदय, यह एक गम्भीर मामला है। इस मामले को महोदय, आपको देखना होगा ।

महोदय, मैं आगे और आपको कहना चाहता हूँ कि आज की तारीख में पूरे बिहार में एक रोजगार खुल गया है, वह रोजगार क्या खुल गया है, इसके संबंध में महोदय, मैं आपको बताना चाहता हूँ । एक दिन हम सवेरे-सवेरे टहलते हुए पड़ोस में ही एक घर में गये, अपना मित्र मंडली ही था, उसके घर में गये, हमने देखा कि घर में एक बहुत बड़ा फोटो लगाये हुये हैं और एक-दो अगरबत्ती नहीं,

एक मुट्ठी अगरबत्ती जला रहे हैं और वह बोल रहे हैं, वह आरती गा रहे हैं, जय सुशासन, जय सुशासन, जय सुशासन देवा, घर-घर शराब पहुँचे, अफसर खाये मेवा। जय सुशासन देवा, जय सुशासन देवा । हुजूर, उसके बाद मैं उनका आरती खतम होने तक सुनता रहा, जैसे ही उनका आरती खतम होता है, हमने उनसे पूछा कि क्या भाई, यह कौन-सा आरती है, उन्होंने कहा कि यह वह आरती है कि उस समय जब आदरणीय मुख्यमंत्री, बिहार के माननीय मुख्यमंत्री ने पूरे बिहार में दारू खोलवाने का, ठेका खोलवाने का काम किया चाहे वह स्कूल के बगल में, चाहे कार्यालय के बगल में हो, चाहे गाँव के बगल में हो, चाहे मंदिर के बगल में हो, चाहे मस्जिद के बगल में हो, एक ऐसा समय था जहाँ घर-घर दारू का ठेका खोलवाने का काम किया और आज वह दारू बंद करने का काम कर रहे हैं, दारू बंद कर दिये हैं । मैं आपसे कहना चाहता हूँ महोदय, उस व्यक्ति ने बताया कि जिस समय ठेका हुआ करता था, उस समय 10 कट्ठा खेत बेचते थे तो एक साल पीते थे लेकिन आज स्थिति यही हो गई है कि घर भी दारू पहुँचाया जाता है तो एक बीघा खेत बेचते हैं, ग्यारह महीना में खतम हो जाता है, एक महीना अलग से रीचार्ज करना पड़ता है ।

महोदय, सदन के माध्यम से आपको मैं बताना चाहता हूँ कि आज की तारीख में जो बिहार की हालत है वह किसी से छुपी हुई नहीं है । हाल ही के दिनों में चार जिलों में शराब पीने वाले और पीकर मरने वालों की संख्या 20 हो गई है और नीतीश कुमार जी के सरकार में कहा जाता है, नीतीश बाबू सुशासन बाबू के नाम पर कहा जाता है, जो मौत हुई है, कहते हैं कि हम दलित के बहुत बड़ा हितैषी हैं, आज जितने भी शराब पीकर सबसे ज्यादा लोग मरे हैं तो दलित-महादलित वर्ग के लोग मरे हैं, शराब पीकर जितना लोग सबसे ज्यादा जेल में है वह महादलित वर्ग के लोग हैं, शराब पीकर जो रोड पर मर रहा है एक्सीडेंट होकर उसमें सबसे ज्यादा महादलित वर्ग के लोग हैं । जिनको खाने के लिए पैसा नहीं मिलता है, कल की तारीख में वह अपने पति को कैसे जेल से छुड़ायेगी, मजबूर है महोदय, उनका छोटा-छोटा बच्चा है, उनका औरत भीख माँगने पर मजबूर हो जाती है और वह अपने पति को नहीं छुड़ा पाती है । यही आपका बिहार का सुशासन की सरकार है ।

महोदय, मैं कहना चाहता हूँ कि आपके सुशासन बाबू कहा करते थे, दलित हमलोग थे, दलित से हमलोगों को महादलित बनाने का काम किया और जब हमलोग महादलित बने तो बोलते थे कि महादलित के लिए बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, महादलित के लिए काम कर रहे हैं, महादलित के लिए हम बहुत उपर सोच रख रहे हैं, हम महादलित के हितैषी हैं । मैं पूछना चाहता हूँ सुशासन की

सरकार से कि अगर आप महादलित के हितैषी होते तब जीतन राम मांझी, एक मुहसर के बेटा को मुख्यमंत्री की कुर्सी से आप नहीं उतारते, आप नहीं उतारते । लेकिन आदरणीय गार्जियन बाबू जीतन राम मांझी फिर वहीं चले गये जहॉ जिस कुर्सी पर मुख्यमंत्री होने के बाद बैठते थे, उस कुर्सी को गंगाजल से धोने का काम किया गया, उन्हीं लोगों के साथ मांझी जी भी जाने का काम किये ।

महोदय, आज मैं कहना चाहता हूँ, आज पूरे बिहार की जो स्थिति है, शराब की जो स्थिति है, घर-घर होम डिलेवरी शराब की हो रही है, छोटा-छोटा बच्चा शराब के नशे से मदमस्त हो रहा है, शराब की स्थिति बिगड़ती जा रही है । आज आपका जितना भी पुलिस प्रशासन के लोग हैं, दारू विभाग वाले पुलिस से आप छापा मरवाइये, तमाम बिहार के पुलिस पदाधिकारी से आप दारू वाला के यहॉ छापा मरवाते हैं और जो अपराध होता है उसपर कोई काम नहीं हो रहा है, सब पुलिस को आप दारू पकड़ने में लगा दिये हैं तो अपराध बिहार में कहॉ से कम होगा । यह भी एक कारण है कि बिहार में दिनोंदिन अपराध बढ़ता जा रहा है।

आगे मैं महोदय, आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि आज जो यहॉ सुशासन की सरकार है, हमने देखा कि एक आदमी जेल जा रहा था और बड़े जोर से हॅस रहा था, हमने उस आदमी से पूछा, भाई बड़े दुख की बात है कि आप जेल जा रहे हो फिर भी आप हॅस रहे हो, तो उस आदमी ने कहा कि हम शराब माफिया हैं, हम शराब कारोबारी हैं, जेल हमको जाने में कोई गम नहीं है, 19 लाख में यह भी एक रोजगार है, इसीलिए हम हॅस रहे हैं अपने रोजगार पर कि रोजगार करने पर भी हम जेल जा रहे हैं । बिहार में जो शराब की स्थिति है, वह किसी से छिपी हुई नहीं है । महोदय, आज मैं कहना चाहता हूँ कि एक कहावत है हमलोगों के तरफ कि सूर्य अस्त और बिहार के सभी चूहा दारू पीकर मस्त । हम नहीं बोल रहे हैं, यह आपके सुशासन बाबू के जो अफसर बाबू हैं, वह बोल रहे हैं कि बिहार के चूहा जितना शराब पकड़ाता है, सभी पी जाते हैं । यह सुशासन बाबू के पदाधिकारी का वक्तव्य है । इसीलिए हम बोल रहे हैं कि सूर्य अस्त और बिहार के सभी चूहा शराब पीकर मस्त । महोदय, आगे मैं सदन के माध्यम से कहना चाहता हूँ, आपने जो मुझे बोलने का मौका दिया है, आप गॉव चल जाइये, आप घर चल जाइये, आप गली-मुहल्ला चल जाइये, आप बाजार-मार्केट चल जाइये, आप मंदिर चल जाइये, आप मस्जिद चल जाइये, कहीं भी ऐसा जगह नहीं है जहॉ आपको बिहार में शराब नहीं मिलेगा, जहॉ आपको बिहार में शराब के तस्कर नहीं मिलेगा, जहॉ आपको बिहार में तस्करी करने वाले लोग नहीं मिलेंगे । लेकिन महोदय, तस्कर पर कार्रवाई नहीं होती है, कार्रवाई

किसके उपर होती है, उस गरीब के उपर जो रात-दिन मेहनत करके अपना बदन तोड़ लेता है और थोड़ा-सा शराब पीने पर कार्रवाई उसके उपर होती है और उसको जेल भेजने का काम किया जाता है ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : बैठ जाइये माननीय सदस्या ।

श्री रामवृक्ष सदा : महोदय, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज बिहार में जो स्थिति है, हमारे सुशासन बाबू बहुत गला चीर-चीर कर कह रहे थे मिट्टी में मिल जायेंगे लेकिन बिहार में शराब नहीं बिकवायेंगे, आज क्या है ? आज देखिये बिहार में, हर घर में शराब है, हर जगह पर शराब । वैसी जो बात बोलते हैं...

अध्यक्ष : बिजली पर भी बोलना है ।

श्री रामवृक्ष सदा : महोदय, बिजली पर जो बोलना था, हम बोल दिये । जो बिजली पर बोलना था, वह हमने बोला । आप ऐसी बात करते हैं । हर जगह शराब...

...क्रमशः...

टर्न-14/आजाद/09.03.2021

..... क्रमशः .....

श्री रामवृक्ष सदा : शराब तस्करों के, शराब माफियाओं से आपके प्रशासन के लोग उनसे मिले हुए हैं और पूरे बिहार में वे लोग ही शराब का सप्लाई करते हैं । आज मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ, आप कहते हैं कि बिहार में पूर्ण शराबबंदी है तो इतना लोग जो जेल में बंद हैं, वे लोग झारखंड के हैं या यू0पी0 के लोग हैं ? इन सब चीजों पर सरकार को जवाब देना चाहिए कि इतने लोग जेल में कहां के हैं, बिहार के हैं. ...

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, संक्षिप्त कर लीजिए ।

श्री रामवृक्ष सदा : महोदय, संक्षिप्त है । इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ कि बिहार में बहार है, सुशासन की सरकार है, घर-घर शराब का कारोबार है, 19 लाख में यह भी एक रोजगार है, यही तो बिहार की सरकार है, यही तो बिहार की सरकार है ।

महोदय, मैं आगे आपसे कहना चाहता हूँ । आज हमलोगों के यहां इतनी स्थिति खराब हो गई है कि एक तरफ आपकी सरकार दलित-महादलित की चिन्ता करती है, दलित से हमलोगों को महादलित बना दिया । अब हमलोगों को समझ में आता है कि माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने दलित से महादलित क्यों बनाया, सिर्फ महादलित को जहरीली शराब में डुबाकर मारने के लिए महादलित बनाया गया है, न कि महादलितों का विकास करने के लिए । महोदय, मैं कहना चाहता हूँ आपसे कि आज जो बिहार की स्थिति है वह किसी से छिपा हुआ नहीं

है । आज जो तस्कर लोग हैं, वे आये दिन पदाधिकारी को मार देता है, आपके एस0पी0 को मार देता है, आपके दारोगा को मार देता है, आपके नीचे आपके पदाधिकारी के बगल में शराब बिकता है लेकिन उसका हिम्मत नहीं होता है कि ऐसा क्यों हो रहा है । आज मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे क्षेत्र में तस्कर और प्रशासन भीड़ गया, हम वहां गया और वहां पर पहुँचा । हमने तस्कर से पूछा कि भाई ये लोग प्रशासन के लोग हैं, ये आपको समझा रहे हैं और ऊल्टे आपलोग इनसे भीड़ गये हैं तो उन्होंने हमको कहा सर कि 19 लाख में यह भी एक रोजगार है, रोजगार करने वाले लोगों से प्रशासन के लोग लड़ने के लिए आयेंगे तो हमलोग भीड़ेंगे ही, इसलिए हमलोग भीड़ते हैं । महोदय, इस 19 लाख में जो है एक रोजगार बांटने का आपने काम किया है, इस रोजगार को आप कम कीजिए और बिहार में पूर्ण शराबबंदी लागू कीजिए । अगर बिहार में पूर्ण शराबबंदी लागू करने का आपलोगों में अगर हौसला नहीं है तो फिर बिहार को शराबमुक्त कर दीजिए । खुले आम जैसे बिहार में शराब बिकता था वैसे ही बिकने दीजिए लेकिन पर्दा के पीछे हुजूर खेल मत कीजिए, पर्दा के पीछे हुजूर खेल मत कीजिए । आगे प्रहार है और पीछे शराब है ऐसा कानून नहीं चलेगा महोदय । आज मैं कहना चाहता हूँ कि आज इस देश में जो शराब बिक रहे हैं, बिहार में जितने भी लोग शराब बेच रहे हैं, वैसे तमाम लोग जो हैं .....

(व्यवधान)

अध्यक्ष : आप बोलते रहिए ।

श्री रामवृक्ष सदा : वह आज अपने स्तर से तमाम लोग बात करते हैं, आज मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आज बिहार में लाखों-लाख लीटर शराब पकड़े जा रहे हैं, शराब के बारे में आपके पुलिस पदाधिकारी हैं वे आपको सही रिपोर्ट नहीं देते हैं और आपके पुलिस पदाधिकारी शराब को बेच देते हैं और नाम चूहा का लगाते हैं । बरका चोर चोर नहीं और छोटका चोर बरका चोर, यही हाल है बिहार में । इसलिए चूहा पर जो आरोप लगा रहे हैं, आप उस आरोप को खतम कीजिए और जो लोग शराब माफिया है, उसपर आप आरोप लगाइए न कि आप चूहा पर आरोप लगाइए ।

आगे महोदय, मैं कहना चाहता हूँ, हमारे क्षेत्र में बहुत सारी समस्यायें हैं, हमारे खगड़िया जिला के अलौली प्रखंड के अन्तर्गत बहादुरगंज ग्राम पंचायत है, जिस ग्राम पंचायत में राम कुमार नाम का आदमी अरूणाचल प्रदेश में तेल कम्पनी में काम करता था, उल्फा उग्रवादियों ने उन्हें अगवा कर लिया, दो महीना हो गया है और उनका बेटा कैंसर पीड़ित है, अभी तक सरकार की ओर से कोई कार्रवाई यहां से नहीं हो सकी है । मैं सदन से मांग करता हूँ, आपसे मांग करता हूँ कि उस गरीब को आप मुक्त कराने का काम करें ।

अध्यक्ष : अब आप बैठ जाइए ।

श्री रामवृक्ष सदा : मेरा आगे और मांग है महोदय, मात्र दो-तीन मिनट में । महोदय, हमारा मांग है कि अलौली प्रखंड नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, इसलिए अलौली प्रखंड को अनुमंडल का दर्जा दिया जाय । महोदय, अलौली प्रखंड का लाखों-लाख किसानों का कोशी इलाका में जमीन है, जिनको फरकिया कहा जाता है । वहां पुल का निर्माण किया जाय और वहां पर बहुत बड़ा बस्ती है .....

अध्यक्ष : अब आप बैठ जाइए, श्री जनक सिंह । अब आप समाप्त करिए ।

श्री जनक सिंह : अध्यक्ष महोदय, ऊर्जा विभाग पर लाये गये कटौती प्रस्ताव के विरोध में बोलने के लिए खड़ा हूँ ....

श्री लखीन्द्र कुमार रौशन : अध्यक्ष महोदय, एक महादलित का बेटा श्री जीतन राम मांझी जी को माननीय नीतीश कुमार जी ने मुख्यमंत्री के कुर्सी पर बैठा दिया था । माननीय सदस्य, लालू चालीसा पढ़ते हैं और आप भी एक महादलित के बेटा हैं, आपको भी मुख्यमंत्री के कुर्सी पर बैठा देंगे ..... (व्यवधान)

अध्यक्ष : आप बैठ जाइए । माननीय सदस्य श्री जनक जी, आप अपनी बात रखें । आप उनका समय क्यों बर्बाद करने में लगे हैं ।

आप बैठ जाइए । आप अपनी जगह पर बैठ जाइए ।

श्री जनक सिंह : अध्यक्ष महोदय, जब सत्ता पक्ष बोलता है तो प्रतिपक्ष बोलता है, सत्ता पक्ष जब बोलता है और तब इनके अन्दर यह भावना आती है । आप अपनी बात को रखिए और हम तो कहते हैं कि .....

अध्यक्ष : आप जनक जी, आसन की तरफ देखकर बोलिए, इधर-उधर मत देखिए ।

श्री जनक सिंह : हम तो कहते हैं अध्यक्ष महोदय, आज 73 वर्ष 6 महीने 25 दिन हो रहे हैं अपने आजादी हासिल हुए, इसमें लगभग 51 वर्ष से अधिक हमारे माननीय सदस्य जो कटौती प्रस्ताव लाये हैं, वे कांग्रेस से आते हैं और उनके सहयोगी राजद के लोग हैं और ये 51 वर्ष से अधिक दिनों तक बिहार के सत्ता को संचालित किया है और अभी माननीय प्रतिपक्ष की ओर से ऊर्जा विभाग पर आंकड़े नहीं दे रहे थे, भाषण कर रहे थे । आंकड़े हमारे माननीय ऊर्जा मंत्री जी देंगे तब आपको लगेगा कि हमारा जो नेतृत्व रहा है, राज्य के अन्दर हमने जो संचालन करने का काम किया है, वह आंकड़ा सत्ता पक्ष से कम है, बहुत कम है । इसलिए हम तो कहते हैं कि एक कवि की युक्ति मुझे याद आ रही है कि -

समय के शिलों पर मधुर चीत कितने,
किसी ने बनाये, किसी ने मिटाये,
किसी ने लिखी ऑसूओं से कहानी,
किसी ने पढ़ा किन्तु दो बूँद पानी,

इसी में गये बीत दिन जिन्दगी,
गयी धूल जवानी, गयी मिट निशानी,
विकल सिंधु के साथ मेघ कितने,
धरा ने उठाये गगन ने गिराये ।

आपने 51 वर्षों तक इस राज्य का चौकीदारी किया और मात्र हम 15 वर्ष 3 महीने कुछ होने जा रहे हैं और हम धरा है, हम गंगा की वह धार हैं, जिस धार को अगर कोई रोकने का प्रयत्न करेगा तो वैसा ही किनारा हो जायेगा, जिस तरह से कीड़-मकोड़े किनारे हो जाते हैं । आंकड़ा पर चलता है सरकार, आपका लालटेन युग था 15 वर्षों तक, आपने उसकी कहानी पढ़िए, तब आप और हम सभी बिहार सूबे से बाहर जाते थे और दूसरे प्रदेशों में जाते थे, वह चकाचौंध बिजली की रोशनी जब मिलती थी तब आपके मन में भी यह बात उठती थी कि काश मेरे बिहार में भी इस प्रकार की रोशनी होती । आपने 15 वर्षों तक बिहार में राज किया लेकिन किया क्या ? किया केवल लूट-खसोट और उद्योगों को बिहार के अन्दर जितने भी उद्योग बन्द है, आपके कारण बन्द है चूँकि उद्योग जगत को बिजली देने का आपने काम नहीं किया ऊर्जा विभाग के कारण । आज जहां पर चले जाइए गांव-गलियारों, खेत-खलिहानों, विद्यालय-महाविद्यालयों के बीच में गरीब झोपड़ी में रहने वाले हमारे भईया-बहने हैं, उनके बीच में भी ऊर्जा है, बिजली है

..... क्रमशः .....

टर्न-15/शंभु/09.03.21

श्री जनक सिंह : क्रमशः इसलिए आज जो हमारे सहकारिता का चाहे वह हमारे उद्योग जगत का हो, चाहे कृषि से संबंधित हो । हम हर विभाग में आगे जो कुछ करने जा रहे हैं उसके लिए हम अपने माननीय ऊर्जा मंत्री जी को और विशेषकर के अपने बिहार सूबे के माननीय मुख्यमंत्री जी को सलाम करता हूँ कि आपने बिहार के अंदर ऊर्जा देने का काम किया है और पूरा देश देख रहा है । इसलिए भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेन्द्र भाई मोदी जी और बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी ये दोनों लोग जो बिहार को आगे बढ़ाने में लगे हैं । इसलिए शक्ति और भक्ति हमारे पास भक्ति भी है और ऊर्जा रूपी शक्ति भी है । आप बोलते रह जाइयेगा, आप कुछ करनेवाले लोग नहीं हैं हम जानते हैं । अध्यक्ष महोदय, आज पूरे राज्य में हर जगह जाइये बिजली ही बिजली है । हम अपने देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेन्द्र भाई मोदी और आदरणीय यहां के सूबे के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी को हम पुनः बधाई दे रहे हैं कि आप जिस रूप से आगे बढ़ रहे हैं, जमाना आपका है आप बोलते रह जाइये कुछ होनेवाला नहीं है । ये अब लोग

जान चुके हैं । इसलिए बिहार के अंदर एक नयी क्रांति आनेवाली है । हमारे बिहार सरकार के पास जितने भी विभाग हैं सभी को हमारे मुख्यमंत्री जी ने और हमारे भारत के प्रधानमंत्री जी ने ऊर्जा देने का जो काम किया है । आज बिहार- बिहार कभी दुनिया का नेतृत्व किया है, केवल भारत का ही नहीं बिहार दुनिया का नेतृत्व किया है और आनेवाले दिनों में आत्मनिर्भर भारत जो है वह आनेवाले दिनों में हमारा बिहार आत्मनिर्भर बिहार होगा और भारत को परम वैभव पर पहुंचाने का काम करेंगे । इसलिए हम तो कहते हैं कि अगर आप चाहते कि बिहार हमारा आगे बढ़े तो आप कटौती प्रस्ताव न लाते लेकिन आप तो यही देख रहे हैं, याद कीजिए वह जमाना अपना 15 वर्ष का कहां था ? लोग लालटेन लिये घुमते फिरते थे और उस लालटेन में भी तेल नहीं था, तेल कौन कहे बत्ती भी नहीं था और कोई खरीद नहीं पाता था । वह युग अब नहीं है, अब युग तरूणाइयों का है भीम और अर्जुन सा.....

अध्यक्ष : अब बिजली पर आ जाइये ।

श्री जनक सिंह : अध्यक्ष महोदय, इसलिए मैं यह कहूंगा कि बिहार विद्युत् की गुणवत्ता और अवधि में बढ़ोत्तरी के कारण राज्य में बिजली के मांग में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। बिजली की अधिकतम मांग पूर्ति जो सितम्बर, 2018 में 5139 मेगावाट थी और वही सितम्बर, 2019 में बढ़कर 5891 हो गयी है एवं पुनः नयी ऊंचाइयों को छूते हुए वित्तीय वर्ष के माह जुलाई 2020 में बढ़कर 5932 मेगावाट तक पहुंच गयी है। यह हमारी उपलब्धि है । इसलिए हम कहते हैं और जो हम कहते हैं वह करते हैं और आप जो कहते हैं वह करते नहीं हैं । हमारे और आपमें यही फर्क है । आज बिजली की उपलब्धता न केवल मानव के जीवन स्तर को ऊंचा करने में अपितु चाय उद्योग आदि जिसके विषय में हमने कहा था । इसलिए हमारा बिहार बढ़ रहा है । अब बिहार को हम आत्मनिर्भर बनायेंगे और हमारा आत्मनिर्भर बिहार जब होगा तो भारत आत्मनिर्भर होगा और जब भारत आत्मनिर्भर होगा तो दुनिया का नेतृत्व भारत करने जा रहा है ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : शांति बनाये रखें ।

श्री जनक सिंह : इसलिए आप देखते रह जायेंगे । मैं तो कहता हूँ कि हे भगवान आपको सुबुद्धि दें, आप पर ध्यान दें कि आप आगे बढ़ें । इसलिए हम कहते हैं कि तमसो मां ज्योतिगर्मय । हम सुबह में उठते हैं तो नमन करते हैं मां का कि हे मां मुझे अंधकार से प्रकाश में ले जा, लेकिन 51 वर्ष में हम यहां कांग्रेस के, राजद के भी लोग बैठे हैं । आप 51 वर्ष से अधिक समय तक इस सूबे में काम किये हैं ।

आप स्वयं से पूछिए कि 51 वर्षों में आपने क्या किया है । क्या यही है, उद्योग जगत वाले को पैरों में मारने का काम किये हैं ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : सुधाकर जी, आप तो बैठे-बैठे बोलनेवाले नहीं हैं ।

श्री जनक सिंह : इसलिए हम कहते हैं महोदय कि जब हम बोलते हैं तो कहते हैं कि सत्तापक्ष बोलता है, ये सुनने की क्षमता नहीं रखते हैं । हम तो कहते हैं कि आप आज सोने के वक्त सोचियेगा, हमारे राजद के माननीय लोग हैं सोचियेगा कि हमारे 15 साल का काल क्या रहा है । जो कटौती प्रस्ताव माननीय दूबे जी लाये हैं उनसे भी कह रहे हैं कि हमारी सरकार ने चाहे केन्द्र में या राज्य में रहे तो उनकी क्या उपलब्धियां रही है । अगर आपकी उपलब्धियां रही है तो आप बताइये । हम आपके अच्छे प्रस्ताव को मानने के लिए तैयार हैं ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : मौका मिलेगा आपको भी, बैठ जाइये । जनक जी, एक मिनट । आप बताइये कि आपका स्थान वही है । आप बैठे-बैठे मत बोलिये, जब एक सदस्य बोल रहे हैं । देखिये इधर से भी भाषण दिये सबलोग सुने, अच्छी परंपरा की शुरूआत करें आपको भी मौका मिलेगा । हल्ला करने से बात न सुनियेगा न समझियेगा, बैठ जाइये ।

(व्यवधान)

आपकी कोई बात प्रोसीडिंग में नहीं जायेगी । जिनको आसन से अनुमति मिली है केवल उन्हीं की बात प्रोसीडिंग में जायेगी, बाकी किन्हीं की बात नहीं जायेगी ।

श्री जनक सिंह : अध्यक्ष महोदय, प्रतिपक्ष के माननीय लोगों को कहना चाहिए कि माननीय मंत्री जी नये-नये जो घर बन रहे हैं वहां तक बिजली पहुंचाने का काम करें, यह बात आप नहीं कहियेगा और उल्टा सीधा बात से नहीं चलनेवाला है । इसलिए हम स्पष्ट रूप से कह देना चाहते हैं कि बिहार आत्मनिर्भर होने जा रहा है और भारत को गति देने जा रहा है । भारत जब हमारा प्रभुत्वशाली होगा- भारत कभी आध्यात्मिक रूप से या अन्य आर्थिक रूप से दुनिया का नेतृत्व किया है और आनेवाले दिनों में हमारा भारत दुनिया का नेतृत्व करने जा रहा है । आप पैरों में जो डंडे मारने का काम कर रहे हैं यह आपका चलनेवाला नहीं है, चूंकि बिहार की जनता आज नीतीश कुमार जी और हमारे उप मुख्यमंत्री आदरणीय हमारे जो..... व्यवधान ।

अध्यक्ष : बोलते रहिये । इधर उधर मत देखिए, बोलते रहिये ।

श्री जनक सिंह : अध्यक्ष महोदय, एक बात मैं कहूंगा कि.....

अध्यक्ष : अब संक्षिप्त कर लीजिए ।

श्री जनक सिंह : महोदय, कोविड-19 से उत्पन्न आपदा की स्थिति में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत आच्छादित लाभुकों को राहत प्रदान करने हेतु हमारे प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अन्तर्गत माह अप्रैल, 2020 से जून, 2020 तक प्रत्येक लाभुकों को राशन कार्डधारी प्रत्येक परिवार को प्रतिमाह 5 किलो चावल और 1 किलो दाल मुफ्त उपलब्ध कराया गया । इसके अन्तर्गत 4 लाख 32 हजार 248.48 मि0टन चावल और 43 हजार 1.297 मि0टन दाल मुफ्त उपलब्ध कराया गया है । साथ ही विस्तारित प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना अन्तर्गत माह जुलाई, 2020 से नवम्बर, 2020 तक प्रत्येक लाभुकों को राशन कार्डधारी परिवार के प्रति सदस्य को प्रतिमाह 5 किलो खाद्यान्न और 2 कि0ग्रा0 गेहूं और 3 कि0ग्रा0 चावल उसमें सम्मिलित था तथा प्रत्येक परिवार को 1 कि0ग्रा0 साबुत चना उपलब्ध कराया गया । अध्यक्ष महोदय, इसके अन्तर्गत कुल 4 लाख 35 हजार 481.705 मि0टन खाद्यान्न प्रति माह जुलाई, 2020 से नवम्बर, 2020 तक एवं कुल 77117. 149 मि0टन साबुत चना उपलब्ध कराया गया ।

अध्यक्ष : अब संक्षिप्त करें ।

श्री जनक सिंह : कोविड-19 से उत्पन्न आपदा की स्थिति में अन्य राज्यों से वापस आये हुए प्रवासी श्रमिकों आत्मनिर्भर भारत की तरह माह मई, 2020 एवं जून, 2020 में प्रति व्यक्ति को प्रतिमाह 5 कि0ग्रा0 खाद्यान्न चावल और प्रति परिवार को 1 कि0ग्रा0 साबुत चना मुफ्त उपलब्ध कराया गया है ।

क्रमशः

टर्न-16/ज्योति/09-03-2021

क्रमशः

श्री जनक सिंह : इस योजना के तहत कुल 86449.70 मैट्रिक टन चावल और 3381.76 मैट्रिक टन साबूत चना मुफ्त वितरण कराया गया है । अध्यक्ष जी, अन्य क्षेत्रों में भी आप एक ऐसा था हम तो कहते हैं अपने आदरणीय बिहार के सूबे के मुख्यमंत्री जी को हम सलाम करते हैं कि बिहार में जब कोई भी माननीय सदस्य अपने विधान सभा क्षेत्र में जाते थे, चाहे वह कोई पार्लियामेंट के सदस्य ही क्यों न हों, किस तरह से शराब पीकर लोग सदन के सदस्यों को अपमानित करने का काम करते थे, वह दिन याद कीजिये और आज...

अध्यक्ष : आप बैठ जाईये ।

श्री जनक सिंह : आज खुलेआम रुप से घूम रहे हें और आज सरकार के सामने, हमारी सरकार के सामने, इस प्रकार की बात करते हैं इसलिए अंत में हम यही कहेंगे

अध्यक्ष महोदय, कि विरोधी पक्ष को चाहिए कि आज जो कटौती प्रस्ताव लाए हैं उनको वापस लेना चाहिए राज्य हित में राष्ट्र हित में । जयहिंद , जय भारत ।

अध्यक्ष : श्री विजय कुमार सिंह उर्फ डब्लू सिंह ।

श्री विजय कुमार सिंह उर्फ डब्लू सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, आज मैं विपक्ष के द्वारा लाए गए कटौती प्रस्ताव के पक्ष में बोलने के लिए खड़ा हूँ । में इसके लिए आपको, हम अपने नेता माननीय लालू प्रसाद यादव जी को, नेता, प्रतिपक्ष भाई तेजस्वी प्रसाद यादव जी को और राष्ट्रीय जनता दल के सभी नेताओं को मैं दिल से धन्यवाद देता हूँ कि आपलोगों ने अवसर दिया और इस अवसर लायक मुझे नवीनगर और बारुन की जनता ने बनाया । मैं उनको दिल से धन्यवाद देता हूं। आज बिजली पर कटौती प्रस्ताव के पक्ष में बोलने के लिए मैं खड़ा हूँ । मैं जिस विधान सभा क्षेत्र से आता हूँ, वह विधान सभा क्षेत्र नवीनगर है और नवीनगर की नयी पहचान अगर आप देखेंगे तो इस बिहार में ही नहीं पूरे हिन्दुस्तान के अंदर में और खस करके बिजली के क्षेत्र में जिस विधान सभा क्षेत्र में, जिस ब्लौक में दो दो एन.टी.पी.सी. प्लान्ट हैं दोनों प्लान्ट को अगर मिला दिया जाय तो 51 सौ मेगावाट बिजली वहाँ पर पैदा होनी है । यह हमलोगों के लिए सौभाग्य की बात है कि हमलोगों ने दोनों परियोजनाओं को लगाने में हमारे क्षेत्र की जनता ने, हमारे किसानों ने, हमारे नौजवान भाईयों ने, मजदूरों ने सबों ने मदद की और मैं धन्यवाद देता हूँ उनको लेकिन अगर आज अब हमलोग देखते हैं, मैं याद करता हूँ उस समय को, जब मैं यहाँ इससे पहले 2005 से 2010 में जब विधायक था, उस समय में यू.पी.ए. की सरकार थी और पहली परियोजना बी.आर.बी.सी.एल. जिसको आज हमलोग पढ़ रहे थे, मैं पढ़ रहा था तो उस समय पहली परियोजना यू.पी.ए. सरकार के समय में हमलोगों ने उस समय वहाँ पर स्थापित कराने का काम किया था जो रेलवे के साथ ज्वायंट वेंचर में था । यह हमलोगों का सौभाग्य रहा कि हमलोगों ने वहाँ पर उस प्लान्ट को लगाने में सहयोग किया और उस समय हमारे जिले के निखिल बाबू थे, वो लोग हमलोगों को समझा रहे थे कि आपलोग माननीय विधायक हैं, आपलोग क्षेत्र में जाईये और उस प्लान्ट को लगवाने में मदद कीजिये । हमलोग उस समय घूमते थे, गांव और देहात में घूमते थे और लोगों को बताते थे कि अगर हमलोगों के क्षेत्र में यह प्लान्ट लग जाता है तो हमलोगों का विकास होगा । हमलोग आज राष्ट्र के निर्माण के लिए आगे बढ़ेंगे और नाम स्वर्णाक्षरों में लिखा जायगा लेकिन आज मैं पूछना चाहता हूँ इस सदन में, आज मैं माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यहाँ बैठे हुए माननीय मंत्री जी से मैं पूछना चाहता हूँ कि कभी भी, कोई दो दो एन.टी.पी.सी. प्लान्ट है, कभी

कोई दो दो एन.टी.पी.सी. प्लान्ट है, कभी भी कोई सुध लेने के लिए नहीं गया, कोई यह देखने के लिए नहीं गया ..

अध्यक्ष : माननीय सदस्य नियमावली मे है कि वाद-विवाद पर प्रभाव डालने के प्रयोजन के लिए राष्ट्रपति, राज्यपाल, उप राज्यपाल के नाम का उपयोग नहीं करेंगे, इसको ध्यान में रखेंगे ।

श्री विजय कुमार सिंह उर्फ डब्लू सिंह : ठीक है, मैं इसके लिए खेद प्रकट करता हूँ । लेकिन कोई सुध लेने के लिए जाने के लिए तैयार नहीं हुआ । हम देखते रह गए कि जिस तरीके से वहाँ पर जमीन अधिग्रहण का मामला हो, जमीन अधिग्रहण जब हो रहा था किसानों का और जिस समय यह जमीन अधिग्रहण हो रही थी मुझे याद है वह समय 2007 जब पूरे हिन्दुस्तान में सिंगूर का मामला चल रहा था और पूरे हिन्दुस्तान के अंदर में सिंगूर का नाम गूंज रहा था वहाँ पर उस समय कोई किसान जमीन देने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन 1001 किसान एक दिन में सहमति पत्र देने का काम किए वो नवीनगर के ही किसान थे, जो सहमति पत्र एक बार में देने का काम किये । उस समय वहाँ के तत्कालीन डी.एम. श्री वीर बहादुर पाण्डेय जी थे उन्होंने कहा था कि यहाँ के जो किसान सहमति पत्र भरे हें इनके लिए मेरे पास शब्द नहीं है लेकिन हमलोग जानते थे, हमलोग जान रहे थे कि जो आने वाला समय है, यह बड़ा जद्दोजहद का रहेगा और इनकी अब जो आवाज होगी, इनकी आवाज को दबाया जायेगा । उस क्षेत्र के नौजवानों को दबाया जायेगा और हुआ भी वही । हमलोगों ने राष्ट्र के निर्माण में अपनी जमीन दी है । हमलोगों ने जमीन बेची नहीं थी, अपनी जमीन अधिग्रहण करवायी और उस अधिग्रहण में हमलोगों का दायित्व था, आपका दायित्व बनता था कि उन लोगों के साथ उचित न्याय हो । अगर उचित न्याय के लिए अगर वो किसान लड़ते हैं, मुझे याद है अभी भी माननीय नीतीश जी यहाँ पर नहीं मौजूद हैं लेकिन इनको भी याद होगा कि 2011 में माननीय नीतीश जी जब एन. पी.जी.सी. के लिए गए थे, एन.पी.जी.सी. जो बिहार के साथ ज्वायंट वेंचर था आज बिहार के साथ ज्वायंट वेंचर टूट गया । आज पूरा का पूरा एन.टी.पी.सी. अपने से उसके परियोजना को चला रही है लेकिन 2011 को मैं याद करता हूँ, 2011 में माननीय नीतीश जी गए थे वहाँ पर किसानों से बात करने के लिए सहमति नहीं बनी लेकिन किसान अगर वहाँ पर विरोध कर रहे थे तो वहाँ पर बैठे हुए पुलिस पदाधिकारियों ने वहाँ पर गोली चलवाने का काम किया और वहां पर हमारे किसानों के ऊपर में जिस तरीके से वहाँ पर गोली चली, लाठी चली हमलोग वहाँ उसका पुरजोर विरोध कर रहे थे, पुरजोर विरोध हो रहा था किसानों ने आवेश में आकर पूरा क्रेन जला दिया तब नीतीश जी को मालूम

हुआ कि नहीं यहॉ के किसान जमीमन देते हैं तो हक लड़ के लेना भी जानते हैं और उसका नतीजा यह निकला कि 1000 बीधा जो गैर मजरुआ जमीन थी माननीय नीतीश जी ने उस समय आनन फानन में कह दिया जो 1000 बीघा जो गैर मजरुआ जमीन है, जो मालिक गैर मजरुआ जमीन है 30 वर्ष का जिसका दखल कब्जा है, जिस किसान का 30 वर्ष का जिसका दखल कब्जा है उसको पेमेंट मिलेगा लेकिन हुआ क्या ? आज भी मैं दावे के साथ कहता हूँ मात्र 25 प्रतिशत किसानों को ही मिला है और आज किसान दर बदर घूम रहा है । कभी कलेक्ट्रेट में घूमता है, अब तो एन.टी.पी.सी. प्लान्ट का बाउन्ड्री बन गया है बड़ी बड़ी सी.आई.एस.एफ. की पुलिस और थाना लग गया है वहॉ पर और कोई किसानों को अंदर जाने नहीं देता है और अपनी बातों को रखने नहीं देता है । यह बड़े अफसोस की बात है जो किसान राष्ट्र के निर्माण के लिए आगे अपना पॉव चलकर अपने खून पसीना से कमायी हुई जमीन को देने का काम किया उनलोगों के साथ यह व्यवहार हो रहा है । खासकर अपने उस क्षेत्र के नौजवानों की बात करते हैं तो एन.टी.पी.सी. के द्वारा शुरु में यह कहा गया था कि आपलोग हमलोगों को सहयोग कीजिये । आप लोगों को डिप्लोमा करायेंगे, डिग्री करायेंगे और आप लोगों को हम लोग नियोजित करेंगे, हमलोग इसमें रोजगार देने का काम करेंगे । आज हमारे क्षेत्र के जितने लड़के हैं, वहॉ पर खास करके जो प्रभावित हैं, जो विस्थापित हैं, उन लोगों को एन.टी.पी.सी. ने डिप्लोमा और आई. टी.आई. कराने का काम किया लेकिन नौकरी देने का काम नहीं किया । आज वो भी लड़के अपनी जमीन देकर रोड पर घूम रहे हैं । आज अगर आप देखेंगे खास करके किसानों को अगर उसके जमीन का दाम मिला तो उस जमीन पर काम करने वाले मजदूरों के बारे में, मजदूरों के मामले में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो उस मजदूर की कोई गलती नहीं ।

(इस अवसर पर माननीय सभापति, श्री नरेन्द्र नारायण यादव ने आसन ग्रहण किया)

सभापति (श्री नरेन्द्र नारायण यादव): माननीय सदस्य, आपके पास मात्र एक मिनट का वक्त है अपना भाषण कंक्लूड करें ।

श्री विजय कुमार सिंह उर्फ डब्लू सिंह : उन मजदूरों के बारे में सोचिये जो उस जमीन पर काम करते थे । वहॉ पर एन0टी0पी0सी0 की पॉलिसी है कि 750 दिन का एक मुश्त पेमेंट एन.टी.पी.सी. को देना है लेबर को लेकिन आज तक विगत 10 साल के दरम्यान में जिला प्रशासन आज तक यह नहीं पता लगा पायी कि ये मजदूर हैं कौन ? रोज लिस्ट बनती है और रोज फट जाती है खास करके अगर अपना इस हिन्दुस्तान को इस बिहार को अगर हमलोगों ने अपनी जमीन देने का काम

किया, हमारे किसानों ने जमीन देने का काम किया है तो उनका भी हक बनता था कि उनके विकास के लिए जो पैसा आता है, एन.टी.पी.सी. के द्वारा पैसा दिया जाता है, वहॉ दो पॉलिसी चलती है, एक आर.एन.आर. पॉलिसी चलती है। जब कोई भी प्रोजेक्ट बनता है तो उस समय आर.एन.आर. प्रोजेक्ट के तहत क्षेत्र का विकास का काम किया जाता है । लेकिन बहुत अफसोस के साथ मुझे यह कहना पड़ता है ।

टर्न-17/अभिनीत-पुलकित/09.03.2021

सभापति (श्री नरेन्द्र नारायण यादव): माननीय सदस्य, अब आप अपना आसन ग्रहण करें ।

श्री विजय कुमार सिंह उर्फ डब्लू सिंह: महोदय, हमारे बिहार राज्य में माननीय पावर मिनिस्टर हैं, आरा से सांसद हैं, भारत सरकार के मंत्री हैं लेकिन जो भारत सरकार के मंत्री हैं उनसे मैंने हमेशा आग्रह किया कि माननीय मंत्रीजी..

सभापति (श्री नरेन्द्र नारायण यादव): अब आप आसन ग्रहण करें ।

श्री विजय कुमार सिंह उर्फ डब्लू सिंह: जो आप कर रहे हैं, वह बहुत गलत है । आप बिहार के ही नहीं पूरे भारत के मिनिस्टर हैं, आपको अपने क्षेत्र का विकास करना है तो एन0टी0पी0सी0 परियोजना का पैसा बाहर मत ले जाइये । यह हमलोगों के खून-पसीने का पैसा है, हमारे क्षेत्र का पैसा है, इसको हमारे क्षेत्र में ही रहने दीजिए लेकिन कोई सुध लेने वाला नहीं रहा । माननीय मुख्यमंत्री जी यहां आने वाले हैं ।

सभापति (श्री नरेन्द्र नारायण यादव): माननीय सदस्य अपना आसन ग्रहण करें । माननीय सदस्य श्री सुधांशु शेखर जी ।

श्री सुधांशु शेखर: माननीय सभापति महोदय, मैं कटौती प्रस्ताव के विरोध में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं । मैं इसके लिए अपने नेता माननीय मुख्यमंत्री एवं उप मुख्यमंत्री जी का आभार प्रकट करता हूं । साथ ही हमारे मुख्य सचेतक श्रवण कुमार जी का भी आभार प्रकट करता हूं । मैं अपने हरलाखी विधान सभा क्षेत्र के सभी मतदातागणों का, मुझे दोबारा इस सदन में भेजने के लिए अभिनंदन और स्वागत करता हूं ।

आज विद्युत के क्षेत्र में, विद्युत आपूर्ति में गुणवत्ता एवं अवधि में बढ़ोत्तरी के कारण राज्य में बिजली की मांग में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है । बिजली की अधिकतम मांग जो सितम्बर, 2018 में 5,139 मेगावाट थी, वहीं सितम्बर, 2019 में बढ़कर 5,891 मेगावाट हो गयी है । पुन: नयी ऊंचाई को छूते हुए वर्तमान वित्तीय वर्ष के माह जुलाई, 2020 में बढ़कर 5,932 मेगावाट तक पहुंच गयी है । बिजली के क्षेत्र में उत्पादन लखीसराय एवं पीरपैंती, भागलपुर में 250-250 मेगावाट क्षमता की सौर ऊर्जा परियोजना की स्थापना की जानी है, जो

राज्य में ग्रीन पावर की विकास की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा । बक्सर में सतजल, जल विद्युत निगम के द्वारा 660 मेगावाट से उत्पादन प्रारंभ करने का लक्ष्य है, जिससे बिहार को 85 प्रतिशत बिजली प्राप्त होगी । सभापति महोदय, एन0टी0पी0सी0 द्वारा औरंगाबाद जिले के नवीनगर में निर्माणाधीन 660 मेगावाट की तीन इकाईयों में प्रथम इकाई से उत्पादन प्रारंभ हो चुका है तथा इससे बिहार को 515 मेगावाट बिजली प्राप्त हो रही है । सभापति जी, वर्ष 2014 में माननीय मुख्यमंत्री, नीतीश जी ने कहा था कि अगर घर-घर बिजली नहीं पहुंचा पाया तो चुनाव नहीं लडूंगा । हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस वादा को पूरा करके दिखाया है ।

सभापति महोदय, वर्ष 2005 के पूर्व बिजली कभी-कभी आती थी लेकिन आज शहर हो या गांव 22 घंटे बिजली सप्लाई होती है । आज बिहारवासियों को बिजली की भरपूर सप्लाई मिल रही है और इसी का नतीजा है कि बिहार से लालटेन विलुप्त होने के कगार पर है । वर्ष 2005 के पहले ट्रांसफार्मर जल जाने पर 2 से 3 महीने के बाद लगता था लेकिन आज वैसी स्थिति नहीं है, आज 24 घंटे के अंदर हमारे जो ट्रांसफार्मर जल जाते हैं, वे लग जाते हैं । पहले बिजली विभाग द्वारा उपभोक्ताओं को जो बिल मिलता था, यदा-कदा गलत बिल आ जाता था । इसको दूर करने के लिए बिहार सरकार द्वारा स्मार्ट मीटर लगाने की योजना शुरू की गयी है । अभी तक राज्य में कुल 1 लाख 6 हजार 773 स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाये जा चुके हैं । हर घर तक बिजली पहुंचाने के लिए राज्य सरकार ने मुफ्त कनेक्शन देने की भी योजना बनायी है । महोदय, इसी का परिणाम है कि आज के दिन सुदूर इलाके में भी गांव तक बिजली कनेक्शन पहुंचा दिया गया है ।

महोदय, मेरे क्षेत्र की कुछ समस्याएं हैं । मेरे हरलाखी विधान सभा के कलना पंचायत में ग्राम कुंडलमंढ़िया और बलवा टोल में अभी भी पुराना तार नहीं बदला गया है । मैं चाहूंगा कि उसको जल्द पूरा किया जाय । सभापति महोदय, हमारा एक मधुआपुर ब्लॉक है, वहां सहार दक्षिणी पंचायत नायक टोल और कबाड़ी टोल में भी तार जर्जर पड़ा हुआ है और ट्रान्सफार्मर की कमी है । मैं चाहूंगा कि यहां विद्युत विभाग के पदाधिकारी लोग उपस्थित हैं, इसको नोट करके लगाने का काम करेंगे । मुझे सदन में बोलने का मौका मिला इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका आभार प्रकट करता हूँ ।

सभापति (श्री नरेन्द्र नारायण यादव): माननीय सदस्य, श्री भरत बिन्द जी । आपका समय दस मिनट है ।

श्री भरत बिन्द: सभापति महोदय, सबसे पहले मैं आपका आभार व्यक्त करना चाहता हूँ । महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया है । मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी का जिन्होंने मुझे यहां तक भेजने में अहम भूमिका निभाई है । प्रतिपक्ष के नेता माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी का मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ और पार्टी के मुख्य सचेतक, ललित कुमार यादव जी का भी आभार प्रकट करता हूं ।

आज मैं खाद्य एवं आपूर्ति विभाग द्वारा पेश आय-व्यय के बजट के परिप्रेक्ष्य में कटौती प्रस्ताव का पुरजोर समर्थन करता हूँ । महोदय, राज्य के गरीब वंचित, बेसहारा लोगों के लिए खाद्यान्न की आपूर्ति के चयन को बनाये रखने के लिए खाद्य एवं आपूर्ति विभाग की स्थापना की गई है । विभाग के नाम के साथ ही एक शब्द 'स' अक्षर जुड़ा हुआ है, जो राज्य की जनता के अधिकारों को संरक्षित करने के लिए है लेकिन सरकार जनता के अधिकारों को संरक्षित करने में विफल रही है । राज्य के खाद्य आयोग ने भी शायद सरकार से, आठ साल पूर्व से आयोग की रिपोर्ट नहीं मांगी है, क्योंकि राज्य में पहली बार वर्तमान खाद्य आयोग ने अपनी जांच रिपोर्ट दी है । सरकार ने अपने उत्तर में यह स्वीकार किया है कि मेरे पास कोई आयोग की रिपोर्ट नहीं आई है, जिसमें यह कहा गया है कि राज्य में खाद्य आपूर्ति के गोदामों से उपभोक्ता तक जाते-जाते प्रति क्विटंल 20 किलोग्राम अनाज में कमी हो जाती है, जबकि राज्य खाद्य आयोग के अध्यक्ष ने मधुबनी, दरभंगा आदि जिलों की जांच में पाये गये घटतौली की, दरभंगा में प्रेस वार्ता कर चुके हैं ।

महोदय, राज्य कोरोना की महामारी से पीड़ित रहा है । हजारों गरीब परिवारों की नौकरी चली गयी, लाखों लोग खाने-पीने से वंचित हुएं तथा जान भी गंवायें हैं । सरकार ने इसी बीच प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी तथा जन वितरण प्रणाली के विक्रेताओं को एक नई कमाई का साधन भी दे दिया । महोदय, गलत राशनधारी के नाम पर उन लोगों का नाम उपभोक्ता सूची से हटाया जा रहा है, जो सही लाभुक हैं । वे गलत लोग अभी भी उस सूची में जुड़े हुए हैं, जो धनाढ्य हैं या उनकी पहुंच, डीलर अथवा प्रखंड आपूर्ति कार्यालय से है । महोदय, इतना ही नहीं उन गरीबों को सरकारी राशन नहीं मिल रहा है, जिनके पास एकमात्र सरकारी राशन का माध्यम है । डीलर उन सभी उपभोक्ताओं का राशनकार्ड जमा कराकर उनके कार्ड को भर देते हैं तथा लाभुकों को डांट-फटकार कर भगा देते हैं और एक अच्छी खासी आमदनी जमा कर लेते हैं । महोदय, बेहद लाचार, नि:सहाय एवं हाशिये पर समाज है, यह सत्यापन के नाम पर ठगा जा रहा है ।

(क्रमश:)

टर्न-18/हेमन्त-धिरेन्द्र/09.03.2021

...क्रमशः...

श्री भरत बिन्द : यह वर्ग ज्यादातर निरक्षर होने के कारण आधार सत्यापन के नाम पर हटा दिये जाते हैं वहीं दूसरी तरफ चालाक लोग स्थानीय कर्मचारी हों या डीलर से मिलकर सॉफ्टवेयर की कमी का फायदा उठाते हुए अवैध तरीके से अपना नाम खाद्यान्न सूची में जुड़वा लेते हैं ।

महोदय, खाद्य आपूर्ति मंत्रालय द्वारा मुख्यतः बिहार के भीतर उत्पादित खाद्यान्न की खरीद, न्यूनतम मूल्य पर खरीद के साथ गरीब लोगों को उचित मात्रा में कम कीमत पर खाद्यान्न उपलब्ध कराने का मुख्य कार्य है । इस महती कार्य हेतु बिहार सरकार को 32 लाख टन चावल एवं 22 लाख टन गेहूं की आवश्यकता है। इसकी पूर्ति हेतु बिहार में किसानों के द्वारा 1 करोड़ 65 लाख हजार टन के उत्पाद का दावा बिहार सरकार करती है । अगर बिहार के किसानों के द्वारा उत्पादित खाद्यान्न का एक तिहाई भी खरीद हो जाता, तो बाहर से लाकर खाद्यान्न नहीं देना पड़ता, जिससे बिहार के किसानों को हजारों-करोड़ों के फायदे के साथ-साथ गरीबों को बिहार में ही उत्पादित खाद्यान्न का स्वाद चखने को मिलता । बिहार के मुख्यमंत्री माननीय श्री नीतीश कुमार जी की इच्छा थी कि बिहार के किसानों द्वारा उत्पादित खाद्यान्न देश के सभी नागरिकों की थाली में बिहार का एक आईटम उपलब्ध हो । इस सपने को पूरा करने के लिए द्वितीय कृषि रोड मैप में एक लाख 54 हजार करोड़ रुपये के भारी-भरकम बजट का प्रावधान किया गया था । यह सपना आज भी वास्तविक धरातल से हजारों किलोमीटर दूर दिखाई पड़ता है, जबकि वास्तविकता है कि गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों के लिए अनाज आज भी दूसरे प्रान्तों से आयात पर निर्भर है । इससे ज्यादा शर्म का विषय हो ही नहीं सकता । या तो बिहार सरकार को राज्य के किसानों के समर्थन पर विश्वास ही नहीं है या तो बिहार सरकार का भ्रष्ट सरकारी तंत्र मुख्यमंत्री के सपनों में पलीता लगाने का काम कर रहा है । इसका सबसे बड़ा ज्वलंत उदाहरण यह है कि एक तरफ बिहार में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान खरीद का पाखंड रचा जा रहा था वहीं दूसरी तरफ अकेले गया और औरंगाबाद से सस्ती दर पर व्यापारियों द्वारा सैंकड़ों लाखों टन धान खरीदकर पंजाब एवं हरियाणा में लाया गया है । जिसकी सरलता से जांच की जा सकती है । रेलवे एवं जी.ए.टी. कार्यालय से इसकी जांच की जा सकती है ।

महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि गरीब मजदूर, किसान जो गांव में बसे हुए हैं, आज सैंकड़ों साल से जहां बसे हुए हैं, एक छोटे से नोटिस पर उनके घर को गिरा दिया जाता है, जबकि पिछली सरकार ने तीन-तीन डिसमिल जमीन प्रत्येक गरीब को देने का वादा किया था । गांव में मैंने जाकर देखा कि सैंकड़ों घर ढहा दिये जाते हैं, जब जे.सी.बी. मशीन का बुकेट लगाकर उन गरीब के घरों पर वार किया जाता है, तो ऐसा लगता है कि कहीं हम लोगों के सीने पर वार हो रहा है । महोदय, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि सरकार ने जब तीन-तीन डिसमिल जमीन गरीबों को मुहैया की है, तो आखिरकार जमीन देने के पूर्व ही घरों को ढहाने का क्या औचित्य है ? महोदय, जहां कॉलोनी पास है, लाखों रुपया लगाकर सरकार ने कॉलोनी बनवायी है, उस कॉलोनी को ढहाने का क्या औचित्य है ? कहीं-न-कहीं...

सभापति(श्री नरेन्द्र नारायण यादव) : माननीय सदस्य, आपके पास मात्र एक मिनट का वक्त है। सरकार के सामने ऊर्जा से संबंधित अपना बहुमूल्य सुझाव रखें ।

श्री भरत बिन्द : सभापति महोदय, ऊर्जा के बारे में मैं बताना चाहता हूँ कि हमलोग, गरीब लोग गांव में बसे हुए हैं । मैं वहां देखता हूँ कि किसी गरीब परिवार का 25 हजार का बिजली बिल, किसी का 30 हजार का बिजली बिल एक बार में भेजा जाता है। महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ कि अगर उन गरीबों ने मात्र एक बल्ब जलाया है, तो उन्हें 25 हजार, 30 हजार का बिल भेजने का क्या औचित्य है ? महोदय, यह बहुत ही गंभीर मामला है, क्योंकि गांव में हमलोग जाते हैं, तो गांव में बसे गरीब लोग दौड़ कर चले आते हैं कि...

सभापति (श्री नरेन्द्र नारायण यादव) : माननीय सदस्य आपका समय हो गया है, अपना भाषण समाप्त करें ।

श्री भरत बिन्द : विधायक जी, हमलोगों का बिजली बिल इतना आया है । इसलिए, मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूँ कि गरीबों का बिजली बिल माफ किया जाय । धन्यवाद । जय हिन्द ।

सभापति (श्री नरेन्द्र नारायण यादव) : माननीय सदस्य श्री मिथिलेश कुमार । आपके पास 10 मिनट का वक्त है ।

श्री मिथिलेश कुमार : माननीय सभापति महोदय, आज लोकतंत्र के पवित्र मंदिर में विश्व की विशिष्टतम धरती सीता प्रकट स्थली सीतामढ़ी की जनता ने आशीर्वाद देकर भेजा है। उसके लिए मैं सीतामढ़ी की जनता के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ और समय ने ऐसा संयोग लिया कि विश्व की सम्पूर्ण ऊर्जा का स्रोत, जो जगत जननी जानकी है, उस धरती के पुत्र को ऊर्जा पर बोलने का सदन में अवसर मिला ।

''या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता ।
नमस्तस्यै, नमस्तस्यै, नमस्तस्यै, नमो नमः ।।''

ऊर्जा से ही सम्पूर्ण विश्व का संचालन होता है । ऋग्वैदिक काल में ऊर्जा का मुख्य स्रोत सूर्य को माना गया है और हम जिस विचारधारा के कार्यकर्ता हैं । माननीय श्री अटल बिहारी वाजपेयीजी ने वर्षों-वर्ष पहले कहा था बम्बई के अधिवेशन में-

''ऐ हिन्दुस्तान के वैज्ञानिकों, क्या कर रहे हो, किस चिंतन में लगे हो, तुम्हारा चिंतन किस दिशा में जा रहा है, सूर्य की ऊर्जा का क्षय हो रहा है, सूर्य की ऊर्जा का उपयोग करो ।''

यह दूरदर्शिता, यह योजनाबद्ध कार्यशैली हमारे संगठन के कार्यकर्ता को सीख से मिलती है । उसका परिणाम है कि आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, अटल जी की संगति में केन्द्र सरकार में उनका सानिध्य मिला और वैसे भी माननीय मुख्यमंत्री जी इंजीनियर हैं । ऊर्जा के संबंध में केन्द्र की सरकार और राज्य की सरकार ने सम्मिलित रूप से जो योगदान दिया, वह विश्व के पैमाने पर बिहार खड़ा है । सभापति महोदय, ऊर्जा के विषय में मुझे लगता है कि सम्पूर्ण विश्व के संदर्भ में भारत अग्रणी भूमिका अदा करेगा । केन्द्र की अद्वितीय योजना पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, इस योजना से सभी बी0पी0एल0 परिवारों को जहां लालटेन में तेल की दिक्कत होती थी, डिबिया में तेल की दिक्कत होती थी, जहां उनको खाने के समय रौशनी नहीं रहती थी, सभी घरों में बिजली के बल्ब लटक गये और मैं यह दावा करता हूँ कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की केन्द्र और राज्य सरकार में बिहार के 80 प्रतिशत से ज्यादा घर बिजली से आच्छादित हैं और 80 प्रतिशत से ज्यादा घरों में बिजली के बल्ब लटकते हैं ।

महोदय, आई0पी0डी0एस0 योजना (इंटीग्रेटेड पॉवर डेवलपमेंट स्कीम), जिसके तहत अर्बन एरिया में पहले 8-10 घंटा बिजली मिलती थी और आज वर्तमान समय में हम 23-24 घंटा बिजली देते हैं । सभापति जी, रुरल एरिया में पहले 4-6 घंटा बिजली मिलती थी और आज 20-22 घंटा बिजली उपलब्ध रहती है । केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण ने 6,576 मेगावाट की मांग की कल्पना की थी, यह विद्युत के सुदृढ़ीकरण का परिणाम है । श्री नरेन्द्र मोदी जी ने सौभाग्य योजना दी, इस योजना के तहत बी0पी0एल0 परिवारों के घरों में विद्युतीकरण हो गया । सभापति जी, बिजली के क्षेत्र में हमारे यहां कई विकास के कार्य हुए हैं, वैसे मेरे पास पूरा बजट है । मैं पूरे हाउस में इसको रख सकता हूँ, यह पूरा एकदम सरकारी और प्रैक्टिकल, व्यावहारिक सभी रूप से अधिकृत है ।

...क्रमशः...

टर्न–19/सुरज–संगीता/09.03.2021

...क्रमशः...

श्री मिथिलेश कुमार : मैं बता दूं कि जिस समय में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन वर्ष 2005 में सत्ता में आई थी उस समय ग्रिड सबस्टेशन की संख्या पूरे राज्य में मात्र 45 थी और आज 154 है । संरक्षण लाइन की कुल लंबाई 5 हजार सी.के.एम. थी और आज 16 हजार 988 सी.के.एम. है । ट्रांसमिशन इवैक्यूशन कैपेसिटी 1 हजार किलोवाट थी आज 12 हजार 752 किलोवाट है । पिकआवर में डिमांड 7 सौ मेगावाट थी आज 5392 मेगावाट है । शक्ति उपकेन्द्रों की संख्या 268 थी वर्ष 2005 में आज 1131 है । उपभोक्ताओं की संख्या वर्ष 2005 में 24 लाख थी आज 167.31 लाख है । विद्युतीकरण राजस्व गांव की संख्या 12 हजार 565 थी आज 39 हजार 73 है । विद्युतीकरण टोलों की संख्या वर्ष 2005 में कोई उसकी गिनती नहीं थी आज 1 लाख 6 हजार 249 है ।

सभापति जी, कृषि के क्षेत्र में जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय के एकात्म मानववाद का सपना जो समाज के अंतिम पायदान पर बैठे हुए लोगों की चिंता की जिसमें अवधारणा थी एकात्म मानववाद में, उस चिंतन के तहत प्रति 2 कट्ठे में डीजल से सिंचाई का व्यय 20 रुपये पड़ता है और हमने दीनदयाल उपाध्याय विद्युतीकरण योजना के तहत किसानों के हर खेत में बिजली पहुंचाने का काम करके 20 रुपये की जगह 0.82 पैसे से प्रति 2 कट्ठे की सिंचाई की व्यवस्था दिये हैं ।

सभापति जी, कजरा और पीरपैंती में ढाई सौ मेगावाट क्षमता का हमने जो ग्रीन पावर सौर ऊर्जा परियोजना की स्थापना करने जा रहे हैं उसमें हमलोग प्रदूषण से मुक्त, सोलर युक्त बिजली उत्पादन की व्यवस्था करने वाले हैं । एन0टी0पी0सी द्वारा औरंगाबाद जिला के नवीनगर में निर्माणाधीन 660 मेगावाट की 3 इकाइयों में प्रथम इकाई से वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ हो चुका है ।

सभापति जी, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना में डीजल चालित कृषि पंप सेटों तथा नये कृषि पंप सेटों को विद्युत सम्बद्ध प्रदान किया जा रहा है ।

सभापति जी, 7–निश्चय में हर घर बिजली योजना में पूर्ण सफलता प्राप्त है । टारगेट डेट हमारा दिसंबर, 2018 था और हमने टारगेट प्राप्त कर लिया अक्टूबर, 2018 में, यह हमारे एन0डी0ए0 के विकास की अवधारणा है, यह हमारे एन0डी0ए0 के विकास का आईना है, यह हमारी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार की कार्यशैली है ।

सभापति (श्री नरेन्द्र नारायण यादव) : आपके पास मात्र एक मिनट का वक्त बचा है । अपने क्षेत्र की समस्या भी रखें ।

श्री मिथिलेश कुमार : हमारे क्षेत्र में ऊर्जा संबंधी कोई समस्या नहीं है, सभापति जी । मुख्यमंत्री नवीन एवं नवीकरण ऊर्जा योजना के अंतर्गत बिहार के विभिन्न जिलों में 7.027 मेगावाट पावर सोलर पावर प्लांट के अधिष्ठापन का कार्य किया जा चुका है । राज्य के शहरी एवं ग्रामीण निजी आवासीय भवनों में 113 भवनों पर 583 किलोवाट पावर क्षमता का ग्रिड पावर सोलर प्लांट के अधिष्ठापन का कार्य किया गया है । इसके साथ ही राज्य के विभिन्न सरकारी भवनों तथा माननीय उच्च न्यायालय एवं जिला सत्र न्यायालय सभी जगह हमलोग सोलर प्लांट की व्यवस्था कर रहे हैं ।

सभापति जी, एक अद्‌भुत योजना 'नीचे मछली ऊपर बिजली' यह किसी की परिकल्पना में नहीं होगा । इस योजना के तहत दरभंगा जिले में 2 MWP फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट का अधिष्ठापन एवं सुपौल जिला में 525 किलोवाट पावर फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट का अधिष्ठापन कार्य प्रगति पर है ।

सभापति जी, सोलर स्ट्रीट लाइट योजना भी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की अद्‌भुत योजना है जहां सभी सड़कें चमचमाती नजर आएंगी अपराध कम होंगे...

सभापति (श्री नरेन्द्र नारायण यादव) : अब आप अपना आसन ग्रहण करें ।

श्री मिथिलेश कुमार : सभापति जी, बस अंतिम बात मैं निबंधन के क्षेत्र में कहूंगा । निबंधन के क्षेत्र में भी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने अद्‌भुत फैसला लिया है । जहां पारिवारिक संपत्ति के बंटवारे में हजारों पैसे व्यय होते थे, वहां मात्र 50 रुपये के स्टाम्प पर निबंधन का कार्य होता है । धन्यवाद । जय हिन्द, जय भारत, जय भारतमाता ।

सभापति (श्री नरेन्द्र नारायण यादव) : माननीय सदस्य, श्री अमरजीत कुशवाहा जी ।

श्री अमरजीत कुशवाहा : माननीय सभापति महोदय, मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने बोलने का मौका...

सभापति (श्री नरेन्द्र नारायण यादव) : आपके पास सिर्फ 2 मिनट का वक्त है ।

श्री अमरजीत कुशवाहा : दिया है । साथ ही साथ पार्टी के विधायक दल के नेता महबूब आलम जी का भी और जीरादेई की उस महान धरती, जहां से भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेन्द्र प्रसाद की जन्मभूमि है, वहां की जनता ने हमें चुनकर के और खासकर तब जब मैं लगभग साढ़े 5 साल से जेल में हूं, भारी मतों से जीताकर इस सदन में भेजा है इसके लिए उनको भी मैं बधाई देना चाहता हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं । आज कटौती प्रस्ताव के पक्ष में बोलने के लिए मैं खड़ा

हूं और खासकर के बिजली के क्षेत्र में अभी हम सुन रहे थे, सरकार ने अनुदान का मांग भी किया है और सत्ता पक्ष के लोग पूरी उपलब्धियों की चर्चा कर रहे थे लेकिन मैं देख रहा हूं सरकार की जो नीयत है, सरकार की जो नीति है, इन नीति और नीयत दोनों में खोट दिखाई दे रहा है । एक तरफ सरकार पूरे बिजली क्षेत्र को प्राईवेट कंपनियों के हवाले कर रही है । बिहार में तमाम संसाधनों की उपलब्धता के बावजूद हर साल बिहार में बाढ़ आती है, बड़े पैमाने पर पानी बर्बाद होता है उसको रोक करके वाटर पॉवर लगाने के बजाय आज भी 15 साल की सरकार ने बिहार में अपना बिजली का उत्पादन शुरू नहीं किया और सबसे महंगा दर से बिजली खरीदकर बिहारवासियों को दावा कर रहे हैं कि हम घर-घर बिजली दे रहे हैं और इसका नतीजा है महोदय, पूरे बिहार के भीतर जो सरकार की योजना चल रही है, गरीब लोग बिजली से वंचित हैं और एक बात जो लगातार सदन में आ रहा है, सारे हमारे भाई पक्ष-विपक्ष दोनों चितिंत हैं कि पूरे बिहार में लगातार फर्जी बिल आ रहा है, मीटर का कोई रिडिंग नहीं है, एक महीना पर या छह महीना पर जो सूचना देना चाहिए, वह नहीं मिलता है और एक बार में 20 हजार, 30 हजार, 40 हजार ऐसे करके जोड़कर के महोदय, बिल आ रहा है । भोजपुर जिला का एक सहार प्रखंड का मठिया टोला, वकील टोला गांव है जहां बी0पी0एल0 धारी परिवार हैं, वहां 20-20 हजार रुपये बिजली का बिल आया है महोदय, वे लोग कैसे दे पायेंगे तो हम समझ रहे हैं कि सरकार की नीयत जो न्याय के साथ विकास की बात, महादलित की बात, गरीब की बात करने की है तो सबसे पहले तो मैं कहना चाहता हूं गरीबों को मुफ्त बिजली देने की बात कहती है तो जितना भी फर्जी बिल आया है उसको माफ किया जाना चाहिए और साथ ही साथ महोदय, मैं यह भी कहना चाहता हूं कि अभी केंद्र सरकार ने जो नई बिजली बिल लायी है 2020, तो आप बिजली देने की, ऊर्जा देने की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ जो बिल लाये हैं, उसमें किसानों को बड़े महंगे दर पर बिजली मिलने की संभावना है जिसका सारे हिन्दुस्तान के किसान विरोध कर रहे हैं तो हम कहना चाहते हैं कि सबसे पहले किसानों को जो बिजली देना है, वह बिजली बिल किसानों को फ्री यानी कि किसानों को मुफ्त बिजली दिया जाये और कम से कम गरीबों को 100 यूनिट बिजली माफ किया जाना चाहिए । साथ ही साथ बिजली के क्षेत्र में हर जिला के अंदर यहां से एक कमिटी बनाकर के जांच हो और जहां-जहां फर्जी बिल आया हुआ है वहां उस फर्जी बिल को माफ करते हुए और खासकर के कोरोना काल में गरीबों का जहां काम छीन गया था और गरीबों के घर में बिजली बिल आ गया है, उनके पास पैसे नहीं है इसलिए मैं सदन के माध्यम से, सभापति महोदय के माध्यम से कहूंगा कि सरकार कम से कम इस दौर के बिजली

बिल को माफ करे । जहां तक हम देख रहे हैं कि मद्य निषेध के बारे में अभी हमारे बहुत सारे बंधु और सरकार भी दावा कर रही है कि पूर्ण शराबबंदी बिहार में लागू हो गया है ।

.....क्रमशः...

टर्न-20/मुकुल-राहुल/09.03.2021

क्रमशः

श्री अमरजीत कुशवाहा: इस योजना को लेकर बड़े जोर-शोर से बिहार में प्रचार भी चला तो सबसे पहले तो यह सरकार पूरे बिहार में पंचायत-पंचायत शराब की भट्टी ख ुलवाई, दूकानें खुलवाई, बेचवाने का काम किया और वर्ष 2016 में जब यह कानून लाया गया तो पूरे बिहार की जनता ने इसका समर्थन भी किया, सदन में भी पक्ष और विपक्ष ने समर्थन किया और हम लोगों को भी लगा कि आने वाले दिनों में लगता है कि बिहार शराब से मुक्त होगा । लेकिन आज हम देख रहे हैं, भले ही हमारे सत्तापक्ष के भाई लोग ऊपर से जो बोलते हों लेकिन आज की स्थिति यह है कि घर-घर होम डिलीवरी हो रहा है ।

सभापति (श्री नरेन्द्र नारायण यादव): माननीय सदस्य, सदन में माननीय सदस्य होते हैं, ये न भाई होते हैं न कुछ होते हैं, इसलिए माननीय सदस्य बोलें ।

श्री अमरजीत कुशवाहा: महोदय, सत्तापक्ष के जो माननीय सदस्य हैं उनके बारे में भी, तो हम कहना चाहते हैं कि होम डिलीवरी हो रहा है और बिहार के नौजवानों का भविष्य सबसे ज्यादा इस योजना के तहत बर्बाद हो रहा है । आज बिहार के सभी जेलों में बड़े पैमाने पर दारू के केस में बंद करके, शराब के केस में बंद करके लाखों की संख्या में नौजवानों की जिंदगी बर्बाद की जा रही है, गरीबों की जिंदगी बर्बाद की जा रही है और हम तो देख रहे हैं कि पूरा का पूरा यह धंधा सत्ता के संरक्षण में, ऑफिसर और माफियाओं के गठजोड़ के जरिये संचालित है और महोदय, मेरे पास तो एक एफ0आई0आर0 की कॉपी भी है कि बिहार सरकार के मंत्री श्री राम सूरत कुमार के पिता जी के नाम पर चलने वाला जो स्कूल है उस स्कूल से शराब का बड़ा खेप बरामद हुआ है । महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि मंत्री जी के भाई के नाम पर एफ0आई0आर0 दर्ज है, एफ0आई0आर0 की कॉपी भी हमारे पास मौजूद है । जहां पर जिस बिहार के अंदर मंत्री के संरक्षण में दारू बेचा जाता हो, बड़ा-बड़ा खेप उतारा जाता हो और उनके संरक्षण में थाना के अंदर, थाना मिलकर बड़ा-बड़ा खेप उतारता हो और वहां तो हम देखते हैं कि जो दारू पकड़ा जाता है उसके कुछ हिस्से को दर्शाया जाता है और उसके लिए भी दारू माफिया से पैसा लिया जाता है और जो बचता है उसे भी बेच दिया जाता है और उससे भी पैसा लेकर थानेदार करोड़पति बने हुए हैं और वह पैसा मंत्रियों तक जाता है । महोदय,

मैं कहना चाहता हूं कि सबसे पहले इसकी जांच होनी चाहिए और कार्रवाई होनी चाहिए और इसमें हम देख रहे हैं कि इन पर कार्रवाई के बजाय, बड़े-बड़े माफियाओं पर कार्रवाई के बजाय, थानेदारों पर कार्रवाई के बजाय, हो क्या रहा है तो गरीबों को फांसी की सजा दी जा रही है । महोदय, मैं कह रहा हूं कि शराब जो है कोई अपराध...

सभापति (श्री नरेन्द्र नारायण यादव): माननीय सदस्य, आपके पास मात्र एक मिनट का वक्त है।

श्री अमरजीत कुशवाहा: शराबबंदी कोई अपराध नहीं है, बल्कि एक सामाजिक बुराई है और मैं कहना चाहता हूं कि सरकार के अंदर सचमुच में शराब रोकने की योजना होती, नैतिकता होती तो इस पर इतना कड़ा कानून बनाने के बजाय व्यापक जागरूकता अभियान चलाया गया होता, गांव-गांव में अभियान चलाया गया होता और आज भी शराब मुक्ति कोई भी केन्द्र नहीं खोला गया है ये सारी चीजें हैं । इसलिए हम कहना चाहते हैं कि शराब के नाम पर महादलित परिवारों पर, मांझी परिवारों पर, पासी परिवारों पर हमला करना, उन पर छापेमारी करना बंद किया जाय और साथ ही साथ...

सभापति (श्री नरेन्द्र नारायण यादव): माननीय सदस्य, अब आप अपना आसन ग्रहण करें ।

श्री अमरजीत कुशवाहा: महोदय, मैं यह भी मांग कर रहा हूं कि एक वैकल्पिक रोजगार की व्यवस्था करके और दारू वाले लोगों को, जो दारू के धंधे से जुड़े हुए हैं उनको रोजगार दिया जाय ।

सभापति (श्री नरेन्द्र नारायण यादव): माननीय सदस्य, आपका समय हो गया है ।

श्री अमरजीत कुशवाहा: महोदय, मैं एक मिनट का और समय मांगना चाहता हूं, मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि एक तो यह दारू के मामले में था । महोदय, दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि वैकल्पिक रोजगार उनको जरूर मुहैया कराया जाय जो सरकार नहीं दे पाई थी, वायदा भी की थी । जहां तक खाद्य के मामले में अगर देखा जाए तो यहां से तो बहुत बड़े-बड़े दावे हो रहे हैं, निश्चित है कि हमें पहली बार यहां बोलने का मौका मिला है लेकिन मैं कह रहा हूं कि आज भी गांव में गरीबों का नाम राशन कार्ड से काट दिया गया है और बड़े-बड़े लोगों का नाम राशन कार्ड में है जिसके कारण गरीबों को राशन नहीं मिल रहा है ।

सभापति (श्री नरेन्द्र नारायण यादव): अब आप अपना आसन ग्रहण करें ।

श्री अमरजीत कुशवाहा: महोदय, एक ही बात कहते हुए, एक छोटा सा शेर कहते हुए, बहुत शेर इन लोगों ने सुनाया है, बहुत देर मैंने सुना है यह कहते हुए कि आप चाहे जितना छुपा लीजिए :-

''सच्चाई छुप नहीं सकती, बनावट के उसूलों से,

खुशबू आ नहीं सकती, कभी कागज के फूलों से । ''

इसलिए महोदय, इन तमाम बिन्दुओं पर विचार हो, बहुत-बहुत धन्यवाद।

सभापति (श्री नरेन्द्र नारायण यादव): माननीय सदस्य, श्री संजय कुमार तिवारी उर्फ मुन्ना तिवारी । आपके पास छः मिनट का वक्त है ।

श्री संजय कुमार तिवारी उर्फ मुन्ना तिवारी: महोदय, अभी 10 मिनट का समय बचा हुआ है ।

सभापति (श्री नरेन्द्र नारायण यादव): माननीय सदस्य श्री विजय शंकर दूबे जी आज 4 मिनट ज्यादा बोले थे ।

श्री संजय कुमार तिवारी उर्फ मुन्ना तिवारी: सभापति महोदय, सबसे पहले मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे विपक्ष के कटौती प्रस्ताव के समर्थन में बोलने का समय दिया । मैं अपने दल के सचेतक, अपने विधायक दल के नेता, विपक्ष के तमाम माननीय सदस्यों और सत्ता पक्ष के माननीय सदस्यों का आभार व्यक्त करते हुए बक्सर की जनता को पुनः दोबारा इस लोकतंत्र के पवित्र मंदिर में भेजने का जो काम किया उसके लिए मैं आभार व्यक्त करता हूं । महोदय, मैं जिस क्षेत्र से आता हूं बक्सर से वह भगवान राम की शिक्षा स्थली, भगवान वामन की जन्मस्थली, मां गंगा का नैहर है । महोदय, मैं आपको बताऊं कि बक्सर में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं । हमारा शाहाबाद बक्सर से जुड़ा हुआ है । महोदय, मैं इसकी पूर्व में भी इस सदन के माध्यम से इसकी पुरजोर वकालात कर चुका हूं कि बक्सर को अगर पर्यटन का दर्जा दिया जाएगा तो निश्चित रूप से शाहाबाद के तमाम बेरोजगार नौजवानों को वहां रोजगार मुहैया हो सकता है । महोदय, एक शेर के साथ मैं ऊर्जा पर अपनी बात कहना चाहूंगा, अदम गोंडवी जी का शेर है-

''तुम्हारी फाईलों में गांव के मौसम गुलाबी हैं
मगर ये आंकड़े झूठे, यह दावा किताबी है ।''

महोदय, सरकार तो आंकड़ों का खेल पेश करके सदन के बाहर और सदन के भीतर लोगों को गुमराह करने का काम करती है । जिस तरह से आज आदरणीय राजीव गांधी, आदरणीय सोनिया गांधी पर सत्ता पक्ष के लोग टीका-टिप्पणियां करते हैं । महोदय, आज पूरा देश राजीव गांधी की दी हुई टैक्नोलॉजी पर चल रहा है । महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि आज जो टैक्नोलॉजी पूरे भारत में आई है, जिस पंचायती राज की व्यवस्था भारत के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न आदरणीय राजीव गांधी की ही देन है । महोदय, आज हमारे सत्ता पक्ष के लोग हल्की-हल्की बातों में ये राजीव गांधी, इन्दिरा गांधी पर टिप्पणियां करते हैं । सच्चाई और त्याग की प्रतिमूर्ति दो-दो बार प्रधानमंत्री पद को धक्का देने वाली त्याग और तपस्या की प्रतिमूर्ति राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी जी के प्रति भी मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं । महोदय, मुझे

कहने में अतिशयोक्ति नहीं है कि जो किसानों के लिए सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में जो बिजली मुहैया करा रही है, आज वह दुर्दशा के कगार पर है । महोदय, जो मेन सप्लाई का ट्रांसफार्मर है वह जर्जर स्थिति में हैं, उसको कृषि फीडर से जोड़ कर के ही गांव को कनेक्शन दिया जाता है । महोदय, यह बहुत दुर्गति वाला और संवेदनशील विषय है । इस पर अगर सरकार जांच कराएगी तो निश्चित रूप से यह उल्लेखनीय उपलब्धि सरकार के पास आएगी कि किस तरह से किसानों का दोहन करके वहां बिजली दी जा रही है । महोदय, मैं तो यह देखता हूं अपने क्षेत्रों में अगल-बगल के क्षेत्रों में, अगर गरीबों के यहां लगी है, उसके यहां न ए0सी0 है, न फ्रीज है, न टी0वी0 है फिर भी उसके यहां बिजली का बिल ढाई हजार, दो हजार, पन्द्रह सौ रुपये आते हैं । महोदय, ये तमाम जनप्रतिनिधि अपने कलेजे पर हाथ रखकर कहें कि यह हकीकत है कि नहीं ? महोदय, मैं आपके आसन के माध्यम से कहना चाहता हूं कि अगर यह हकीकत है तो सरकार निश्चित रूप से इसपर संज्ञान लें । महोदय, आज हमारे बिहार राज्य में बिजली अन्य राज्यों की तुलना में दोगुनी और तीगुनी लागत पर प्रतियूनिट जो आ रही है, यह भी सोच का विषय है । माननीय मुख्यमंत्री महोदय का यह सपना था कि एक राष्ट्र और एक बिजली दर की, वह जब भाजपा गठबंधन में है, तो आखिर मजबूरी क्या है । महोदय, सरकार क्यों इस पर अमल नहीं कर पा रही है ?

क्रमशः

टर्न-21/यानपति-अंजली/09.03.2021

(क्रमशः)

श्री संजय कुमार तिवारी उर्फ मुन्ना तिवारीः महोदय, मैं आपके आसन के माध्यम से यह भी जानना चाहता हूं । महोदय, हमारे क्षेत्र में चौसा पॉवर प्लांट लग रहा है महोदय, जिस कंपनी का नाम है सतलज जल विद्युत निगम लिमिटेड । महोदय, माननीय मंत्री के वक्तव्य में चौसा का जिक्र आया है । 1320 मेगा वाट बिजली वहां उत्पादन करने की क्षमता है । महोदय, 2023-24 में वह प्लांट शुरू होने वाला है लेकिन सरकार ने वहां के बच्चों को जो बीटेक, डिप्लोमाधारी हैं, इंजीनियर हैं, कंप्यूटर पढ़े हैं महोदय...

सभापति(श्री नरेन्द्र नारायण यादव): आपके पास एक मिनट समय है ।

श्री संजय कुमार तिवारी उर्फ मुन्ना तिवारीः महोदय, उनको रोजगार देने की व्यवस्था में यह सरकार कौन-सा उपाय कर रखी है कि वहां के स्थानीय या अगल-बगल के बच्चों को जो प्रतिभावान हों, गुणवान हों, उनको वहां उस कंपनी में नौकरी देने के नाम पर सरकार क्या विचार रखती है ? महोदय, माननीय मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि

इस पर अपना संबोधन जरूर करेंगे । महोदय, सरकार तो कहती है कि बिजली गांव-गांव में चली गई । महोदय, लेकिन एक कैमूर पहाड़ी है जहां हमारे शाहाबाद में बाबा गुप्ता नाथ का मेला लगता है आज तक वहां बिजली नहीं पहुंच पाई है । चूंकि वह बिहार सरकार के पर्यटक स्थल के रूप में भी जाना जाता है लेकिन आज तक कैमूर की पहाड़ियों पर बिजली नसीब नहीं हो पाई...

सभापति(श्री नरेन्द्र नारायण यादव): अब आप आसन ग्रहण करें । माननीय सदस्य अपना आसन ग्रहण करें ।

श्री संजय कुमार तिवारी उर्फ मुन्ना तिवारी: महोदय, यह भारतीय जनता पार्टी, ये सत्ता पक्ष के लोग जो हैं, एन0डी0ए0 के परमाणु कार्यक्रम को आदरणीय मोहन सिंह के द्वारा लाया गया है महोदय, उसका भी विरोध इन सत्ता पक्ष के लोगों ने किया था । महोदय, अब आज बेईमानी है जो कि बिजली पर अपनी उपब्धियां और चर्चा पर चर्चा करते हैं...

सभापति(श्री नरेन्द्र नारायण यादव): अब आप अपना भाषण समाप्त करें ।

श्री संजय कुमार तिवारी उर्फ मुन्ना तिवारी: महोदय, अंत में अपने भाषण को विराम देने से पहले अपने क्षेत्र के तमाम ऋषियों, मुनियों का जो हमारे लक्ष्मी प्रपन्न जीयर स्वामी जी हैं, नाथ बाबा हैं, राजाराम बाबा हैं मैं उनको अपनी तरफ से श्रद्धा-सुमन अर्पित करते हुये, बहुत-बहुत धन्यवाद, आपलोगों ने मुझे बोलने का मौका दिया ।

सभापति(श्री नरेन्द्र नारायण यादव): माननीय सदस्य श्री जितेंद्र कुमार जी । आपके पास 7 मिनट का समय है ।

श्री जितेंद्र कुमार: आज ऊर्जा विभाग पर बजट पेश हुआ है 85,59,99,72,000/- (पचासी अरब उनसठ करोड़ निन्यानवे लाख बहत्तर हजार) रुपये का । महोदय, हम सभी जानते हैं कि बिजली का क्या महत्व है । बिजली मानव जीवन के विकास का पैमाना है महोदय और बिजली के बिना आधुनिक जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती है । यूं कहिये महोदय कि बिजली आज हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग बन चुका है और इस पर हम पूरी तरह निर्भर हैं । इसी मर्म को हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने समझा है, हमारे माननीय ऊर्जा मंत्री ने समझा है और उस क्षेत्र में अद्भुत विकास हुआ है । हम सभी सौभाग्यशाली हैं, मैं खुद सौभाग्यशाली हूं इस मामले में कि मुझे माननीय लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के रहनुमाई में कार्य करने का मौका मिला और मुझे अस्थावां विधान सभा क्षेत्र से 5वीं बार लगातार विधायक बनने का मौका मिला है । आज मैं सुन रहा हूं महोदय, विपक्ष के लोग कह रहे हैं कि बिजली में कोई विकास ही नहीं हुआ है । यह देखने की चीज है महोदय, यह आंकड़ा देखने की चीज है कि विरोधी भी मानते हैं महोदय, भले यहां पर बोल रहे हैं लेकिन यह जब घर में बैठते हैं, लॉबी

में बैठते हैं, अपने लोगों के बीच बैठते हैं तो निश्चित तौर पर कहते हैं कि माननीय नीतीश कुमार के रहनुमाई में बिहार का विकास हुआ है, ऊर्जा के क्षेत्र में विकास हुआ है और तरक्की हुई है । महोदय, ये आंकड़ा देखा जा सकता है । महोदय, यह जो आंकड़ा है संचरण के क्षेत्र में मांग की चरम पूर्ति मेगा वाट में महोदय, 2005 में मैं जब पहली बार विधायक बना था तो ट्रांसफार्मर के लिए, तार के लिए, एसेम्बली क्वेश्चन करते थे महोदय, आज उसकी आवश्यकता नहीं है । महोदय, आज देख लीजिए कि हमलोग जब 2005 के पहले पढ़ते थे तो रात को बिजली नहीं, दिन को बिजली नहीं, लैंप में पढ़ते थे, पेट्रोमैक्स में पढ़ते थे, रात भर लोग जागते थे कि 2 घंटे बिजली आ जाय, सो जायं, आज बताइए वह हालत नहीं है । महोदय, आज लॉकडाउन में भी सब लोग जानते हैं पूरे भारत में लॉकडाउन, पूरे विश्व में लॉकडाउन लगा और बिहार में भी लगा लोग घर में बंद थे लेकिन किसी तरह की परेशानी नहीं हुई महोदय क्योंकि बिजली थी लोग टीवी देख रहे थे फ्रिज चल रहा था एसी चल रहा था महोदय और बिजली से चलने वाले उपकरण भी चल रहे थे लोग हंसी-खुशी रह रहे थे और मैं ग्रामीण क्षेत्र का विधायक हूं ।

सभापति(श्री नरेन्द्र नारायण यादव): बैठे-बैठे बातचीत नहीं करें ।

श्री जितेंद्र कुमार: मैं तो ग्रामीण क्षेत्र का विधायक हूं महोदय और ग्रामीण क्षेत्र में भी सुखाड़ जब आया पिछले दिनों...

सभापति(श्री नरेन्द्र नारायण यादव): आप आसन की ओर देखकर बोलें माननीय सदस्य ।

श्री जितेंद्र कुमार: तो वहां भी बिजली से अच्छी पैदावार हुई महोदय और हम तो कहना चाहेंगे महोदय देखने की चीज है तुलनात्मक अध्ययन करने की चीज है महोदय । 2005 में मुश्किल से 700 मेगावाट थी मांग की चरम पूर्ति में संचरण के क्षेत्र में महोदय 2012-13 में 1802, 2013-14 में 2335, 2014-15 में 2831, 2015-16 में 3459, 2016-17 में 3769, 2017-18 में 4535, 2018-19 में 5139, 2019-20 में 5891 यह क्या दर्शाता है महोदय । लगातार हम आगे बढ़ रहे हैं उन्नति कर रहे हैं । माननीय मुख्यमंत्री जी चेहरा देखकर काम नहीं करते हैं । महोदय, समाज के अंतिम व्यक्ति का भी विकास करते हैं । आप चले जाइये गांव में महोदय, वहां भी बिजली जल रही है । गांव-गांव में हमलोग चुनाव में भी घूमते हैं, झोपड़ी में भी जाते हैं वहां भी बल्ब जल रहा है महोदय । वहां भी देख रहे हैं महोदय कि ठंडा-ठंडा पानी भी आ रहा है लोग टी0वी0 भी देख रहे हैं यह तो अद्भुत नजारा था महोदय और यह कार्य माननीय मुख्यमंत्री जी के अथक प्रयास से हुआ है । माननीय मुख्यमंत्री जी महोदय केवल खाका ही नहीं खींचते हैं, केवल शिलान्यास ही नहीं करते हैं उस कार्य को अमलीजामा पहनाने का काम करते हैं वो हैं आदरणीय नीतीश कुमार जी । महोदय, आप देख लीजिये बिहार में पावर स्टेशनों

की संख्या कितनी थी । 2005 में 268, 2012 में 545 और 2019 में 1051 हमलोग माननीय मंत्री महोदय से आग्रह करते थे यहां आदरणीय हमारे ऊर्जा मंत्री जी हैं जिनके कार्यों से हमलोग सबक भी लेते हैं इनके कार्य इतने बेहतर रहते हैं कि हमलोग जीवन में आत्मसात करते हैं इनके कार्यों से लेसन लेने की आवश्यकता है । हमारे क्षेत्र में गये थे तो हमलोग दिखाते थे महोदय यह सब पावर स्टेशन जर्जर अवस्था में हैं 2005 में विधायक बने थे तो दिखाते थे बोले कि सबकुछ हो जायेगा माननीय मुख्यमंत्री जी का पक्का इरादा है । देख लीजिए महोदय, ग्रिड सब पावर स्टेशन की संख्या कितनी थी 2005 में 45, 2012 में 83, और 2019 में 148 आप देख सकते हैं महोदय लगातार हम तरक्की की ओर जा रहे हैं महोदय । हमारी सरकार की सोच एक सकारात्मक सोच है एफ्यूजन का विचार है महोदय एक रचनात्मक विचार है और उसी के तहत हम आगे बढ़ रहे हैं महोदय । प्रति व्यक्ति खपत देख लीजिए महोदय । बिजली की खपत क्या थी किलोवाट में देखिये महोदय, 2012-13 में 145 किलोवाट, 2013-14 में 160 किलोवाट, 2014-15 में 203 किलोवाट, 2015-16 में 258 किलोवाट, 2016-17 में 272 किलोवाट, 2017-18 में 280 किलोवाट, 2018-19 में 311 किलोवाट आवर, 2019-20 में 332 किलोवाट, लगातार हम बढ़ रहे हैं महोदय । महोदय, हम कह सकते हैं कि एक समय था कि मोबाइल चार्ज करना भी मुश्किल था, लोग जाते थे प्रखंड मुख्यालय और 10 रुपया देते थे मोबाइल चार्ज करने का, वह दिन भी याद कीजिये, कोई बड़ा दिन नहीं है । हमलोग 2005 के पहले कॉलेज में पढ़ते थे तो मोबाइल चार्ज करने के लिये प्रखंड मुख्यालय जाते थे । महोदय, वह भी जमाना था, आज देख लीजिये 2005 के पहले और 2005 के बाद आप एसी की दुकान में चले जाइये, कूलर की दुकान में चले जाइये, फैन की दुकान में चले जाइये...

सभापति(श्री नरेन्द्र नारायण यादव): आपके पास मात्र एक मिनट का वक्त है ।

श्री जितेंद्र कुमार: तो लगातार इजाफा हुआ है महोदय । महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि आज खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग का भी आज बजट पेश हुआ है, हम आग्रह करेंगे कि पैक्स किसानों का तुरंत भुगतान करता है लेकिन पैक्सों का भुगतान 6 महीने में होता है, 4 महीने में होता है, वह देखने की चीज है । महोदय, इसी कारण आज पूरे बिहार राज्य में करीब 725 पैक्स डिफॉल्टर हैं क्यों हैं डिफॉल्टर क्योंकि एस0एफ0टी0 ने एक पत्र जारी किया है कि आपको दो महीने का सूद दिया जायेगा लेकिन यह भी कहा गया है कि आपके चावल का उठाव, पैक्सों के चावल का उठाव जून तक किया जायेगा तो बाकी शेष महीने का जो सूद लगेगा

उसका भुगतान कौन करेगा । महोदय, यह देखने की चीज है कि बेवजह जो पैक्सों पर सूद लगेगा उसका भुगतान कौन करेगा यह देखने की चीज है ।

सभापति(श्री नरेन्द्र नारायण यादव): अब आप अपना आसन ग्रहण करें ।

श्री जितेंद्र कुमार: महोदय, यह बहुत ही इंपोर्टेंट है, पैक्सों की बात है । महोदय, अब पैक्सों के द्वारा चावल दिया जा रहा है और चावल के बदले करीब 9.5 लाख एम0टी0 का चावल अभी गिराया गया है एस0एफ0टी0 के यहां लेकिन केवल चावल की राशि दी गयी है लेकिन परिवहन शुल्क चाहे गनी बैग का, चाहे प्रबंधकीय अनुदान पैक्सों का भुगतान नहीं किया गया है तो एक बात जरूर कहेंगे महोदय...

सभापति(श्री नरेन्द्र नारायण यादव): अब आपका समय हो गया है ।

श्री जितेंद्र कुमार: हमारे पैक्स जो डिफॉल्टर हो रहे हैं उसके बारे में सोचिये और बेवजह जो सूद लग रहा है उसके बारे में सोचने की आवश्यकता है कि पैक्सों को डिफॉल्टर से बचाया जा सके महोदय ।

सभापति(श्री नरेन्द्र नारायण यादव): अब आप अपना स्थान ग्रहण करें ।

श्री जितेंद्र कुमार: महोदय, आपने मुझे समय दिया, धन्यवाद ।

सभापति(श्री नरेन्द्र नारायण यादव): माननीय सदस्य श्री मनोज कुमार यादव जी, आपके पास 09 मिनट का वक्त है ।

टर्न-22/सत्येन्द्र/09-03-21

श्री मनोज कुमार यादव: माननीय सभापति महोदय, मैं कटौती प्रस्ताव के पक्ष में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ। महोदय, मैं पूर्वी चम्पारण के कल्याणपुर विधान-सभा से पहली बार निर्वाचित होकर आया हूँ और सदन में हमको बोलने का जो मौका मिला है इसके लिए माननीय आदरणीय लालू प्रसाद यादव, आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव और गरीबों के महानायक स्व0 कामरेड पिताम्बर सिंह को नमन करता हूँ। महोदय,मैं अपना प्रस्ताव एक भोजपुरी लोकोक्ति से शुरू करना चाहता हूँ कि 'काकी हउ त का हउ, फटक के द और फटक के ल।' सरकार को गुमान है महोदय तो हमलोगों को भी गुमान है विरोधी दल को, विराधी दल भी कोई मामूली चीज नहीं है, विरोधी दल में रहकर सरकार के झूका के, काम करवा कर के और सरकार को आईना दिखाये वही नेतागिरी है, वही विधायकी है। सभापति महोदय, हमलोगों को मौका मिला है और हमलोग भाग्यशाली है, सौभाग्यशाली हैं कि तेजस्वी प्रसाद यादव जी जैसे विरोधी दल के नेता हमलोगों को मिला है। लोगों को अच्छा लगे या ना लगे लेकिन सोने पर तो बुझाता ही है कि इसका कोई जवाब नहीं है । महोदय, हम कोई खाता खेसरा, कोई बड़ा बात विधान-सभा में बोलना नहीं चाहते हैं, हम एक आम आदमी के नेता है जो गरीब गुरबा है, हमलोग कम्युनिष्ट पार्टी से जुड़े

हुए हैं। एक बात बोलना चाहते हैं, भोजपुरी हमको अच्छा लगता है इसलिए हम भोजपुरी में बोल रहे हैं बीच में हम हिन्दी भी बोलेंगे। पहली बार हम यहां बोल रहे हैं इसलिए घबराहट भी हो रहा है, लग रहा है कि क्या बोलें क्या नहीं बोलें। क्या कहें कहा नहीं जा रहा है बिजली मंत्री जी लेकिन कहे बिना रहा नहीं जाता है। महोदय,आम आदमी के, दलित के, पिछड़ा के, किसान के, मजदूर के बिजली का बहुत बुरा हाल है, काफी समस्या है लोग उससे तबाह है, कोई कितना भी अपना कलेजा क्यों न थपथपा ले लेकिन जमीन पर जाकर देखिये तो पता चलेगा कि क्या हाल है गरीब गुरबा का इसलिए हम मंत्री महोदय का ध्यान सभापति महोदय के माध्यम से आकृष्ट करना चाहते हैं कि आज क्या हाल है बिजली के क्षेत्र में, महोदय, बड़ी कमाल है डुगडुगी बजता है लेकिन हाल यह है सभापति महोदय कि ट्रांसफर्मर का अगर फ्यूज उड़ जाय 7 बजे सुबह में और अगर कल 7 बजे सुबह तक लग जाये तो हमलोग विधायकी छोड़ देंगे। फ्यूज नहीं लग रहा है चूंकि सब प्राइवेट हो गया है और सरकार का उस पर कोई नियंत्रण नहीं है, छोड़िये न विनय बिहारी भईया आपके क्षेत्र के लोग भी सुन रहे होंगे कि हम जो बोल रहे हैं वह सच है या असत्य। उस पर जे0ई0, एस0डी0ओ0 का कोई लगाम नहीं है, एस0डी0ओ0 कहता है कि कोई बहाली नहीं हो रहा है, जे0ई0 बोलता है कि कोई बहाली नहीं हो रहा है तो हम कहां से ले आये, प्राइवेट आदमी से काम करवाना है। सभापति महोदय, प्राइवेट वाला जो ट्रांसफर्मर का काम देख रहा है वह ठीकेदार है और उस ठीकेदार अपने अंदर में भी पैसा लेकर बहाली कर रहा है, किसी को हटा रहा है तो किसी को जोड़ रहा है, ट्रांसफर्मर कब बनेगा, जब उस गांव के लोग जो उससे जुड़ा हुआ है चंदा करेगा और आयेगा मिस्त्री तो बोलेगा कि ट्रांसफर्मर में तेल कम हो गया है, बहुत गड़बड़ी हो गया है, भोल्टेज डाउन हो गया है इसलिए इसमें दो हजार का खर्च है मिलेगा तब तो बनेगा और यह सुनते सुबह से चंदा और चारों तरफ गांव में वसूली शुरू हो जायेगा कि भाई चंदा देंगे तब न बनेगा, यह हाल है ट्रांसफर्मर के फ्यूज उड़ने पर। 2005 के पहले और बाद का बड़ा बड़ा बात हो रहा है लेकिन अभी भी हालत है कि आप जायें गांव में तो जो बी0पी0एल0 परिवार है जो गरीब लोग है उसके गांव का तार जर्जर हो गया है, लगता है कि कब गिर जायेगा, कब टूट जायेगा लेकिन सरकार की योजना केवल कागज पर है कि तार जो जर्जर है उसको बदलकर नया लगाना है। कहीं नया नहीं लग रहा है जो इसका ठीकेदारी ले लिया है मंत्री जी वह दो साल से तार बदल रहा है लेकिन अब तक तार नहीं बदलाया है। जब भी कार्यपालक अभियंता को फोन किया जायेगा और जब उनसे पूछेंगे कि तार आया है तो कहते हैं कि रास्ते में गाड़ी है, छः माह से गाड़ी मोतिहारी नहीं आया है, चला है तो कलकत्ता और

दिल्ली से यह हाल है, अभी कहीं तार नहीं बदला रहा है। कवर वाले बिजली के तार का ठीका हो गया है, ऑनलाईन अप्लाई हो रहा है मीटर का लेकिन उसका क्या हाल है, मीटर के लिए हजारों लोग ऑनलाईन अप्लाई कर के लाईन में लगे हुए हैं और लोग इंतजार कर रहे हैं कि कब मीटर आवे कि लगे और आपका जाता है जे0ई0 गांव में तो गरीब आदमी को जाकर कहता है कि तुमको लाईन काट देंगे और तुम पर एफ0आई0आर0 करेंगे । हुजूर, उसका क्या दोष है वह तो मीटर के लिए ऑनलाईन अप्लाई किया है और बी0पी0एल0में उसका नाम है,सरकार का पहले आया कि फ्री में लगेगा, सब बी0पी0एल0 के घर में लगेगा लेकिन वह काम भी ठीका में ,सब काम ठीका में, मीटर आया लेकिन ठीकेदार मीटर जो लगाया,जो ए0पी0एल0 में है उसको बी0पी0एल0 में लगा दिया और जो बी0पी0एल0 में है उसको ए0पी0एल0 में लगा दिया और पेपर में भाउचर बनाकर भाग गया, आज लाभुक उसको खोज रहा है। इसी प्रकार जिसको घरेलु बिजली कनेक्शन दिया गया उसको कॉमर्शियल का बिल आ रहा है हमलोगों के यहां दर्जनों लोग रोज आते हैं और कहते हैं कि हमारा कॉमर्शियल बिल आ रहा है जबकि हमको रहने का घर तक नहीं है, वे लोग कहां से बिल जमा करेंगे, ऐसा हो रहा है यह सब समस्या है।सभापति महोदय, 11 हजार वोल्ट का तार पावर हाउस से आता है जहां हमलोगों का घर है जमुनिया में, कोटवा फीडर है वहां से 11 हजार का तार हमलोगों के गांव से 5 कि0मी0 तक आया हुआ है तीन फेज और 5 कि0मी0 के बाद आज दो वर्ष हो गया, तीन फेज ट्रांसफर्मर में लगना था लेकिन वह आजतक नहीं हुआ। जब भी फोन किया जाता है तो पता चलता है कि वह सरकार का काम नहीं है, पदाधिकारी बोलते हैं कि इससे हमको मतलब नहीं है यह तो ठीका पर चला गया है, जब ठीकेदार आयेगा तो वही तार बदलेगा और ठीकेदार से भेंट नहीं हो रहा है।

सभापति(श्री नरेन्द्र नारायण यादव): माननीय सदस्य, आपके पास दो मिनट का वक्त बचा है।

श्री मनोज कुमार यादव: बहुत बात बोलना था सभापति महोदय लेकिन एक कहानी कह कर अपनी बात समाप्त करूंगा चूंकि मेरे समय में कटौती हो गया है..

सभापति(श्री नरेन्द्र नारायण यादव) : गागर में सागर भरिये।

श्री मनोज कुमार यादव: एक भोजपुरी कहावत है, वही कहकर अपना बात समाप्त करेंगे। समस्याओं का भंडार है, जितना समस्या का भंडार है उससे संबंधित भोजपुरी में एक कहानी कह रहा हूँ- गांव में एक बिजली का दुकान था जिसमें लिखा हुआ था बड़कागांव के बड़का बिजली का दुकान, कुछ सामान हमलोगों को खरीदना था तो हुआ कि कहां खरीदा जाय तो हुआ कि चला जाय बड़कागांव के बड़का दुकान में, वहीं पर सब सामान मिल जायेगा तो खरीद लिया जायेगा जब लोग वहां गया

तो वहां लिखा हुआ था बड़कागांव के बड़का बिजली का दुकान, उनलोगों ने पूछा कि यहां बिजली का बल्व है एल0ई0डी0 वाला जो तीन साल में बदला जाता है लेकिन कोई भेंट ही नहीं हो रहा है, बिजली का बल्व तो मिला था लेकिन अब उसको बदलने के लिए कोई कहीं भेंट नहीं हो रहा है, पूछा लोग कि बिजली के एल0ई0डी0 का बल्व है तो दुकानदार बोला कि बल्व नहीं है, तार है तो नहीं है, फ्यूज है तो नहीं है, कवर वाला तार है तो नहीं है, ताला है तो कहा कि हां हैं तो उसने कहा कि दुकान में ताला लगाकर बंद क्यों नहीं कर देते? दुकान में जब कोई सामान नहीं है तो यह दुकान बंद होना चाहिए। सभापति महोदय, आज बिहार सरकार के बिजली विभाग में काई सामान नहीं है और जब दुकान में सामान नहीं है, जब विधान-सभा में हम क्वेश्चन करें और यहां कोई समस्या का समाधान नहीं हो, कुछ लोगों को बुझाता है कि मनोज कुमार यादव विधायक हो गये तो विधान-सभा में बैठेंगे और बोलेंगे तो हो जायेगा। हमने कहा कि दुकान में कोई सामान नहीं है विधान-सभा के और सरकार के दुकान में जब कोई सामान नहीं है तो इसको बंद कर गांव में जाना चाहिए...

सभापति(श्री नरेन्द्र नारायण यादव) : माननीय सदस्य,अब आप आसन ग्रहण करें।

श्री मनोज कुमार यादवः लोकतंत्र के इस मंदिर का अपमान न हो इसलिए इसमें ताला लगा दें और यहां से गांव की ओर चलें ताकि लोगों का विश्वास बना रहे। यही कहकर मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ और कटौती प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ।

सभापति(श्री नरेन्द्र नारायण यादव) : श्री सैयद रूकनुद्दीन अहमद। आपके पास में चार मिनट का वक्त है।

श्री सैयद रूकनुद्दीन अहमदः सभापति महोदय,मैं ऊर्जा विभाग के कटौती प्रस्ताव के पक्ष में उठा हूँ, मुझे आपने बोलने का मौका दिया मैं इसके लिए आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ और वायसी विधान-सभा क्षेत्र के समस्त जनता को धन्यवाद देता हूँ। महोदय, सभी घर में हो रहे बिजली के इस मुहिम में सरकार की हम सराहना करते हैं लेकिन अमीर गरीब नहीं, रोशनी सभी के घर में पहुंचना चाहिए। एक तरफ हर घर में बिजली पहुंचाने का सरकार क्रेडिट ले रही है लेकिन समस्याओं के निदान पर ध्यान नहीं दे रही है। वैसे लोगों का सूध लेने वाला भी कोई नहीं है

(क्रमशः)

टर्न-23/मधुप/09.03.2021

...क्रमशः..

श्री सैयद रूकनुद्दीन अहमद : एक तरफ लोग कोरोना-काल में इस महामारी से देश में जूझ रहे थे, लगभग सभी राज्य की सरकारें बिजली बिल को माफ किया था लेकिन बिहार

सरकार ने परेशान आवाम पर बिजली का बोझ लादने का काम किया है । यही नहीं, बायसी विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत कई पंचायत के वार्ड में अबतक बिजली का बिल नहीं पहुँचा है । आज भी बिजली वहाँ नहीं पहुँची है, जैसे कि ताराबारी पंचायत के टिक्का टोला गाँव और गांगर पंचायत के सिमलिया गाँव में आज भी खुटिया पंचायत के खुटिया गाँव में बाँसों के पोल पर 11000 का बिजली का तार पास हुआ है । जिसमें कई अप्रिय घटनाएँ घटी हैं । आज भी ऊर्जा विभाग की स्थिति अत्यंत ही दयनीय है । बाढ़ प्रभावित एरिया में खासकर बायसी, डगरूआ, अमौर और बैसा में बिजली कटने के उपरांत विभागीय कर्मचारियों की लापरवाही के कारण कई दिनों तक बिजली कटी रहती है । स्थानीय अभियंताओं के द्वारा मीटर कनेक्शन ट्रांसफर्मर के नाम पर स्थानीय उपभोक्ताओं से काफी मोटी रकम लेकर काम किया जाता है एवं उपभोक्ताओं को उचित बिल प्रस्तुत नहीं कर फर्जी बिल दिया जाता है जिससे स्थानीय जनता में आक्रोश व्याप्त है । मैं माननीय मंत्री, ऊर्जा विभाग से यह माँग करता हूँ कि विभागीय त्रुटिपूर्ण कार्य में सुधार के लिए पूरे बिहार के संबंधित पदाधिकारियों को निदेश दिया जाय जिससे सरकार द्वारा जो घोषणा किया जा रहा है उसपर सही अमल हो सके । बहुत-बहुत धन्यवाद ।

सभापति(श्री नरेन्द्र नारायण यादव) : माननीय सदस्या श्रीमती ज्योति देवी । आपके पास 3 मिनट का वक्त है ।

श्रीमती ज्योति देवी : माननीय महोदय, मैं अपने सरकार पक्ष के लोगों से माँगना चाह रही हूँ कि एक-दो मिनट आपलोग दीजिए ।

सभापति महोदय, सबसे पहले मैं अपने बाराचट्टी की जनता को हृदय से नमन करती हूँ ताकि आपकी ऊर्जा हममें प्रवाहित हो और मैं अपने दल के नेता मांझी साहब को और माननीय नीतीश कुमार जी को और माननीय प्रधानमंत्री जी को, जिन्होंने बिहार को बढ़ाने में कदम से कदम मिलाकर ऊर्जान्वित किया है ।

सभापति महोदय, ऊर्जा विभाग के अनुदान माँग के पक्ष में अपनी बात रखने का समय देने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद । महोदय, जब भी मेरे मस्तिष्क में ऊर्जा या कहें बिजली की बात आती है तो मुझे वह पुराना वक्त याद आता है कि जब शाम में घर के बच्चे पढ़ने के लिए लालटेन का शीशा, ढिबरी साफ किया करते थे और मैं उन्हें किरासत तेल देती थी कि लालटेन की रोशनी तेज हो जिससे बच्चों को पढ़ने में कोई परेशानी न हो ।

महोदय, वक्त के साथ-साथ हालात भी बदले हैं । माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हमने विद्युत क्षेत्र में प्रचलित पुरानी परम्पराओं को तोड़ा है । आज बिहार की जनता लालटेन युग में नहीं जी रही बल्कि विकास की अविरल धारा के साथ आगे बढ़ रही है । सम्पूर्ण राज्य में विद्युत कनेक्शन दिया गया है ।

विद्युत उत्पादन के क्षेत्र में भी वृद्धि हुई है जिससे राज्य के सभी क्षेत्रों में विद्युत की उपलब्धता लगातार बढ़ रही है । इस दिशा में नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व वाली केन्द्र सरकार भी हमारे बिहार को मदद कर रही है तभी तो केन्द्र सरकार द्वारा बिहार के कटिहार जिले में 4300 करोड़ की मदद से 765 के0वी0 का सुपर ग्रीड एवं इसके संचरण लाईन के निर्माण की योजना है इससे बंगलादेश को भी 800 मेगावाट बिजली की आपूर्ति की जा सकेगी ।

महोदय, कई मायने में बिहार ने ऐसा काम किया है जिसका अनुसरण देश कर रहा है । उसी कड़ी में हमने स्मार्ट मीटर का अधिष्ठापन प्रीपेड प्रणाली के साथ बिहार में काम शुरू किया है । यह विद्युत उपभोक्ताओं को बिलिंग एवं कनेक्शन की समस्या से निजात दिलाने में सहायक होगी । राज्य में अबतक 1,06,773 स्मार्ट मीटर लगाये जा चुके हैं । जल जीवन हरियाली अभियान के तहत राज्य के सभी प्रखंडों के प्रखंड कार्यालय, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के भवनों, राजकीय आई0टी0आई0 एवं पंचायत सरकार भवनों का कुल 10.0 MWp floating सोलर पावर प्लांट लगाने का काम प्रगति पर है । नीचे मछली उपर बिजली योजना के तहत दरभंगा जिला में 2 MWp floating सोलर पावर प्लांट एवं सुपौल में 2 KWp floating सोलर पावर प्लांट का काम प्रगति पर है ।

सभापति(श्री नरेन्द्र नारायण यादव) : आपके पास एक मिनट का समय बचा है ।

श्रीमती ज्योति देवी : महोदय, कुछ लोग आज भी राज्य को लालटेन युग में ले जाने के फिराक में जुटे हुये हैं । उन्हें एल0ई0डी0 बल्ब की रोशनी पसन्द नहीं आ रही है इसलिये वे हमारी माँगों में कटौती करने की बात कहते हैं । महोदय, जबकि 2005 में जहाँ राज्य में बिजली की आपूर्ति 700 मेगावाट थी जो अब बढ़कर 5932 मेगावाट से अधिक हो गई है । माननीय महोदय, मैं ज्यादा वक्त नहीं लूँगी, थोड़ा-सा मैं विपक्ष के भाईयों से निवेदन करके कहूँगी कि पिछले जितने भी साथी थे, उनको याद होगा कि जब सदन शुरू हुआ तो हमारे माननीय नेता श्री नीतीश कुमार जी ने कहा था कि बिहार के विकास के लिए हम सबों की उतनी ही जवाबदेही है क्योंकि सरकार, मंत्री और मुख्यमंत्री ही नहीं होते हैं, सारे विधायक भी सरकार होते हैं । तो मैं आप सबों से यह कहना चाहूँगी कि जो हमारी सरकार है...

सभापति(श्री नरेन्द्र नारायण यादव) : अब आप आसन ग्रहण करें ।

श्रीमती ज्योति देवी : थोड़ा-सा सर । पूर्व में भी हमारे ए0पी0जे0 अब्दुल कलाम साहब जब आये थे..

सभापति(श्री नरेन्द्र नारायण यादव) : अब आप आसन ग्रहण कर लें, आप बैठ जायं । माननीय सदस्य श्री मिश्री लाल यादव जी ।

श्रीमती ज्योति देवी : उन्होंने कहा था कि बिहार के आप पिलर हैं, अगर पिलर डगमगायेगा तो बिहार की शक्ति डगमगायेगी । इसलिए माननीय महोदय, मैं यही कहूँगी कि बिहार के विकास के लिए सबलोग मिलकर काम करें ।

सभापति(श्री नरेन्द्र नारायण यादव) : माननीय सदस्या, अब आप बैठ जायं ।

माननीय सदस्य श्री मिश्री लाल यादव जी । आपके पास 3 मिनट का वक्त है ।

श्री मिश्री लाल यादव : मान्यवर सभापति महोदय, मुझे आज सदन में बोलने के लिए वी0आई0पी0 के राष्ट्रीय अध्यक्ष मान्यवर मुकेश सहनी जी ने मौका दिया है, आपके प्रति और सहनी जी के प्रति, सदन के प्रति आभार प्रकट करता हूँ ।

माननीय सभापति जी, आज ऊर्जा, मद्य निषेध एवं खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के बजट पर चर्चाएँ हो रही हैं । महोदय, मुझे तो मात्र 3 मिनट का समय मिला है, मैं कहना चाहता हूँ, मैं 2003 में एम0एल0सी0 था और महोदय, जब मैं उस फ्लैट में रहता था तब भी वहाँ बिजली पूरा-पूरा नहीं दिखाई देता था। जब मैं गाँव जाता था तो बिजली नाम की कोई चीज दिखाई नहीं दे रही थी । आज सदन को भी विश्वास है और सारे लोग जान रहे हैं कि आज गाँवों में भी 22 घंटा बिजली मिल रही है । महोदय, हम गाँव-गवई से आते हैं, जब ट्रांसफर्मर जल जाता था तो महीना नहीं, दो महीना नहीं, 6-6 महीने तक ट्रांसफर्मर के बिना बिजली गुल रहती थी । आज सरकार कृत-संकल्पित है जो आपको 24 से 72 घंटे में बिहार के किसी कोने में ट्रांसफर्मर जलता है तो सरकार उसको आपूर्ति करती है। महोदय, आज विकसित बिहार, आत्मनिर्भर बिहार में बिजली की अहम भूमिका है। आज बिजली के जरिये जहाँ सरकार घर-घर बिजली पहुँचाने में लगी है, आज मैं बता देना चाहता हूँ सदन के माध्यम से पूरे बिहार को कि आज बिहार में एक घर भी बाकी नहीं है जहाँ बिजली नहीं है और दूसरी ओर सरकार संकल्पित है कि किसान के आय को हम दुगुणा करेंगे । सदन को सुनकर खुशी होगी जो आज की तारीख में जहाँ बिजली के बिना आपको पम्पिंग सेट से जब बोरिंग से किसान खेत पटा रहे थे ।

...क्रमशः..

टर्न-24/आजाद209.03.2021

..... क्रमशः .....

श्री मिश्री लाल यादव : तो 200 रू0 प्रति कट्ठा उनको खर्चा पड़ता था । अब सरकार ने निर्णय लिया है कि हम बोरिंग को बिजली से जोड़ेंगे । जब बिजली से बोरिंग चलेगी तो प्रति कट्ठा मात्र 20 रू0 खर्चा आयेगा । आज जैसे गांवों में बिजली का

पोल लग रहा है तो बोरिंग के तरफ भी, खेत के तरफ भी बिजली का पोल लग रहा है । यह सरकार .....

सभापति(श्री नरेन्द्र नारायण यादव) : आपका समय हो गया है । माननीय सदस्य, आसन ग्रहण करें ।

श्री मिश्री लाल यादव : महोदय, एक मिनट का समय चाहूँगा, मुझे मात्र तीन मिनट समय मिला था । महोदय, आज मैं सरकार से मांग करना चाहता हूँ कि हम अलीनगर विधान सभा से आते हैं, काफी चर्चित विधान सभा है और वहां एम0ओ0 के बदले घनश्यामपुर और अलीनगर में एम0ओ0 का काम सी0ओ0 देख रहे हैं, चूँकि सी0ओ0 को दाखिल खारिज करना है, अन्य सारे कामों को करना है और जनवितरण प्रणाली के कार्यों को सी0ओ0 ठीक से नहीं देख पाते हैं । इसलिए बगल के एम0ओ0 को चार्ज मिलना चाहिए और इस कार्य से सी0ओ0 को हटाना चाहिए.....

सभापति(श्री नरेन्द्र नारायण यादव) : अब आप अपना आसन ग्रहण करें, आपका समय हो गया है । माननीय सदस्य श्री बच्चा पाण्डेय, आपके पास 9 मिनट का वक्त है ।

आप माननीय सदस्य बैठ जायं ।

श्री बच्चा पाण्डेय : माननीय सभापति महोदय, मैं कटौती प्रस्ताव के पक्ष में बोलने के लिए तैयार हूँ । मेरा विषय मद्य निषेध, शराबबंदी से संबंधित है । महोदय, जब मैं बॉर्डर से गुजरता हूँ तो वहां पर बड़ा बोर्ड लगा हुआ है जिसपर लिखा हुआ है कि आइए बिहार में, नशामुक्त बिहार में आपका स्वागत है । क्या इस सरकार से मैं पूछना चाहता हूँ कि जिस राज्य में शराब बिकता हो, कोकिन बिकता हो, चरस बिकता हो और अफीम बिकता हो, क्या यह नशामुक्त बिहार है, क्या नशामुक्त का यही परिभाषा है, क्या इसी परिभाषा से इसको परिभाषित किया जाता है ?

महोदय, मैं कुछ दिन पहले माननीय मुख्यमंत्री जी का भाषण सुन रहा था, माननीय मुख्यमंत्री जी बड़े तेज से बोल रहे थे कि मैं नहीं मानूंगा, मैं शराब नहीं खोलूंगा, शराब बंद कहां है जिसको खोलने की बात आती है । शराब तो स्वतः चालू है, चालू को खोलने की कहां बात है ? माननीय मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं अपने भाषण में तो खुले हुए दरवाजे को कैसे खोलेंगे ? माननीय महोदय, अन्तर बस इतना ही है महोदय कि 2015 में उत्पाद नीति के द्वारा दुकानों की बन्दोबस्ती होती थी और अनुज्ञप्तिधारी द्वारा शराब की बिक्री की जाती थी । आज 2016 से लेकर 2020 तक माफियाओं के द्वारा शराब बेची जा रही है और उनके द्वारा शराब की बिक्री करायी जा रही है । महोदय, प्रत्येक गांव में माफियाओं के द्वारा एक होलसेलर, तीन रिटेलर, एक रिटेलर द्वारा पॉच-पॉच होम डिलिवरी की नियुक्ति किया है, जिसमें 16 वर्ष से लेकर 22 वर्ष तक का लड़का इस अँधे बिजनेस में

लगा हुआ है । महोदय, टोटल जोड़ा जाय तो इसमें 31 सदस्य जो है इस धंधे में इस स्वरोजगार में लोग लिप्त हैं । जहां तक 19 लाख रोजगार देने की बात आती है तो माननीय मुख्यमंत्री जी 19 लाख रोजगार तो नहीं दे पायेंगे लेकिन 19 लाख स्वरोजगार जो है, वे युवाओं को दे दिये हैं और 31 से गुना किया जाय पूरे बिहार में तो 19 लाख से ज्यादा युवाओं को स्वरोजगार मिला हुआ है । महोदय, बिहार में प्रत्येक गांव के आकलन किया जाय, युवाओं जो है 16 से लेकर 20 वर्ष तक जितने युवा वर्ग है, सब लोग इस धंधे में सम्मिलित हो गये हैं । इस ओर सरकार का ध्यान नहीं है कि युवाओं को स्वरोजगार कैसे दिया जाय, युवाओं जो है प्रत्येक दिन इस धंधे से जुड़ रहे हैं और इसमें अनेक युवाओं को शामिल करने के लिए बढ़ावा देते हैं । जिस तरह महोदय, कोराना काल में आम जनता को जागरूक किया गया, उसी तरह 2015 में अगर सरकार ने जनता को जागरूक किया होता तो आज जो है दिनेश राम की हत्या नहीं होती, आज दिनेश राम स्वतः अपने परिवार के साथ जीवित रहते । महोदय, 2005 से पहले नगर परिषद् और नगर पंचायत में और प्रखंडस्तरीय शराब की दुकान हुआ करती थी । 2005 के बाद जब नई सरकार आयी तो उन्होंने एक कम्पोजिट दुकान के नाम से नामकरण कर दिया जो कि चौक-चौराहे पर शराब बिकवाने का काम किया । 2005 से पहले सिर्फ छोटे-छोटे शहरों में शराब की दुकानें होती थी । जब नई सरकार आयी तो इन्होंने चौक-चौराहे पर अपनी दुकान खोलवाना शुरू कर दिया जिसमें आम जनता द्वारा इसका विरोध हुआ । उस समय माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभिभाषण हुआ कि हमने जहरीली शराब को रोकने के लिए चौक-चौराहे पर शराब की दुकान खोलवा रहा हूँ । महोदय, आज माफिया लोग गली-गली में शराब बेच रहे हैं और होम डिलिवरी का काम कर रहे हैं । 2016, 2017, 2018, 2019 में होम डिलिवरी का काम हुआ, 2020 में तो इसके साथ चखना डिलिवरी भी शुरू हो गया जो कि आम जनता के लिए बहुत आसान हो गया । कोई भी गरीब जनता इसको नहीं चाहती, कोई अमीर जनता नहीं चाहती कि शराब खुले, लोग चाहते हैं कि शराब बंद रहे, अब बंदी की जरूरत है क्योंकि जब आम जनता को इसकी सुविधा मिल रही है तो खोलने से क्या फायदा है ।

सभापति(श्री नरेन्द्र नारायण यादव) : माननीय सदस्य, ऊर्जा पर अपना बहुमूल्य सुझाव रखें, मात्र दो मिनट का वक्त आपके पास है ।

श्री बच्चा पाण्डेय : महोदय, सबसे पहले मैंने कह दिया था कि मैं मद्य निषेध पर बोलूंगा । महोदय, मद्य निषेध, उत्पादन विभाग का 2015-16 में वार्षिक आय था 4500 करोड़ रू0, जिसमें सेल्स टैक्स की आय थी उसका 50 प्रतिशत, टोटल आय मिलाकर के 6750 करोड़ का आय था प्रतिवर्ष में । महोदय, 2017-18 में यही

आय 9720 करोड़ रू0 हो गया । 2018-19 में वार्षिक आय बढ़कर 11665 करोड़ रू0 हो गया.....

सभापति(श्री नरेन्द्र नारायण यादव) : मात्र एक मिनट आपका बचा है आपके पास में ।

श्री बच्चा पाण्डेय : पुनः 2019-20 में बिहार की वित्तीय आय बढ़कर 13996.8 करोड़ रू0 हो गई महोदय । महोदय, मेरे कहने का आशय यह है कि सिर्फ एक ही इस विभाग से पंचवर्षीय योजना में 47980.8 करोड़ रू0 का ह्रास हुआ । जबकि बिहार सरकार को केन्द्रीय कर्ज 1,80,000 करोड़ रू0 है । अगर इस विभाग का वित्तीय ह्रास नहीं होता तो बिहार का कर्ज मात्र 1,32,000.2 करोड़ रू0 होता । यह बिहार की आर्थिक ह्रास है .....

सभापति(श्री नरेन्द्र नारायण यादव) : माननीय सदस्य, अब आप अपना आसन ग्रहण करें, आपका समय हो गया । अब आप अपना आसन ग्रहण करें । माननीय सदस्य डॉ0 सत्येन्द्र यादव जी, एक मिनट आपके पास वक्त है, इसलिए गागर में सागर को भर दें ।

डॉ0 सत्येन्द्र यादव : सभापति महोदय, आज मुझे कटौती प्रस्ताव के पक्ष में बोलने का मौका मिला है । सरकार के आंकड़े और सत्ता पक्ष के दावे दोनों हवा में है । माननीय मंत्री का डंक और बिजली विभाग के करंट से पूरा बिहार के गांवों में हाहाकार मचा हुआ है । सब जगह कनेक्शन कट रहे हैं, लाखों के बिजली बिल जा रहे हैं। लेकिन जनता को राहत देने का कोई काम सरकार से नहीं हो रहा है । लोग दावे कर रहे हैं कि सरकार 2005 से या 2005 के बाद मैं सीधे-सीधे सवाल करना चाहता हूँ कि इस देश के अन्दर सिर्फ बिहार की सरकार नहीं है, इस देश के अन्दर केरल की सरकार है, इस देश के अन्दर बंगाल की सरकार है, इस देश के अन्दर झारखंड की सरकार है, वह सरकार बिहार की तुलना में बिजली कम रेट पर देती है और बिहार की सरकार अधिक रेट पर बिजली देती है । जिसके चलते कई लौह कम्पिनयां बिहार छोड़ने के लिए बाध्य हुई है । आज उद्योग-धंधे पर आफत है तो लोग दूसरी तरफ दावा करते हैं कि झोपड़ी में बिजली जाकर झोपड़ी वाले से पूछिए कि उनकी क्या हालात हैं ? सत्ता पक्ष के लोग हों या विपक्ष के लोग हों, रोज फोन आते हैं कि बिजली कनेक्शन कट गया, लाखों का बिजली बिल आ गया, आपकी हिम्मत नहीं है कि आप अधिकारी से कहिए कि बिजली बिल माफ करिए .....

टर्न–25/शंभु/09.03.21

सभापति(श्री नरेन्द्र नारायण यादव) : माननीय सदस्य, अब आप आसन ग्रहण करें, आपका समय हो गया है । माननीय सदस्य अब आप अपना भाषण समाप्त करें । माननीय सदस्य श्री सूर्यकांत पासवान जी, प्रारंभ करें, आपके पास 1 मिनट है ।

श्री सूर्यकांत पासवान : महोदय, पदाधिकारियों की लापरवाही के कारण प्रत्येक लाभुकों की समस्या को सुननेवाला कोई नहीं है बिहार के अंदर । महोदय, हमारे पक्ष के लोग दावा करते हैं कि बिजली की चमचमाती रौशनी में हमलोग चलते हैं । मैं स्वीकार करता हूँ, लेकिन पूरे बिहार के अंदर जितने भी कर्मचारी थे उनकी छंटनी हो गयी और आज प्राइवेट लोग बिजली के पोल पर चढ़ते हैं उनकी जान जाती है, लेकिन सरकार के पास उनको मुआवजा देने के लिए कहीं कोई नया कदम नहीं है । मैं मंत्री महोदय से मांग करता हूँ कि या तो कर्मचारी बहाल किया जाय या फिर जिन प्राइवेट लोगों की जान जाती है उनको मुआवजा दिया जाय । महोदय, आज खाद्य उपभोक्ता संरक्षण– महोदय, कोरोना काल में जो खाद्य दी गयी, लोगों को जो राशन मुहैय्या कराया गया माननीय मंत्री महोदय ने कहा कि हमारी सरकार ने मुफ्त में राशन देने का काम किया । मैं जानना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि इसकी जॉच हो ।

सभापति(श्री नरेन्द्र नारायण यादव) : आपका समय समाप्त हुआ, आप आसन ग्रहण करें । माननीय सदस्य श्री कान्त यादव जी, आपका समय 5 मिनट है ।

श्री सूर्यकान्त यादव : माननीय सभापति जी, मैं ऊर्जा विभाग के कटौती प्रस्ताव के पक्ष में बोलने के लिए खड़ा हूँ । महोदय, मैं बिजली विभाग के कुछ सदस्यों को आपके माध्यम से ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ । महोदय, ग्रामीण क्षेत्र में बिजली विभाग की दो बड़ी समस्या है । पहला विभाग द्वारा 11 हजार वोल्ट का तार एवं पोल घनी आबादी के बीच लगा दिया गया है । 11 हजार वोल्ट के तार जर्जर हैं और बार–बार उनके टूटने से गरीब जनता की जान चली जाती है । महोदय, तार उनके घर के दरवाजे के सामने से गुजरता है । कई बार तो ऐसे तार छत के उपर से लगा दिया जाता है जिससे भयानक दुर्घटना होती है । महोदय, मेरे क्षेत्र में ही ऐसे हादसे में कई जानें चली गयी । इसपर विभाग को ध्यान देना चाहिए और निदान निकालना चाहिए । महोदय, बिजली विभाग के कर्मियों द्वारा गरीब जनता के यहां मीटर यह कहकर लगाया गया कि इसका कोई शुल्क नहीं लगेगा, कंपनियों के कर्मचारी द्वारा इसके लिए उपभोक्ताओं से 5 सौ रूपये, 1 हजार रूपये तक की वसूली भी की जाती है । मीटर लगाने के बाद उपभोक्ताओं से मीटर, तार और अन्य शुल्क वसूले जा रहे हैं जो लगभग 5 हजार रूपया तक हो गया है । मैं सरकार से उपभोक्ताओं के मीटर, तार और उनके लगाने के खर्च को माफ करने

की मांग करता हूँ क्योंकि राज्य की गरीब जनता इस शुल्क को देने में समर्थ नहीं है । महोदय, तीसरी समस्या है रीडिंग और बिलिंग –सभी राज्य में फिक्स चार्ज और बिलिंग चार्ज दोनों लागू है, लेकिन बिलिंग फिक्स चार्ज से पांच गुणा ज्यादा आ रहा है जिसके कारण मेरे क्षेत्र सहित पूरे राज्य की जनता परेशान है । कंपनियों के द्वारा मीटर रीडिंग के बाद जो बिल दिया जा रहा है वह कभी कभी 5 हजार तक पहुंच जा रहा है । हमारी ग्रामीण क्षेत्र की 90 प्रतिशत जनता ए0सी0 और फ्रिज का उपयोग नहीं कर पाती है फिर भी इतना ज्यादा बिलिंग होना चिंता का विषय है, सरकार को इसपर ध्यान देना चाहिए । महोदय, हमारे जिले में अमौर के रसूलपुर में पावरग्रिड का निर्माण किया गया है जो तीन वर्ष पूर्व पूरा हुआ है । इसके निर्माण में मिट्टी भराई का कार्य और सुरक्षात्मक काम मानक और प्राक्कलन के अनुरूप नहीं किया गया है जिसके कारण वर्ष 2020 में इस पावरग्रिड में महीनों पानी जमा रहा और बिजली उपभोक्ताओं को नहीं मिला । महोदय, यह क्षेत्र हमेशा से बाढ़ प्रभावित रहा है, लेकिन प्राक्कलन बनाते समय इसका ध्यान नहीं रखा गया था जिसके कारण निर्माण के काम में गड़बड़ी हुई । यह जॉच का विषय है और सरकार को इसकी जॉच करानी चाहिए । महोदय, एकमा विधान सभा में किसान भाइयों के घर में चार–चार लाख बिजली बिल आया है इसकी जॉच होनी चाहिए । मैं सदन से अनुरोध करता हूँ । नमस्कार ।

सभापति(श्री नरेन्द्र नारायण यादव) : माननीय सदस्य श्री बीरेन्द्र कुमार जी, आपके पास 10 मिनट का वक्त है ।

श्री बीरेन्द्र कुमार : आदरणीय सभापति महोदय, समय देने के लिए आभार व्यक्त करते हुए– मैं आभार व्यक्त करता हूँ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जिसका मैं पूर्णकालिक कार्यकर्त्ता था और भारतीय जनता के सिंबल पर जीतकर आया हूँ । मैं आभार प्रकट करता हूँ रोसड़ा की जनता का जहां पर कबीर के सामाजिक न्याय का बहुत बड़ा केन्द्र है उदेनाचार्य जी जो न्याय शास्त्र के जनक थे उनका स्थान है । उस जनता के प्रति आभार व्यक्त करते हुए जो विपक्ष कटौती का प्रस्ताव लाया है उसके विरोध में मैं बोलता हूँ । भारतीय जनता पार्टी के कालजयी नेता वाजपेयी जी कहा करते थे कि हम बिजली इतनी उपलब्ध करा देंगे कि लोग शौक से मोमबत्तियां जलाया करेंगे वह दौर माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी के सात निश्चय के अवधि में आ गया है । आज घर–घर बिजली उपलब्ध है । गरीब लोग जब गेहूं पिसाने के लिए बगल के चक्की पर जाया करते थे तो उस दौर में उनसे 5 रूपये कि0 गेहूं पिसाने का कीमत लिया जाता था, लेकिन आज बिजली उपलब्ध रहने के कारण 1 रूपये गेहूं पिसाने का मौका मिल रहा है । आज बिजली इतनी उपलब्ध हो गयी है कि जो लोग पहले दिया सलाई खोजते थे वे लालटेन भी नहीं खोजते

हैं। आज बिजली इतनी उपलब्ध हो गयी है । आज किसानों के खेत में बिजली पहुंचाया जा रहा है, हमलोग भी किसान हैं खेती करते हैं, 1 एकड़ गेहूं उपजाने के लिए चार पटवन में डेढ़ सौ रूपये घंटे डीजल के माध्यम से पंपसेट को देने का काम करते थे, लेकिन आज 5 रूपये घंटा के हिसाब से अपने खेत का पटवन कर रहे हैं । आज बिजली के क्षेत्र में सरकार की जो उपलब्धि है और बिजली के कारण हर घर, हर व्यक्ति तक ऊर्जा पहुंच रही है, ऊर्जा के बारे में आज जो बाजार की स्थिति है, दुनिया एक बाजार है जिसमें हर व्यक्ति खरीददार है जिसके पॉकेट में दारोमदार है और वह दारोमदार नाई के माध्यम से हो, कुम्हार के माध्यम से हो, लकड़ी काटने वालों के माध्यम से हो हर व्यक्ति के जेब में पहुंच रहा है । सभापति महोदय, आज ऊर्जा अगर दो घंटे के लिये गुल हो जायेगी तो आइ0टी0 अंधेरे में गुल हो जायेगी, आइ0टी0 का सारा सपना बेकार हो जायेगा । आज बिजली हर व्यक्ति के जीवन का अंग बन गया है । आज हर चर्चा में बात आती है गरीबों की जो गरीबों के उत्थान का काम किया जा रहा है, लेकिन जीवन स्तर में जो बढ़ोत्तरी हुआ है उसमें हम आकलन कर सकते हैं कि दुनिया में गरीबी की कोई परिभाषा नहीं है, गरीबी की परिभाषा है तो वह पड़ोसी है श्रीमान् जी । हर व्यक्ति चाहता है कि हम अपने पड़ोसी से ऊंचा जीवन स्तर को उठायें और बिजली के कारण हर व्यक्ति का जीवन बेहतर बन रहा है ।

(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

आज बिजली के क्षेत्र में हो, ऊर्जा के क्षेत्र में रसोई तक जो गैस उपलब्ध कराया गया है- लोग घंटो-घंटो तक लकड़ी चुनने का काम करते थे लेकिन उनको उज्ज्वला योजना के माध्यम से हर व्यक्ति के जीवन में रसोई गैस पहुंच गया है, घंटो में वह अपना भोजन तैयार करने का काम करते हैं ।

क्रमशः

टर्न-26/ज्योति/09-03-2021

क्रमशः

श्री बीरेन्द्र कुमार : जिससे व्यक्ति का जीवन स्तर इतना ऊपर आ गया है । ऊर्जा के कारण हर व्यक्ति का जीवन स्तर इतना ऊपर उठ रहा है जिसके सामने हैजा, डायरिया, कौलरा स्वतः समाप्त हो रहा है । आज कोरोना आया, ऊर्जा इतना उपलब्ध था जो कोरोना जैसे अभिशाप को वरदान में बदल दिया और मेडिकल की दुनिया में जो पीक मौसम था, वह भी समाप्त हो गया और व्यक्ति स्वस्थ्य रहना प्रारम्भ कर दिए । आज ऊर्जा इतना उपलब्ध हो रहा है कि अपने पड़ोसी देश बंगला देश को निर्यात करेंगे कटिहार में इतना उर्जा के लिए प्लान्ट लगाया जा रहा है । आज हर व्यक्ति के जीवन का अंग बन गया है ऊर्जा । ऊर्जा को इतना बाजार

में उपलब्ध करा दिया जाय, बाजार में खुला छूट छोड़ दिया जाय ताकि हर व्यक्ति के पास ऊर्जा सुगमता से पहुंच जाय । आज कीमत मायने नहीं रखता है, मायने यह रख पाता है कि ऊर्जा किस रुप में उपलब्ध हो पा रहा है अध्यक्ष महोदय । ऊर्जा चाहे जिस क्षेत्र में हो, पानी के क्षेत्र में हो, जल ऊर्जा की बात हो, सोलर ऊर्जा की बात हो, सोलर के बारे में हर गांव में दो तीन किसान आज सोलर प्लान्ट के माध्यम से अपने खेत की सिंचाई कर रहे हैं और अपने अनाज को दुनिया के बाजार में बेच रहे हैं । हमलोग जिस क्षेत्र से आते हैं समस्तीपुर मसाला उद्योग का बहुत बड़ा क्षेत्र रहा है वहॉ पर एक मौसम में एक साथ 14 फसल उगाने का काम होता है और किसान खुशहाल रहते हैं और उसमें बिजली की बहुत बड़ी भूमिका है । आज बिजली इतनी उपलब्ध हो रही है कि फुड प्रौसेसिंग के माध्यम से किसान अपने अनाज को संरक्षित कर उचित समय पर उचित कीमत वसूल कर रहे हें जिसमें उर्जा की महती भूमिका है । आज समस्तीपुर में भी फुड प्रौसेसिंग प्लानट लगाया जा रहा है जिसमें बिजली की बहुत बड़ी महती भूमिका है । आज बिजली के कारण हम किसानों की आय 2023 तक जो आजादी के 73 वें वर्ष को पूरा करेंगे ।

अध्यक्ष : अब आप संक्षिप्त कर लीजिये ।

श्री बीरेन्द्र कुमार : किसान अपनी आय को दुगुना करेंगे इन्हीं बातों के साथ अपनी बात को समाप्त करते हैं । भारत माता की जय ।

श्री प्रहलाद यादव : अध्यक्ष महोदय...

अध्यक्ष : क्या हुआ आपको ?

श्री प्रहलाद यादव : जिला मुख्यालय में एक प्रौब्लेम हो रहा है कि जिला मुख्यालय में अगर विधान सभा नहीं आता है तो जिला मुख्यालय में पैसा विधायक फंड से नहीं दे सकते हैं । दूसरी बात है कि कोई भी पी.सी.सी. का कार्य जैसे छोटी छोटी पुलिया की जरुरत होती है तो उसका भी कोई प्रावधान नहीं है तो ये दोनों अहम बात है तो चूंकि जिला मुख्यालय है जिसका तो औटोमेटिक है तो कोई भी विधायक दे सकते हैं जिला मुख्यालय में लेकिन ऐसा प्रावधान नहीं है इसलिए मैं आपके माध्यम से मंत्री से आग्रह करुंगा ।..

अध्यक्ष : यह प्रश्न का समय नहीं है ।

श्री प्रहलाद यादव : जिला का सवाल है । एक जिला में तीन चार विधान सभा होता है मान लीजिये दो विधान सभा एक जिला मुख्यालय को टच करता है ।

अध्यक्ष : बैठ जाइये ।

श्री विजय शंकर दूबे : अध्यक्ष महोदय, बिजली पर समय वाद-विवाद परवान पर है और आप आसन पर विराजमारन है और उत्तर होगा सरकार का और मैं माननीय मंत्री जी

से एक निवेदन करना चाहता हूँ कि सदन और इस राज्य की जनता को जानने का अधिकार है कि वर्ष 2009 से लेकर 2014 तक माननीय मंत्री बिजेन्द्र यादव जी भारत सरकार में बिजली मंत्री जब शिंदे साहेब हुआ करते थे ।

अध्यक्ष : अब वो कहेंगे । अब सरकार का उत्तर होगा । माननीय मंत्री, निबंधन, मद्य निषेध एवं उत्पाद विभाग ।

श्री सुनील कुमार, मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, हम तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आपाने इस सदन में अपने विचारों को रखने का मौका दिया । हम खास कर माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का और भोरे की जनता को धन्यवाद देना चाहते हैं जिनके आशीर्वाद से हम सदन में आए हैं । हम अपने स्वर्गीय पिता जी को भी श्रद्धा सुमन अर्पित करना चाहेंगे जो इस सदन के सदस्य भी रहे और मंत्री भी रहे और मेम्बर औफ कंस्टीच्युएंट असेम्बली भी रहे। हम निबंधन विभाग के बारे में बताना चाहेंगे कि कोरोना काल के बावजूद भी हमारे निबंधन के विभाग के पदाधिकारियों ने काफी मेहनत की है और जो हमारा वित्तीय लक्ष्य था उसका 77 प्रतिशत यानी कि 3617 करोड़ का लक्ष्य प्राप्त कर लिया है वह काफी सराहनीय है और हम समझते हैं कि राजस्व संग्रह विकास के लिए बहुत जरुरी है इसलिए हमलोगों ने हर तरह की सुविधा दे रखी है । औन लाईन रजिस्ट्री के अलावे रविवार को भी कार्यालय खुले हैं और ऑन लाईन स्लौटिंग की सुविधा है और हम सदन को आश्वस्त करना चाहेंगे कि आने वाले वित्तीय वर्ष में पूरा विभाग पूरी मेहनत के साथ राजस्व के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कार्रवाई करेगा । जहाँ तक पूर्ण शराबबंदी नशाबंदी की बात है तो इसका उल्लेख डायरेक्टिव प्रिंसपुल में है । महात्मा गांधी जी ने अपने विचारों मे रखा था लेकिन पूर्व की जो शराबबंदी थी यहाँ और वर्तमान शराबबंदी है उसमें सबसे बड़ा फर्क माननीय नीतीश कुमार जी के पौलिटिकल विल का यह सबसे बड़ा फर्क है । उन्होंने महिला सशक्तिकरण और एक स्वास्थ्य परिवार की परिकल्पना की और इसी उद्देश्य से यहाँ शराबबंदी और नशाबंदी लागू की गयी और पूरे सदन में सर्व सम्मति से इसका समर्थन किया । करोड़ों लोगों ने मानव श्रृंखला में अपना साथ दिया । इस संबंध में बहुत सारे विचार और टिप्पणियाँ की गयी शराबबंदी के बारे में इस सदन में, मीडिया में कहा गया कि पैरेलल इकानॉमी है काला बाजारी है इसके अतिरिक्त मेरी बातों को सुन लें इसके अतिरिक्त राजस्व की हानि हुई । इन सभी बातों का जवाब हम जरुर देंगे । देखिये अंग्रेजों ने सैकड़ो साल पहले सी.आर.पी.सी. और आई.पी.सी. को इजाद किया लेकिन इसके बावजूद भी आपराधिक घटनाएं घटीं और आज भी घट रही है तो जब भी एक्ट लागू होता है तो ऐसा नहीं है कि समाज के सभी लोग

उसका पालन करते हैं । समाज में ऐसे लोग हैं जो उसका पालन नहीं करना चाहते हैं अपने व्यक्तिगत कारणों से फायदे के कारण से तो इस कानून का भी कुछ लोग उल्लंघन कर रहे हैं लेकिन गौर तलब बात यह है कि हमें यह देखना है कि एक्साईज विभाग और पुलिस डिपार्टमेंट के लोग क्या कर रहे हें तो मैं आपको आश्वस्त करना चाहूंगा कि पुलिस डिपार्टमेंट और एक्साईज डिपार्टमेंट बिल्कुल समन्वय के साथ काम कर रहा है और कुछ आंकड़ों को हम जरुर पेश करना चाहेंगे क्योंकि सम्पादकीय बात हम नहीं करना चाह रहे हैं । आप देखेंगे कि जहॉ तक गिरफ्तारियों का सवाल है तो हमलोगों ने दूसरे राज्यों में जाकर के खास कर पंजाब, हरियाणा, झारखंड से 5 हजार से अधिक गिरफ्तारियॉ की, 47 हजार से अधिक वाहन जप्त किए और ये वाहन हमेशा गरीबों के नहीं होते, इसमें अच्छे लोगों के भी वाहन थे इसके अलावे 15 हजार से अधिक वाहनों का हमलोगों ने कान्फिस्टिकेट किया । हमलोगों ने 53 लाख से ज्यादा देसी शराब और 97 लाख से ज्यादा विदेशी शराब को भी जप्त किया है और हमारे इरादे इस बात से स्पष्ट हैं कि हाल में जो पटना के बाई पास में जो शराब की बरामदगी हुई थी अब निर्णय लिया गया है कि उसी गोदाम और उसी जगह पर अब थाना खुलेगा तो हम अपनी ओर से सख्ती हर तरीके से कर रहे हैं और सरकार ने हर तरह का संसाधन मुहैया कराया है । जो बॉर्डर चेक पोस्ट हैं, इन्टीग्रेटेड वाहन की उपलब्धि, आई.जी. प्रोहीबीशन का पोस्ट इजाद किया है । जो सूचना तंत्र हैं, आज सूचना तंत्र हैं, उसे हम सुदृढ़ कर रहे हैं ।

क्रमशः

टर्न-27/पुलकित-अभिनीत/09.03.2021

..क्रमशः..

श्री सुनील कुमार, मंत्रीः महोदय, जो कॉल सेंटर हैं उसे और रेस्पोंसिव बना रहे हैं, ये तमाम कार्रवाइयां सरकार कर रही हैं । अभी कहा गया कि यह पुलिस के या प्रशासन के संरक्षण में हो रहा है तो मैं सदन को बताना चाहूंगा कि हमलोगों ने अपने विभागों में भी बहुत सख्त अनुशासनिक कार्रवाई की है । पुलिस विभाग में 186 पुलिसकर्मियों की बर्खास्तगी हुई है, उत्पाद विभाग में 8 बर्खास्तगियां हुई हैं और ऐसे सात एस0एच0ओ0 हैं जो दस वर्ष तक दोबारा थाना प्रभारी नहीं बन पायेंगे । मैं नहीं समझता ऐसा कोई विभाग होगा जिसने चार सालों में इतनी ज्यादा सख्त कार्रवाई की होगी तो सवाल ही नहीं पैदा होता है कि किसी तरह की अनुश्रवण में कमी रही है या हमलोगों ने जोरदार कार्रवाई नहीं की है । कुछ दिन पहले जैसा कि अखबारों में आपलोगों ने पढ़ा होगा कि गोपालगंज के बहुचर्चित कांड में निर्णय

आया, आजीवन कारावास हुए, फांसियां हुईं तो यह एक स्पष्ट संदेश है वैसे लोगों के लिए जो इस अवैध धंधे में जुड़े हुए हैं ।..

(व्यवधान)

मेरी बात सुनिए, पूरी बात सुनिए..

(व्यवधान)

अध्यक्ष: बैठिए, पूरी बात सुनिए । माननीय मंत्री बोल रहे हैं । बिना अनुमति के आपलोगों का प्रोसीडिंग में कुछ नहीं जायेगा । बैठ जाइये, आप सुन लीजिए । बहुत ही गंभीरता से मंत्री जी बोल रहे हैं और पहली बार बोल रहे हैं, सुन लीजिए ।

श्री सुनील कुमार, मंत्री: महोदय, यह स्पष्ट दिखलाता है कि कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। आपको मैंने बताया, सदन को मैंने बताया कि पांच हजार से ज्यादा गिरफ्तारियां दूसरे प्रदेशों में हुई हैं और जो भी साक्ष्य मिलेगा, हम उनकी गिरफ्तारियां सुनिश्चित करेंगे।

(व्यवधान)

अध्यक्ष: माननीय मंत्री, आप इधर देख कर बोलें, उधर मत देखिए ।

श्री सुनील कुमार, मंत्री: देखिए, अब तक आपलोगों ने रेवन्यू लॉस की बात कही, इस एक्ट को समझने की कोशिश कीजिए...

श्री महबूब आलम: अध्यक्ष महोदय..

अध्यक्ष: महबूब जी बैठ जाइये ।

श्री सुनील कुमार, मंत्री: इसका सामाजिक पहलू सबसे महत्वपूर्ण है । आधी आबादी हमारी महिलाएं हैं और यह निश्चित है कि महिलाओं में एक सुरक्षा की भावना उत्पन्न हुई है । मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आज कोई भी पटना के डाकबंगला चौराहे पर, आपके खगड़िया के चौराहे पर पी कर हंगामा नहीं कर सकता है । महिलाओं में सुरक्षा की भावना उत्पन्न हुई है, निश्चित रूप से महिला उत्पीड़न में कमी आई है, दहेज उत्पीड़न में कमी आयी है, घरेलू हिंसा में कमी आयी है, ये सभी आंकड़े बताते हैं, जबकि जनसंख्या में वृद्धि हुई है तब भी संख्याओं में कमी आयी है

अध्यक्ष: अब संक्षिप्त कर लीजिये ।

श्री सुनील कुमार, मंत्री: महोदय, एक्सीडेंट में भी कमी आयी है । डब्ल्यू0एच0ओ0 ने जो बताया है कि सुसाइड इत्यादि का कारण भी शराब है तो उसमें भी और यह कहा जाता है कि हॉस्पिटैलिटी सेक्टर, टूरिज्म में कमी आयी है लेकिन सच्चाई यह है कि, जो आंकड़े बताते हैं कि 2015 से 2019 तक 21 परसेंट से अधिक फॉरेन और डोमेस्टिक टूरिस्ट में ईजाफा हुआ है । निश्चित रूप से हमारी जो कार्य योजना है, हम बस संक्षिप्त में अपनी बात को..

(व्यवधान)

अध्यक्षः सुनिए, मंत्री जी आंकड़ा देख कर बोल रहे हैं ।

श्री सुनील कुमार, मंत्रीः हमारी कार्य योजना है, खास कर के जो माफिया हैं उनको साक्ष्य के आधार पर, हम कहीं भी रहें गिरफ्तार करेंगे । स्पीडी ट्रायल करेंगे और आने वाले दिनों में सुनिश्चित करेंगे कि उनकी प्रोपर्टी को कॉन्फिसकेट करके ऑक्शन करें । माननीय अध्यक्ष महोदय, अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि यह एक बहुत ही अनूठी पहल है, इस सदन ने पूर्व में साथ दिया है और मैं चाहूंगा कि आपके जो भी विचार या सुझाव हैं आप हमें दे सकते हैं, कोई सूचना हो वह भी दे सकते हैं। हम निश्चित रूप से कार्रवाई करेंगे और अंत में यही कहकर अपनी बातों को समाप्त करना चाहूंगा कि 'सच्चाई और निष्ठा की नाव डगमगा सकती है, हिचकोले खा सकते हैं लेकिन वह अपना सफर सफलता पूर्वक तय करेगी, अपने बलबूते पर। जय हिन्द ।

सरकार का उत्तर

अध्यक्षः माननीय मंत्री, ऊर्जा विभाग ।

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, मैं कुछ दूसरी बातों से शुरू करना चाहता था, अच्छा है, कटौती प्रस्ताव के जो एक्सपर्ट हैं, दूबे जी ने कुछ जिक्र किया । ये पुराने सदस्य हैं और 2004 में जब मैं इनके यहां गया था तो गोली चल रही थी लेकिन तब भी इनके घर के बगल में मैंने खाना खाया था । इनको मैं शुरू से, उस समय से जानता हूँ, उससे पहले नहीं जानता था । महोदय, वर्ष 2000 में झारखंड का बंटवारा हुआ । वर्ष 2000 में जब झारखंड का बंटवारा हुआ, उस समय स्वर्गीय वाजपेयी जी की सरकार थी और माननीय मुख्यमंत्री जी उस समय सरकार में थे, हमलोग विपक्ष में थे । सभी पार्टी के लोग आर0जे0डी0 के लोग भी एक डेडीकेशन बनाकर गये थे कि बिहार को विशेष पैकेज मिलना चाहिए चूंकि झारखंड बंटने के बाद, उस समय की जो आर्थिक स्थिति थी लगभग 900 करोड़ रूपये कोयले के रॉयल्टी से आता था, जो बिहार की आमदनी का मेजर आइटम था। मुझे स्मरण है, वाजपेयी जी ने मुस्कराते हुए कहा था कि बिहारीपन जगा है, मैं तो पहले से ही बिहारी हूँ और तीन हजार करोड़ रूपये का, मुझे याद है एस0सी0 झा कमीशन कमिटी बनाई गयी, प्लानिंग कमीशन में जो भागलपुर के ही थे, बड़े अर्थशास्त्री थे, विद्वान आदमी थे, उस कमिटी ने तीन चीजों को आइडेंटिफाई किया बिहार में कि इन तीनों में बड़ी कमी है । नंबर एक आइटम था कि यहां ट्रान्समिशन और डिस्ट्रीब्यूशन की बड़ी कमी है, बिजली बाहर से खरीद कर लाई जा सकती है लेकिन उसकी अति आवश्यकता है, उसके लिए एक हजार करोड़ रूपया, स्टेट हाईवे की दुर्दशा थी, उसके लिए एक हजार करोड़ रूपये दिया

और तीसरा आइटम था कि सोन नहर, गण्डक नहर, कोसी नहर स्वर्गीय श्री वाजपेयी जी के रिजम में ये बनीं, पचास के दशक में, उसकी क्षमता घट गई है, 40 परसेंट ही इरिगेशन कैपेसिटी है, उसको भी रिनॉवेट करने की जरूरत है । उस समय की सरकार थी, कहा कि बिजली का काम हम लोग नहीं करेंगे, सड़क का काम भी हमलोग नहीं करेंगे, सिंचाई विभाग ने कहा कि हां सिंचाई का काम करेंगे। बिजली का काम दूबे जी एन0एच0पी0सी0 पावर गृह दोनों, जो भारत सरकार का ऑर्गेनाइजेशन है, स्वर्गीय वाजपेयी जी की सरकार ने देने का काम किया कि भारत सरकार का ऑर्गेनाइजेशन काम करेगा, लेकिन सात जिलों को किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को नहीं दिया गया, जिसमें कटिहार एक, कोसी के तीनों जिले मिलाकर चार, समस्तीपुर- पांच, बेगूसराय-छः और आपका जिला अध्यक्ष महोदय, ये सात जिले किसी में नहीं आयें । काम प्रारंभ हुआ, क्योंकि आपने कहा कि मनमोहन सिंह की गर्वमेंट ने कितनी राशि दी ।...

(व्यवधान)

सुनिये तो, जब आप बोल रहे थे तब हम नहीं बोल रहे थे, इतनी तो मर्यादा रखिये, अब आप नये सदस्य तो नहीं हैं कि आपको बताया जाय । एक बात दूबे जी लोकतंत्र 'सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय' की अवधारणा पर नहीं है, अब 'बहुजन हिताय' की अवधारण पर है । कुछ लोग विरोध करेंगे इसमें मान्यताएं हैं, ये अपना काम करेंगे लेकिन सुनना चाहिए सबकी । महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जब हमलोगों की सरकार बनी तो सिंचाई क्षेत्र में एक-डेढ़ सौ करोड़ रूपये खर्च नहीं हो पाया बाकि भारत सरकार का एक ऑर्गेनाइजेशन का, जिसका मैं नाम भूल रहा हूँ उसमें स्टेट हाईवे का निर्माण कर दिया गया । एक रोज माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ बैठक हो रही थी तो मैंने कहा कि 31 मार्च, 2005 तक, क्योंकि नवम्बर तक हमको लगता है यह पैसा खर्च नहीं हो पायेगा तो पांच साल के लिए ये वापस हो जायेगा भारत सरकार को । हम तैयार हैं ऊर्जा विभाग ने प्रपोजल बना दिया है ।

(क्रमशः)

टर्न-28/हेमन्त-धिरेन्द्र/09.03.2021

...क्रमशः...

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : तो कुछ दिनों के बाद इन्होंने समीक्षा की, हमारे अफसर को बुलवाया कहा कि हां, तीन-चार महीने पहले माननीय मंत्री जी ने कहा था कि ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन का टोटल स्टीमेट बना लीजिए, हम लोग तैयार हैं । उसमें सारा पैसा माननीय मुख्यमंत्री जी ने देने का काम किया, फिर वह प्रारंभ हुआ ।

आगे चलकर दो हजार मेगावाट, जिसका माननीय सदस्य जिक्र कर रहे थे, 60-40, 60 परसेंट बिहार सरकार, 40 परसेंट भारत सरकार, जमीन, मशीन सब बिहार सरकार । मुजफ्फरपुर का भी एक्पेंशन, दो सौ मेगावाट का दो यूनिट, बरौनी का भी दिया गया, 250 का स्टेट गवर्नमेंट कि एन.टी.पी.सी. के नेतृत्व में, चूंकि वह टेक्निकली एक्सपर्ट टीम है उसके नियंत्रण में और दो हजार मेगावाट का बाढ़ में, जब माननीय मुख्यमंत्री जी रेल मंत्री थे, मुझे याद है कि जब चुनाव लड़ रहे थे, उसी समय शिलान्यास हुआ था ईस्वी मुझे याद नहीं है । अब लगता है कि शायद जैसे कल एन.टी.पी.सी. के लोग आये थे, उनसे मिले दो-तीन दिन पहले, उन्होंने कहा कि एक यूनिट हम लोग चालू कर पायेंगे 500 मेगावाट की । जब बिहार का बंटवारा हुआ था, तो 110 मेगावाट की यूनिट बरौनी और 110 मेगावाट की यूनिट मुजफ्फरपुर के हिस्से में मिली थी । मुजफ्फरपुर बंद, बरौनी का 40-50 मेगावाट कभी चलता, कभी पांच दिन बंद हो जाता, यहां से प्रारंभ हुआ । महोदय, आज तरह-तरह की बातें होती हैं । लगभग 6000 मेगावाट बिजली की हम लोग खरीददारी करते हैं । ये आंकड़े हैं और पता नहीं, कहते हैं कि इस गांव में नहीं हुआ है, आर0जे0डी0 के लोग बता रहे थे, पता नहीं बिजली गंगा में जा रही है, हम तो जांच करायेंगे कि कहीं नदी में बह तो नहीं जा रही है, क्योंकि इतना तो हो रहा है ।

(व्यवधान)

अब, इनके घर दरभंगा में एक मिनट भी बिजली नहीं कटती है, बड़ा विशाल घर है । अब, आज हम कहेंगे कि भाई, दिखवाइये जरा, क्या है कि ठीक है, उसका कटा हुआ है क्या ? तो अब ज्यादा मत बोलिये ।

(व्यवधान)

चुप रहिये । ठीक है ।

(व्यवधान)

हां, हां बड़ा भारी गरीब का । बैठिये, बैठिये ।

अध्यक्ष : बैठ जाइये, बैठ जाइये ।

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : महोदय, मैं इस हाउस में रिजर्व बैंक के गवर्नर को, भारत सरकार के मंत्री को और प्रधानमंत्री कार्यालय को बधाई दूंगा कि कोरोना काल में सारी चीजें ठप हो गईं, वित्तीय संकट पैदा हो गया, पूरी दुनिया में, केवल भारत में नहीं, राज्य में नहीं । साढ़े तीन हजार करोड़ का जो बिजली खरीदने का काम हुआ और चुनाव में, कोरोना काल में कहीं एक मिनट भी बिजली में अवरोध नहीं हुआ। यह मुख्यमंत्री जी के आदेश के अनुसार हुआ । महोदय, अब मैं रेट की बात का जिक्र करना चाहता हूं । यह तो कितना कहा जाय, हम लोग कुछ कहें, ये तो

असत्य कहेंगे कि यह असत्य है । लेकिन हम लोग तो कथनी में नहीं, करनी में विश्वास करते हैं । इसीलिए हम काम करते हैं और आम लोग उसको अहसास करते हैं, महसूस करते हैं । महोदय, दो-तीन नई बातें, एक तो कृषि कनेक्शन, हमेशा माननीय मुख्यमंत्री जी की इच्छा थी कि ढ़ाई-तीन हजार रुपये में लोग डीजल से खेती करते हैं, किसानों को बहुत पैसा लगता है और प्रदूषण भी फैलता है, तो इसको कराना चाहिए, तो कृषि कनेक्शन शुरू किया गया । महोदय, अभी तक तीन लाख तक कृषि कनेक्शन दिये जा चुके हैं, जिसमें सरकार अपना पूरा पैसा देकर सस्ती बिजली 65 पैसे प्रति यूनिट के हिसाब से 200-250 रुपये का बिल आता है । भारत सरकार ने भी उसको अडॉप्ट किया । उसकी डेट खत्म हो रही है 31 मार्च तक, इसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि नहीं, हम अपनी योजना चलायेंगे । तो मैं अगले वर्ष के लिए लगभग 1329.61 करोड़, दो कम्पनियों को टेंडर दे दिये गये हैं, कार्य आदेश भी निर्गत कर दिया गया है और 22 मार्च, 2022 तक हर इच्छुक व्यक्ति को मुख्यमंत्री कृषि विद्युत कनेक्शन देने का काम किया जायेगा । महोदय, इसके अलावा एक नई चीज, बहुत माननीय सदस्यों ने और मैं भी इसको स्वीकार करता हूँ, इंसान, इंसान है। कहावत है अपने हिन्दू माइथोलॉजी में और इस्लाम धर्म में भी कि शत प्रतिशत खुदा भी नहीं होते, भगवान भी नहीं होते, खाते हैं तो कुछ जूठा होता है, सब एक तरह के लोग नहीं होते हैं, कुछ गड़बड़ियां होंगी, कुछ चीजें होंगी, आपका और हमारा भी दायित्व है कि माननीय सदस्यों की जितनी भी शिकायते हैं, वह लिख कर भेज दें, हम निश्चित रूप से उसकी जांच करवायेंगे और कार्रवाई करेंगे लेकिन वर्षों से माननीय मुख्यमंत्री भी चिंतित थे कि बिजली बिल ज्यादा आता है । महोदय, अब एक बात कहूँगा कि मेरे कॉन्स्टीच्यूऐंसी का एक आदमी आया और कहा कि हमारा बिजली बिल बहुत आ गया है, हम गरीब आदमी हैं, एक ही बल्ब जलाते हैं । उसे बगैर कहे मैं शाम को उसके यहां चला गया, बगल में था । वहां 6 बल्ब, पानी को ठंडा करने वाला फ्रीज, हर रूम में पंखा था और जब मैं शाम को गया तो यहां कोई सोया हुआ नहीं है, बिजली क्यों जल रही है और पंखा क्यों चल रहा है, तो चुप हो गया । उसके बाद कभी नहीं बोला कि बिजली बिल ज्यादा है । मैंने कहा मीटर बैठा हुआ है तो यह एक अलग कहानी है, महोदय । लेकिन माननीय मुख्यमंत्री की चिंता थी कि गरीबों का अधिक बिल आ जाता है ।

मो0 नेहालउद्दीन : माननीय मंत्री जी, चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में क्या कहियेगा ?

(व्यवधान)

अध्यक्ष : सत्येन्द्र जी बैठ जाइये ।

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : बिजली का जो नियम और कानून है उसको आप जरा पूरी तरह पढ़िये । वैसे मत बोलिये, आप नये सदस्य हैं । महोदय, बिहार सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेशानुसार 2019 में ही स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने का निर्णय लिया था । अब, प्रीपेड मीटर का मतलब महोदय, जैसे मोबाइल में बिल भरवाइये और जब बिल पूरा हो जायेगा, वह ऑटोमेटिकली बंद हो जायेगा, वह इंट्रड्यूस किया गया । माननीय मुख्यमंत्री की इच्छा थी कि जल्दी इसको कर दिया जाय । मैं दूसरे कन्फ्यूजन में था, हमने कहा कि लग तो जायेगा परन्तु मेंटेनेंस कौन करेगा ? यह तो नई टेक्नोलॉजी है, विदेशों से कंपनी ने लाकर बनाया है । मुझे यह कहते हुए खुशी होगी कि स्वाभाविक है जब इरादा नेक हो तो रास्ते भी निकलते हैं, परिणाम भी आते हैं । स्मार्ट प्रीपेड मीटर ई0ई0एस0एल0 के द्वारा जो कंपनी का नाम है, फ्रांसीसी कंपनी ई0डी0एफ0 के माध्यम से लगाया जा रहा है । अगर यह 18 महीने में 2.5 लाख मीटर लगाने की योजना है, इसके बाद अगले 6 वर्षों तक यह कंपनी मेंटेनेंस भी करेगी । अब किसी को शिकायत नहीं रहेगी । महोदय, इसके अलावा प्रीपेड मीटर लगाने पर पहली बार उपभोक्ताओं को एक वेलकम मैसेज भेजा जायेगा, उपभोक्ता अपना रिचार्ज मोबाइल ऐप से या ऑनलाईन माध्यम से...

(व्यवधान)

अब गरीब लोग, लोक शिकायत अधिकार भी नहीं जायेंगे, भरेंगे कैसे ? तो आप भरवा दीजियेगा, जनप्रतिनिधि का क्या काम है ? बैठिये, बैठिये । माननीय सदस्य, लोग आपसे ज्यादा प्रीपेड मोबाइल चार्ज करने में मशगूल हैं, अब वैसी दुनिया नहीं है । आदि से पेटीएम माध्यम या बिजली कंपनी के काउंटर पर जाकर कर सकते हैं जो नहीं कर पायेंगे, बिजली कंपनी के काउंटर पर ।

...क्रमशः....

टर्न-29/सुरज-संगीता/09.03.2021

...क्रमशः...

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : पहले रिजार्च के लिए तीन दिन का समय दिया जाता है । उपभोक्ता को रिचार्ज करने के लिए एस0एम0एस के माध्यम से स्मरण कराया जाता है । बैलेंस शून्य होने पर भी एस0एम0एस0 दिया जाता है तथा कार्यदिवस को सुबह 10 बजे से 1 बजे तक ही बिजली काटी जाती है, रिचार्ज करने के बाद स्वतः ही 5 से 10 मिनट में स्वतः बिजली जुड़ जाती है । किसी असुविधा की स्थिति में हेल्पलाइन भी दिया गया है । उपभोक्ताओं के पुराने बकाया राशि के संबंध में व्यवस्था की गई है । बकाया राशि तीन सौ दिनों में बांटकर प्रतिदिन एक

हिस्से का समायोजन दिया जायेगा । उपभोक्ता अपने मोबाईल पर ऐप डाउनलोड कर प्रतिदिन की खपत की भी जानकारी ले सकते हैं और ऊर्जा की बचत के प्रति जागरूक भी हो सकते हैं । इसका फायदा महोदय यह होगा कि लोग मुस्तैद भी रहेंगे कि हम कम से कम खपत करें, लोग जब सो जाते हैं या रसोई घर में बिजली जलती रहती है तो उसे ऑफ कर दिया जायेगा, दुरूपयोग नहीं करेंगे क्योंकि पैसा खत्म हो जायेगा तो यह शिकायत भी दूर हो जायेगी साथ-साथ । अब इंसान पर जो आरोप लगता है मशीन पर तो आरोप संभव नहीं हो पायेगा इसलिए यह एक अच्छी चीज है और फ्रांस की कंपनी आकर लगा रही है ऐसा नहीं है इसलिए यह एक नई योजना माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेशानुसार यह हो रहा है। एक और चीज है...

(व्यवधान)

अध्यक्ष : आपलोग सुन लीजिये, सुनिये न । देखिये अनुभव की किताब लेकर बैठे हैं, हम सबको उनसे सीखना चाहिए और सुनना चाहिये ।

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : महोदय, माननीय सदस्यों ने आरोप लगाया कि बिहार में सबसे महंगी बिजली...

(व्यवधान)

श्री आलोक कुमार मेहता : इसके बारे में कहा जा रहा है कि पुराना जो मीटर था उसकी अपेक्षा यह ज्यादा चार्ज कर रहा है .....

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : ऐसी कोई बात नहीं है ये अफवाह है, ये बातें असत्य हैं । ये सब अफवाह है इन सब बातों पर मत जाइये । कोई नई चीज होती है तो यहां इसी तरह की अफवाह फैलती है । महोदय...

(व्यवधान)

कहा जा रहा था कि बिहार में बिजली का चार्जेज ज्यादा है । महोदय, मैं आंकड़े बता रहा हूं । वर्ष 2018-19 में 5070 करोड़ रुपया, कन्ज्यूमर का देखिये बिल, उस पर लिखा हुआ रहता है बिल इतना और सरकार का अनुदान इतना इसलिये पेमेंट इतना । वर्ष 2019-20 में 5193 करोड़ और वर्ष 2020-21 में 5469 करोड़ और वर्ष 2021-22 का प्रस्ताव महोदय आपके आदेशानुसार सदन पारित करेगा इसमें 6000 करोड़ रुपये का प्रस्ताव है कि अगल-बगल के राज्यों से सस्ती बिजली, माननीय मुख्यमंत्री जी की आकांक्षा है । एक बात और पिछले दिनों महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी प्रधानमंत्री जी के साथ नीति आयोग, जो अब प्लानिंग कमीशन नहीं है, नीति आयोग है उसमें अपनी बात रख रहे थे । उन्होंने ऊर्जा सेक्टर के लिए दो बातों का महत्वपूर्ण भारत सरकार के अफसरों ने भी कहा कि He is alone Chief Minister, जिन्होंने इस आईक्यू को रखा और किसी ने

नहीं उठाया । महोदय, एक तो यह बिहार हिमालयन बेसिन में है, यू0पी0 भी, नॉर्थ इस्टर्न रिजन में पानी की बहुतायत है । माननीय मुख्यमंत्री ने कहा कि हाइड्रो बेस को भी डेवलप करके और नॉन कन्वेंशन इनर्जी पर इम्फैसिस करना चाहिए इससे बाढ़ की क्वांटिटी भी घटेगी, क्वांटम भी घटेगा और वाटर पोटेंशियल का भी लेवल जो है, मेंटेन रहेगा । जो जल-जीवन-हरियाली का महत्वपूर्ण मुद्दा है ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : अब महबूब जी, आगे हो गये ।

(व्यवधान)

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : और दूसरी बातें, दूसरी बातें....

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष : शांति से, शांति से । मंत्री जी बोलते रहें ।

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : महोदय, बिजली क्षेत्र को महोदय...

(व्यवधान जारी)

महोदय, बिजली को पांच सेक्टर में बांटा गया है पूरे देश में । एक है महोदय...

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष : शांति, शांति । मंत्री जी आप बोलते रहें ।

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : बिहार में महोदय, सबसे पीछे बिजली का घर बना इसीलिए इस्टर्न एरिया में बिजली का चार्जेज जो बिहार सरकार खरीदती है, वह ज्यादा है ...

(व्यवधान जारी)

(इस अवसर पर विपक्ष के माननीय सदस्यगण द्वारा सदन से बहिर्गमन किया गया)

जहां महोदय, देश में औसत बिजली दर 3 रुपया 60 पैसे प्रति यूनिट है बिहार को 4 रुपये 12 पैसे खरीदना पड़ता है इसलिए 'वन नेशन वन टैरिफ' माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्माण करने का उन्होंने मांग किया और हाइडल का मैंने जिक्र किया इसलिए एक बात कहकर मैं अपनी बात खत्म करूंगा । महोदय, अभी भारत सरकार ने एक ऑब्लिगेटरी रिस्पांसिब्लिटी किया है कि इसमें सर्टेन परसेंट नॉन कन्वेंशनल एनर्जी लेना पड़ेगा नहीं तो पैसे लगते हैं, चार्जेज देने पड़ते हैं । अगर डगमरा हमारा बन जाता है तो प्रति वर्ष 375 करोड़ रुपये की बचत होगी हमारी इसीलिए इसको भी हमलोगों ने भारत सरकार से रिक्वेस्ट किया है इस परियोजना को करें । इन्हीं बातों के साथ मैं आपके प्रति आभार प्रकट करते हुए दूबे जी से मैं निवेदन करूंगा कि वे अपना कटौती प्रस्ताव वापस लें और सदन से दरख्वास्त करूंगा कि इस अनुदान मांगों को पास करने की कृपा करें ।

अध्यक्ष : क्या माननीय सदस्य, श्री विजय शंकर दूबे अपना कटौती प्रस्ताव वापस लेना चाहते हैं ?

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''इस शीर्षक की मांग 10/- रुपये से घटाई जाय ।''

यह प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ ।

अब मैं मूल प्रस्ताव को लेता हूं ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि:

''ऊर्जा विभाग के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए 85,59,99,72,000/-(पचासी अरब उनसठ करोड़ निन्यानवे लाख बहत्तर हजार) रुपये से अनधिक राशि प्रदान की जाय ।''

यह प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

मांग स्वीकृत हुई ।

माननीय सदस्यगण, आज दिनांक 09 मार्च, 2021 के लिए स्वीकृत निवेदनों की कुल संख्या-38 है । अगर सदन की सहमति हो तो इन्हें संबंधित विभाग को भेज दिया जाय ।

(सदन की सहमति हुई ।)

अब सभा की बैठक बुधवार, दिनांक-10 मार्च, 2021 के 11.00 बजे पूर्वाह्न तक के लिए स्थगित की जाती है ।

.....